



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38
No. 38

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 1987/ भाद्र 28, 1909
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1987/BHADRA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

कानूनी, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कानूनी और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

का. भा. 2466—केंद्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन
अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में
बिनिश्चित करती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा
किया जाना है, अर्थात्:—

(क) ऐसे अपराध, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962
का 52) की धारा 110 के अधीन दण्डनीय हैं;

(ख) खण्ड (क) में वर्णित अपराध और उन्हीं पद्यों से उत्पन्न
होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अन्तर्गत में किए गए किसी
अन्य अपराध के संबंध में या उनसे गण्यत प्रवृत्ति, वृद्धि
और पद्धति।

[संख्या 228/13/87-ए. वी. डी. II]

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G., & PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2466.—In exercise of the powers conferred by Sec-
tion 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946
(25 of 1946), the Central Government hereby specifies the

87/1035 GJ—1

following offences as the offences which are to be investigated
by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

(a) Offences punishable under section 110 of the Cus-
toms Act, 1962 (52 of 1962);

(b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to,
or in connection with the offences mentioned in
clause (a) and any other offences committed in the
course of the same transaction arising out of the
same facts.

[No. 228/13/87-AVD. II]

का. भा. 2467—केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(1474 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, श्री के. कुन्हीरामा मेनन और श्री के. जे. एन्तेनी,
अधिवक्ता, एर्नाकुलम को एर्नाकुलम के विचारण, अपील और पुनरीक्षण
न्यायालयों में श्री पी. के. नारायणन और तीन अन्य के विरुद्ध दिल्ली
विशेष पुलिस स्थापन नियमित मामला सं. 7/86-केरल के अभियोगन
का और उसमें उद्भूत होने वाली किसी अन्य कार्यवाहियों का संचालन
करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/14/87-ए. वी. डी. II]

जी. सीतारामन, अवर सचिव

S.O. 2467.—In exercise of the powers conferred by sub-
section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure,
1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints
Shri K. Kunhirama Menon and Shri K. J. Antony, Advocates,
Ernakulam, as Special Public Prosecutors for the purpose of
conducting the prosecution and also any other proceedings

(3087)

arising out of the Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 7/86-KER against Shri P. K. Narayanan and 3 others in trial, appellate and revisional Courts in Ernakulam.

[No. 225/14/87-AVD. II]
G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1987

(आयकर)

का. आ. 2468.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 10-9-1986 की अधिसूचना सं. 6903 (फा. सं. 398/20/86-आ.क.व.) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री आर. एस. गुप्ता को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री आर. एस. गुप्ता द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 7417/फा. सं. 398/2/87-आ. क. (व)]

बी. नागराजन, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th July, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 2468.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 6903 [F. No. 398/20/86-II(B)] dated 10-9-1986, the Central Government hereby authorises Shri R. S. Gupta, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri R. S. Gupta takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7417/F. No. 298/2/87-IT(B)]

B. NAGARAJAN, Director

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1987

अधिसूचना सं. 7425

(आयकर)

का. आ. 2469.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54ड की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ आवास तथा शहरी विकास निगम लि. (हुडको) द्वारा जारी किए गए "3-वर्षीय हुडको पूंजी अभिलाष ऋणपत्र" विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 207/7/86-आ. क. नि.-II]

New Delhi, the 15th July, 1987

(INCOME-TAX)

NOTIFICATION NO. 7425

S.O. 2469.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Explanation I to sub-section (1) of Section 54E of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Govern-

ment hereby specifies the "3-year HUDCO Capital Gains Debentures" issued by the Housing & Urban Development Corporation Ltd. for the purposes of the said clause.

[F. No. 207/7/86-IT. A-II]

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1987

(आयकर)

का. आ. 2470.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "तमिल इवंगेलिकल लूथर्न चर्च, तिरुचिरापल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7442/फा. सं. 197-क/22/82-आ. क. (नि.-I)]

New Delhi, the 29th July, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 2470.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Tamil Evangelical Lutheran Church, Tiruchirapalli" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1988-89.

[No. 7442/F. No. 197A/22/82-IT(AI)]

का. आ. 2471.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "सोसायटी ऑफ द डॉटर्स ऑफ मैरी, त्रिवेंद्रम" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7443/फा. सं. 197/200/83-आ. क. (नि.-I)]

रोशन सहाय, अवर सचिव

S.O. 2471.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of the Daughters of Mary, Trivandrum" for the purpose of the said clause for the assessment years 1983-84 to 1986-87.

[No. 7443/F. No. 197/200/83-IT(AI)]

ROSHAN SAHAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1987

(आयकर)

का. आ. 2472.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में, तथा भारत सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 30-10-1985 की अधिसूचना संख्या 6477 (फा. सं. 398/4/85 आ. क. (व) में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत श्री एन. एन. उब्रेती को श्री एम. आर. शर्मा के स्थान पर कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एन. एन. उब्रेती द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 7444/फा. सं. 398/17/87-आ. क. (व)]

बी. ई. अलकजेंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 30th July, 1987

INCOME-TAX

S.O. 2472.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in partial modification of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 6477/F. No. 398/4/

85-II(B), dated the 30th October, 1985, the Central Government hereby authorises, Shri N. N. Uppreti, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act, in place of Shri M. R. Sharma.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri N. N. Uppreti takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7444/F. No. 398/17/87-II(B)]
B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1987

(अधकर)

का. भा. 2473--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "एरुमिगु सुब्रमणियसामो तिरुक्कोल, तिरुपरानकुन्दम" को समस्त तमिलनाडु और केरल राज्य में विद्यमान सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करना है।

[सं. 7458/का. सं. 176/39/87-प्र. क. नि.-I]
रोशन साहय, अवसर सचिव

New Delhi, the 4th August, 1987
(INCOME-TAX)

S.O. 2473.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Arudmigu Subramania Swamy Tirukkoll, Tirupparankundram" to be a place of public worship of renown throughout the states of Tamil Nadu and Kerala for the purpose of the said Section.

[No. 7458/J. No. 176/39/87-II(A)]
ROSHAN SAHAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1987

आदेश

का. भा. 2474 :-भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से संश्लेषित किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/30/87-सी. गु.-VIII, तारीख 23-3-1987 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री संजीव निर्मलकुमार अग्रवाल, 471-6 मन्. महल फ्लैट नं. 16, फिगज स्किल, बम्बई-400019 को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने-ले-जाने अथवा छिपाने, बचाना रखने के अथवा तस्करी के माल का धंधा करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का. सं. 673/30/87-सी. गु.-VIII]

New Delhi, the 18th August, 1987

ORDER

S.O. 2474.-Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974)

issued order F. No. 673/30/87-Cus. VIII dated 23rd March, 1987 under the said sub-section directing that Shri Sanjeev Nirmal Kumar Agarwal, 471-6, Manu Mahal, Flat No. 16, Kings Circle, Bombay-400019 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/30/87-Cus. VIII]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1987

आदेश

का. भा. 2475--भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन विशेष रूप से संश्लेषित किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/25/87-सी. गु. VIII, तारीख 23-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि दबुध तमन गेथ इब्राहीम, मकबा. बिल्डिंग, फ्लैट नं. 5, 94 टेंमकर स्ट्रीट, बम्बई-8 और 33 पकमोदिया स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, बम्बई को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का. सं. 673/25/87-सी. गु.-VIII]

New Delhi, the 19th August, 1987
ORDER

S.O. 2475.-Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/25/87-Cus. VII, dated 23rd March, 1987 under the said sub-section directing that Shri Dawood Hassan Shaikh Ibrahim, Maqba Building, Flat No. 5, 94, Temkar Street, Bombay-8 also at 33, Pakmodia Street, 2nd Floor, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself, so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/25/87-Cus. VIII]

आदेश

का. भा. 2476--भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से संश्लेषित किया गया

है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/27/87-सी. भू. viii तारीख 23-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि पारेश चन्द्र कुमार चौक्सी, नवयुग निकेतन, फ्लैट नं. 5, तीन बत्ती, मालाबार हिल, बम्बई को बम्बई केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि तस्करी के माल को लाने ले जाने अथवा छिपाने अथवा रखने के अलावा तस्करी के माल का धंधा करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हों।

[फा. सं. 673/27/87-सी-भू. VIII]

ORDER

S.O. 2476.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order P. No. 673/27/87-Cus. VIII dated 23rd March, 1987 under the said sub-section directing that Shri Paresh Chandrakumar Chokshi, Navyug, Niketan, Flat No. 5, Teen Batti, Malabar Hill, Bombay be detained and kept in custody in the Bombay Central Prison, Bombay with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 673/27/87-Cus. VIII]

आदेश

का. भा. 2477.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/29/87-सी. भू.-viii, तारीख 23-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री निर्मल कुमार मोती लाल अग्रवाल, 471-6, मानू महल, फ्लैट नं. 16, किंगम सर्किल, बम्बई 400019 को बम्बई केन्द्रीय कारागार, बम्बई, में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को ढोहने, अथवा छिपाने, अथवा रखने के अलावा तस्करी के माल का धंधा करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हों।

[फा. सं. 673/29/87 सी. भू.-VIII]

ORDER

S.O. 2477.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order P. No. 673/29/87-Cus. VIII dated 23rd March, 1987 under the said sub-section directing that Shri Nirmal Kumar Motilal Agarwal, 471-6, Manu Mahal, Flat No. 16, King's Circle, Bombay-400019 be detained and kept in custody in the Bombay Central Prison, Bombay with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 673/29/87-Cus. VIII]

आदेश

का. भा. 2478.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/33/87 सी. भू. viii, तारीख 23-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री किरत कुमार बाबुल शाह, धांजीबाई कुरान्जीबाई चव्हाण कमरा नं. 1 कबाड़ी रोड, मलाड (पूर्वी), बम्बई-68 को केन्द्रीय कारागार बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने ले जाने अथवा छिपाने अथवा रखने के अलावा तस्करी के माल का धंधा करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हों।

[फा. सं. 673/33/87-सी. भू. VIII]

ORDER

S.O. 2478.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/33/87-Cus. VIII dated 23-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Kiritkumar Babulal Shah, Dhanjibhai Karsanji Chawl, Room No. 1, Kawadi Road, Malad (East), Bombay-68 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 673/33/87-Cus. VIII]

आदेश

का. प्रा. 2479.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/44/87—सी. गु.-VIII, तारीख 20-3-1987 यह निर्देश देते हुए जारी किया था कि श्री एम. अमीन, पुन्न, मोहिदीन बाबा, निवासी 1/53, मेला स्ट्रीट, नान्दुयलार्ड, रामनाड, को केन्द्रीय कारागार, मदुरै में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[का. सं. 673/44/87—सी. गु.-VIII]

ORDER

S.O. 2479.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/44/87-Cus. VIII dated 20-3-1987 under the said sub-section directing that Shri M. Ameen, s/o. Mohideen Bava, r/o. 1/53, Mela Street, Nambuthalai, Ramnand be detained and kept in custody in the Central Prison, Madurai with a view to preventing him from smuggling goods, and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/44/87-Cus. VIII]

आदेश

का. प्रा. 2480.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/45/87—सी. गु.-VIII, तारीख 20-3-1987 यह निर्देश देते हुए जारी किया था कि श्री ए. सुहम्मद खली, पुन्न अब्दुल करीम, निवासी मच्चूर, वल्लुथल, रामनाड, तमिलनाडु को केन्द्रीय कारागार, मदुरै में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके, और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[का. सं. 673/45/87—सी. गु.-VIII]

ORDER

S.O. 2480.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/45/87-Cus. VIII dated 20-3-1987 under the said sub-section directing that Shri A. Mohamed Ali, S/o. Abdul Karcam, r/o. Machoor, Vattanam, Ramnad, Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Madurai with a view to preventing him from smuggling goods, and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/45/87-Cus. VIII]

आदेश

का. प्रा. 2481.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/47/87—सी. गु.-8, तारीख 20-3-87 यह निर्देश देते हुए जारी किया था कि श्री पी. लक्ष्मी-कान्थन, पुन्न पालानी, निवासी नेहरू नगर काजमलार्ड, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु को केन्द्रीय कारागार तिरुचिरापल्ली में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[का. सं. 673/47/87—सी. गु.-VIII]

ORDER

S.O. 2481.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/47/87-Cus. VIII dated 20-3-87 under the said subsection directing that Shri P. Lakshmi Kanthan, s/o. Palani, r/o. Nehru Nagar, Kajamalai, Tiruchirappalli, Tamilnadu, be detained and kept in custody in the Central Prison, Tiruchirappalli with a view to preventing him from smuggling goods, and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/47/87-Cus. VIII]

आदेश

का. प्रा. 2482.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया

गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/51/87-सी.गु.-VIII, तारीख 20-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री ए. मलवान पुत्र अम्मायाप्पन, नं. 59-बी, धनपथी, विजुप्रावादी पोस्ट, नगपत्तनम तालुक, तनजौर जिला, तमिलनाडु को केन्द्रीय कारागार त्रिचुरापल्ली में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे तस्करी के माल को लाने से रोका जा सके, अथवा छिपाने, अथवा रखने के अथवा तस्करी के माल का धन्य करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हजरि हों।

[फा.सं. 673/51/87-सी.गु.-1/VIII]

ORDER

S.O. 2482.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/51/87-Cus. VIII dated 20-3-87 under the said sub-section directing that Shri A. Selvan, S/o Ammaiappan, No. 59-B, Thenpathi, Vilunthavadi Post, Nagapattinam Taluk, Tanjore Distt. Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Tiruchirapalli with a view to preventing him from smuggling goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/51/87-Cus. VIII]

आदेश

फा.आ. 2483.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/52/87-सी.गु.-8 तारीख 20-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री सी. गोविन्द सामी पुत्र एम. विवाम्बरम, निवासी डाकघर विन्नुन्धमवाडी, तानुक नागपत्तनम, जिला तनजौर, तमिलनाडु को केन्द्रीय कारागार त्रिचुरापल्ली में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे तस्करी के माल को लाने-ले जाने अथवा छिपाने अथवा रखने के अथवा तस्करी के माल का धन्य करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हजरि हों।

[फा.सं. 673/52/87-सी.गु.-VIII]

ORDER

S.O. 2483.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/52/87-Cus. VIII dated 20-3-1987 under the said sub-section directing that Shri C. Govindasamy S/o Chidambaram r/o Vilunthamavadi Post, Nagapattinam Taluk, Tanjore Distt. Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Tiruchirapalli with a view to preventing him from smuggling goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/52/87-Cus. VIII]

आदेश

फा.आ. 2484.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/50/87-सी.गु.-8, तारीख 20-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री इस्माइल पुत्र नैना मोहम्मद, निवासी 6/75, वेस्ट स्ट्रीट नम्बुथलई, रामनाड जिला तमिलनाडु को केन्द्रीय कारागार मद्रुरै में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे माल को तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हजरि हों।

[फा.सं. 673/50/87-सी.गु.-VIII]

ORDER

S.O. 2484.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/50/87-Cus. VIII dated 20-3-1987 under the said sub-section directing that Shri N. Ismail, S/o. Naina Mohamed, r/o 6/75, West Street, Nambuthalai, Ramnad District, Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Madurai with a view to preventing him from smuggling goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/50/87-Cus. VIII]

आदेश

फा. आ. 2485.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त

किया गया है, उक्त जाशान के अधीन आदेश का. सं. 673/55/87-सी. शु.-VIII, तारीख 20-3-87 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री सी. मृत्तुकृष्णन उर्फ मृत्तु पुत्र चिन्ताम्बरम, नाथ स्ट्रीट, वाडापथी, विलुन्थमवादी, नागपत्तनम, तन्जौर, जिला तमिलनाडु को केन्द्रीय कारागार तिरुचिरापल्ली में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने के लिए उत्प्रेरित करने में सक्षम न हो सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त मद्रास के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/55/87-सी. शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2485.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/55/87-Cus. VIII dated 20-3-87 under the said sub-section directing that Shri C. Muthukrishnan @Muthu S/o Chidambareem, North Street, Vadapathi, Vilunthamavadi, Nagapattinam, Tanjore Distr. Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Tiruchirapalli with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/55/87-Cus. VIII]

आदेश

का. प्रा. 2486 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/55/87-सी. शु.-VIII, तारीख 20-3-1987 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री सी. मृत्तुकृष्णन उर्फ मृत्तु पुत्र चिन्ताम्बरम, नाथ स्ट्रीट, वाडापथी, विलुन्थमवादी, नागपत्तनम, तन्जौर, जिला तमिलनाडु को केन्द्रीय कारागार, तिरुचिरापल्ली में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने में सक्षम न हो सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/55/87-सी. शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2486.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/55/87-Cus. VIII dated 20-3-1987

under the said sub-section directing that Shri V. Thayanathan @Thaya, C/o Vinayaga Moorthy, r/o Beach Road, Madagal, Sri Lanka (No. 7, Melamadavilagan Vedoranyam Thanjavur Distt.) be detained and kept in custody in the Central Prison, Tiruchirapalli with a view to preventing him from smuggling goods; and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/58/87-Cus. VIII]

आदेश

का. प्रा. 2487 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/58/85-सी. शु.-VIII तारीख 24-3-87 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद हसन मोजावला उर्फ मामोन, रूम नं. 42, बिल्डिंग नं. 138 चौथी मंजिल, कार्नाक रोड, बारा मंशन, 7-9 पिनजरी स्ट्रीट, बम्बई-3 को बम्बई केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने में सक्षम न हो सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/85/87-सी. शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2487.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/85/87-Cus. VIII dated 24-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Mohammed Hasan Mojwala @ Mamon, Room No. 42, Bldg. No. 138, 4th Flr., Carnac Road, Bawa Mension 7-9, Pinjari Street, Bombay-3 be detained and kept in custody in the Bombay Central Prison, Bombay with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/85/87-Cus. VIII]

आदेश

का. प्रा. 2488 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/93/87-सी. शु.-VIII, तारीख 24-3-87 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद शकील, 5, वर्गम हाऊस, 167 केवलेमी रोड, बंगलूर-5.

को केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे मान की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है कि उसे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बंगलूर के समक्ष हजरि हो।

[फा. सं. 673/93/87-सी. शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2488.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/93/87-Cus. VIII dated 24-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Mohamed Shakeel, 5, Vergeese House, 167, Cavalary Road, Bangalore-5 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bangalore within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/93/87-Cus. VIII]

आदेश

का. आ. 2489.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/105/87-सी. शु.- VIII, तारीख 25-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री एम. इब्राहिम उर्फ अहमद सैत पुत्र श्री मोहम्मद मोरान, (1) सं. 18, (पुलाना नं. 32) वार्लेयुधम स्ट्रीट मद्रास-1(2), 105 सिन्नाकदाई स्ट्रीट कलाकराई, रामनाड को केन्द्रीय कारागार मद्रास में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे मान की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त मद्रास के समक्ष हजरि हो।

[फा. सं. 673/105/87-सी. शु.- VIII]

ORDER

S.O. 2489.—Whereas the Joint Secretary, to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/105/87-Cus. VIII dated 25-3-1987 under the said sub-section directing that Shri M. Ibrahim Ahmed Sait S/o Shri Mohamed Meeran, (1) No. 18 (old No. 32), Velayudham Street, Madras-1. (2). 105, Sinnakadai Street Keelakkurai, Ramnad. be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from smuggling goods; and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/105/87-Cus. VIII]

आदेश

का. आ. 2490.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/107/87-सी. शु.- VIII, तारीख 25-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री नजीरखान पुत्र स्वर्गीय श्री अली, 19 बालुमुथु स्ट्रीट, एल्लिस रोड, माउंट रोड, मद्रास को केन्द्रीय कारागार मद्रास में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे मान की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हजरि हो।

[फा. सं. 673/107/87-सी. शु.- VIII]

ORDER

S.O. 2490.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/107/87-Cus. VIII dated 25-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Nazeer Khan S/o Late Shri Ali, 19, Balumuthu Street, Ellis Road, Mount Road, Madras be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from smuggling goods and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/107/87-Cus. VIII]

आदेश

का. आ. 2491.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/108/87-सी. शु.-VIII तारीख 25-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री एम. मधु पुत्र श्री सुमुभरन 273 कुप्पाडोमेडु, स्वम किलरुस बोर्ड, आर. के. नगर, मंडावेल्ली, मद्रास-28 को केन्द्रीय कारागार मद्रास में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे मान की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 का उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/108/87-सी. शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2491.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/108/87-Cus. VIII dated 25-3-1987 under the said sub-section directing that Shri S. Muthu, S/o Shri Sugumaran, 273, Kuppalmadu, Slum Clearance Board, R. K. Nagar, Mandaveli, Madras-28 be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from smuggling goods and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/108/87-Cus. VIII]

आदेश

फा. प्रा. 2492.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/128/87-सी. शु.-VIII तारीख 25-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री ए० एम० युनुस, पुत्र श्री अम्मान सलाम, (1) 1बी, अमन कोल स्ट्रीट, वाडापालानी, मद्रास (2) मरक्काबाई गांव, मन्नारगुडी तालुक तनजौर जिला, को तस्करी जेल, मद्रास में निरुद्ध कर जिरा जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके, और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/128/87-सी. शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2492.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/128/87-Cus. VIII dated 25-3-1987 under the said sub-section directing that Shri A. M. Younoos, S/o Shri Abdul Salam, (1) 1B Amman Koil Street, Vada-palani, Madras, (2) Marakkabai Village, Mannargudi Taluk, Tanjore District be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from smuggling goods, and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/128/87-Cus. VIII]

आदेश

फा. प्रा. 2493.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे 87/1035 GI—2.

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/121/87-सी. शु.-VIII तारीख 25-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री बाबा बाहदुरीन फातिसो स्वयंभू मादमर हुसैन पुत्र अम्मुन रहमन 6/94- ईस्ट स्ट्रीट, नान्बुथलै, थिरुवदानी (मद्रास) रामनाद को सेटुल जेल, मद्रास में निरुद्ध कर जिरा जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके; और

केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/121/87-सी. शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2493.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/121/87-Cus. VIII dated 25-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Bawa Baharudeen Falsely styled as Mohamed Hussain, S/o Abdul Rahim, 6/94, West Street, Nambuthalai, Thiruvadanai (Via), Ramnad, be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from smuggling goods, and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/121/87-Cus. VIII]

आदेश

फा. प्रा. 2494.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/133/87-सी. शु.-VIII तारीख 25-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री. आर. सुब्बालिंगम पुत्र श्री रघोनाथामो, 39 कैन्स बैक कालोनी श्रीनिवास नगर, बयलूर रोड त्रिची-8 को केन्द्रीय कारागार मद्रास में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से उत्प्रेरित करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर महानिरीक्षक पुलिस, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/133/87-सी. शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2494.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974)

issued order F. No. 673/133/87-Cus. VIII dated 25-3-1987 under the said sub-section directing that Shri R. Sundaralingam S/o Rathinasamy, 39, Canara Bank Colony, Srinivasa Nagar, Vayalur Road, Trichy-8 be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, Madras, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/133/87-Cus. VIII]

आदेश

का.पा. 2495—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/141/87-सी.गु.-8, तारीख 25-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री युसुफ पुत्र खाजा मोहम्मद, 88, पी.वी. कोल स्ट्रीट मद्रास-13 को सेंट्रल जेल, मद्रास में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके, और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अथ केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त मद्रास के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/141/87-सी.गु.-VIII]

ORDER

S.O. 2495.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/141/87-Cus. VIII dated 25-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Yousuff, S/o Shri Khaja Mohidden, 88, P. V. Koil Street, Madras-13 be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from smuggling goods, and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/141/87-Cus. VIII]

आदेश

का.पा. 2496—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/142/87-सी.गु.-8, तारीख 25-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री इस्माइल सुपुत्र श्री भती मोहम्मद, 98-ए, इस्माइल साहब स्ट्रीट, पाल्लाबरम, मद्रास, को केन्द्रीय जेल मद्रास में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अथ केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/142/87-सी.गु.-VIII]

ORDER

S.O. 2496.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/142/87-Cus. VIII dated 25-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Ismail S/o Shri Gani Mohamed, 98-A, Ismail Sahib Street, Pollavaram, Madras be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from smuggling goods, and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/142/87-Cus. VIII]

आदेश

का.पा. 2497—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/156/87-सी.गु.-8, तारीख 23-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अब्दुल मजीद अली मोहम्मद उर्फ बेल्हन, चौथी फ्लोर, मसजिद ट्रस्ट बिल्डिंग, 307, अब्दुल रहमान स्ट्रीट बम्बई-3 को बम्बई केन्द्रीय कारागार, बम्बई, में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने ले जाने का धन्धा करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अथ केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/156/87-सी.गु.-VIII]

ORDER

S.O. 2497.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/156/87-Cus. VIII dated 23-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Abdul Majeed Ali Mohamed Weldons, 4th Floor, Masjid Trust Building, 307, Abdul Rehman Street, Bombay-3 be detained and be detained and kept in custody in the Bombay Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay, within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/156/87-Cus. VIII]

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1987

का.आ. 2498.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/90/87-सी.शु.3, तारीख 24-3-87 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री कयम नवदी पुत्र अजीज नवदी, गांधी वयेंगन, बखतारन, ईरान को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/90/87-सी.शु.-VIII]

ORDER

New Delhi, the 21st August, 1987

S.O. 2498.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/90/87-Cus. VIII, dated 24-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Karyam Navidy Sjo Azceez Navidy, Village Bayengan, Bakhturan, Iran be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/90/87-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 2499.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/100/87-सी.शु.-VIII तारीख 19 जून, 1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री सैयद मोहम्मद सैयद फारूक, निवासी रूम नं. 13 तथा 14, दूसरी मंजिल, 38/38-ए, सैमुल स्ट्रीट, बम्बई-9 को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया गए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी प्रकार के कार्य को करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो, और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/100/87-सी.शु.-VIII]

S.O. 2499.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/100/87-Cus. VIII dated 19th June, 1987 under the said sub-section directing that Shri Sayed Mohamed Sayed Farooq, R. No. 13 & 14, 2nd Floor, 38/38A, Samuel Street, Bombay-9 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/100/87-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 2500.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/76/87-सी.शु.-8 तारीख 23-3-1987 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री हुनीफ अहमद यूसुफ अहमद खान, निवासी कमरा नं. 15, 293 नाग देवी स्ट्रीट बम्बई-400003 को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी प्रकार के काम को करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/76/87-सी.शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2500.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/76/87-Cus. VIII dated 23-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Hanif Ahmed Yusuf Ahmed Khan, R/o Rooms No. 15, 293, Nagdevi Street, Bombay-400003 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/76/87-Cus. VIII]

आदेश

का.प्रा. 2501.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/83/87-सी.शु.-8, तारीख 24-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मन मोहन सिंह 174-ख, शोख सराय, फेज 1 नई दिल्ली-110017 को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने के लिए उत्प्रेरित करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, नई दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/83/87-सी.शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2501.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 to 1974) issued order F. No. 673/83/87-Cus. VIII, dated 24-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Man Mohan Singh, 174-B, Seikh Sarai, Phase-I, New Delhi-110017 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/83/87-Cus. VIII]

आदेश

का.प्रा. 2502.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/88/87-सी.शु.-8 तारीख 24-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री नितिन बाजरांग यादव प्लेट नं. 13, दूसरी मंजिल बम्बुपव सोसाइटी, वैभव विलिंग, असाफा गांव घाटकोपर बम्बई-400084 को बम्बई केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने के लिए उत्प्रेरित करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/88/87-सी.शु.-VIII]

ORDER

S.O. 2502.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 to 1974) issued order F. No. 673/88/87-Cus. VIII dated 24-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Nitin Bajrang Jadhav, Flat No. 13, 2nd Floor, Badhubhav Society, Vaibhav Building, Asalfa Village Gha'koper, Bombay-400084 be detained and kept in custody in the Bombay Central Prison, Bombay with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods and;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/88/87-Cus. VIII]

आदेश

का.प्रा.—2503 भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/89/87-सी.शु.-8, तारीख 24-3-1987 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्रीमती मीना मानिकराम पेशवानी बैरक नं. 378/भार. 70 टी-सेक्शन उल्हास नगर, जिला ठाणे (महाराष्ट्र राज्य) को केन्द्रीय कारागार बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/88/87-सी.शु.-VIII].]

ORDER

S.O. 2503.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 to 1974) issued order F. No. 673/89/87-Cus. VIII dated 24-3-1987 under the said sub-section directing that Mrs. Meena Manikram Peswani, Barrack No. 378/R/70, T-Section, Ulhasnagar, Dist. Thane (Maha. State) be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods and;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/89/87-Cus. VIII]

आदेश

का.प्र. 2504—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/96/87-सी.पु.-8 तारीख 24-3-1987 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद असलम गुलाम मोहम्मद, 119, कल्याण मैनशन, तीसरी, मजिल, कमरा नं. 7 एस.वी.पी. रोड, बम्बई-9 का केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल को तस्करी करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/96/87-सी.पु.-VIII]

ORDER

S.O. 2504.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/96/87-Cus. VIII dated 24-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Mohamed Aslam Gulam Mohamed, 119, Kalyan Mansion, IIIrd Floor, R. No. 7 S.V.P. Road, Bombay-9 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods and;

2. Whereas, the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/96/87-Cus. VIII]

आदेश

का.प्र. 2505—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/158/87-सी.पु.-8, तारीख 23-3-1987 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री नादिरशाह अर. अमराग हसनाबाद, डा. मासकारणहास रोड, मल्लगांव, बम्बई-400010 को नासिक केन्द्रीय कारागार, नासिक में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को कोहने, अथवा छिपाने अथवा रखने के द्वारा तस्करी के माल का घन्टा करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/158/87-सी.पु.-VIII]

ORDER

S.O. 2505.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/158/87-Cus. VIII dated 23-3-1987 under the said sub-section directing that Mr. Nadirshah R. Chunara, 8, Hasanabad Dr. Mascarenhas Road, Mazgaon, Bombay-400010 be detained and kept in custody in the Nasik Central Prison, Nasik with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods; and

2. Whereas, the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/158/87-Cus. VIII]

आदेश

का.प्र. 2506—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/187/87-सी.पु.-8, तारीख 2 जुलाई, 87 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री सावर मल मोदी, 10 ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता-7 को प्रेजिडेंसी जेल कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को कोहने और तस्करी के माल को छिपाने तथा रखने के धंधे के द्वारा तस्करी के माल का व्यापार करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/187/87-सी.पु.-VIII]

ORDER

S.O. 2506.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/187/87-Cus. VIII dated 2nd July, 1987 under the said sub-section directing that Shri Sanwar-mal Modi, 10, Tarachand Dutta Street, Calcutta-7 be detained and kept in custody in the presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in concealing and keeping smuggled goods; and

2. Whereas, the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/187/87-Cus. VIII]

आदेश

का.भा. 2507.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी भुमा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/95/87-सी.शु.-8 तारीख 24-3-1987 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री नुरपा कृष्ण लामा, बुद्ध विहार सेकी गोपा, नई दिल्ली को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे सरकार के मान को लाने से जाने का धन्धा करने से रोक जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः, अथ, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह निदेश देता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हजरि हो।

[का.सं. 673/95/87-सी.शु.-VIII]

एस. के. चौधरी,

अवर सचिव

ORDER

S.O. 2507.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/95/87-Cus. VIII dated 24-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Nurpa Krishna Lama, Bhudha Vihar, Sackay Gompa, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and;

2. Whereas, the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/95/87-Cus. VIII]

S. K. CHOWDHRY, Under Secy.

(भय विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1987

का. भा. 2508.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अनुसरण में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 5 के उपबन्ध में क्रम सं. 14 के सामने स्तम्भ 3 के अधीन की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“पूरी शक्तियाँ, जहाँ मुद्रण कार्य निदेशक, मुद्रण के माध्यम से या उसके अनुमोदित से निष्पादित किया जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकाशन प्रभाग और विज्ञापन और बुध्द प्रचार के मामले को छोड़कर जहाँ इन दो संगठनों के निदेशकों को या तो मुद्रण

कार्य प्राईवेट मुद्रणालयों को आर्मांडा करने के लिए मुद्रण निदेशालय के निदेशक की शक्तियाँ होंगी।”

टिप्पण: वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978, अधिसूचना सं. का. भा. 2131, तारीख 22 जुलाई, 1978 द्वारा प्रशोधित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

- (1) अधिसूचना सं. का. भा. 1887, तारीख 9-6-79
- (2) अधिसूचना सं. का. भा. 2942 तारीख 1-9-79
- (3) अधिसूचना सं. का. भा. 2611 तारीख 4-10-80
- (4) अधिसूचना सं. का. भा. 2164, तारीख 15-8-1981
- (5) अधिसूचना सं. का. भा. 2304, तारीख 5-9-81
- (6) अधिसूचना सं. का. भा. 3073, तारीख 4-9-82
- (7) अधिसूचना सं. का. भा. 4171, तारीख 11-12-82
- (8) अधिसूचना सं. का. भा. 1312, तारीख 26-2-83
- (9) अधिसूचना सं. का. भा. 2502, तारीख 14-8-84
- (10) अधिसूचना सं. का. भा. 22 तारीख 5-1-85
- (11) शुद्धि पत्र सं. का. भा. 1953, तारीख 11-5-85
- (12) अधिसूचना सं. का. भा. 3082 तारीख 6-7-85
- (13) अधिसूचना सं. का. भा. 3974, तारीख 24-8-85
- (14) अधिसूचना सं. का. भा. 5641, तारीख 21-12-85
- (15) अधिसूचना सं. का. भा. 1548, तारीख 19-4-86
- (16) अधिसूचना सं. का. भा. 3183, तारीख 20-9-86
- (17) अधिसूचना सं. का. भा. 3787, तारीख 8-11-86

[सं. का. 1(30)ई II (ए)/87]

कुलवीर सिंह, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 24th August, 1987.

S.O. 2508.—In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 namely:—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule V to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, in the Annexure, against serial No. 14, for the entry under column 3, the following entry shall be substituted, namely:—

“Full powers where the printing is executed through or with the approval of the Director of Printing save in the case of Publications Division and Directorate of Advertising and Visual Publicity under the Ministry of Information and Broadcasting, where the Directors of these two organisations shall have powers of the Director in the Directorate of Printing to allocate their printing jobs to private printing presses.”

Note:—The Delegation of Financial Powers Rules, 1978 published vide Notification No. SO. 2131, dated 22nd July, 1978 have subsequently been amended by:—

- (i) Notification No. SO 1887, dated 9-6-1979.
- (ii) Notification No. SO. 2942, dated 1-9-1979.
- (iii) Notification No. S.O. 2611, dated 4-10-1980.
- (iv) Notification No. SO. 2164, dated 15-8-1981.
- (v) Notification No. SO. 2304, dated 5-9-1981.
- (vi) Notification No. SO. 3073, dated 4-9-1982.
- (vii) Notification No. SO. 4171, dated 11-12-1982.
- (viii) Notification No. SO 1314, dated 26-2-1983.
- (ix) Notification No SO. 2502, dated 4-8-1984.

- (x) Notification No. SO. 22, dated 5-1-1985.
- (xi) Carrigendum No. SO. 1958, dated 11-5-1985.
- (xii) Notification No. SO. 3082 dated 6-7-1985.
- (xiii) Notification No. SO. 3974, dated 24-8-1985.
- (xiv) Notification No. SO. 5641, dated 21-12-1985.
- (xv) Notification No. SO. 1548, dated 19-4-1986.
- (xvi) Notification No. SO. 3183, dated 20-9-1986.
- (xvii) Notification No. SO. 3787, dated 8-11-1986.

[No. F. 1(30)/E.II(A)/87]
KULDEEP SINGH, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1987

का. आ. 2509:- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 क 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जे. डी. खेतपाल को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 31-7-87 को समाप्त हो गयी है, 1-8-87 से प्रारंभ होकर 31-1-88 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या : एफ. 2-39/87-आर.आर. बी.]

प्रवीण कुमार तेजयान, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 31st August, 1987

S.O. 2509.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri J. D. Khetrapal whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 31-7-87 as the Chairman of Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarnagar for a further period commencing from 1-8-87 and ending with 31-1-88.

[No. F. 2-39/87-RRB]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 19 87

का आ 2510.—बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक की विकारित पर एतद्वारा घोषणा करती कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध 16 अगस्त, 1987 से 15 अगस्त, 1989 तक दो वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इनका सम्बन्ध नैनीताल बैंक लिमिटेड तथा बरेली कार्पोरेशन बैंक में शेयरों की इसकी धारिता से है।

[सं 15/11/87-बी. ओ. - III]

प्राणनाथ, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd September, 1987

S.O. 2510.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve

Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to Bank of Baroda for a period of two years from 16 August, 1987 upto 15 August 1989 in so far as they relate to its holding of shares in the Nainital Bank Ltd. and also in the Bareilly Corporation Bank Ltd.

[No. 15/11/87-B.O. III]
PRAN NATH, Under Secy.

आयकर आयुक्त का कार्यालय, विदम्ब

नागपुर, 1 मई, 1987

का. आ. 2511-—वित्तीय वर्ष 1985-86 की अवधि के लिए उन निर्धारितियों के नाम एवं अन्य विवरण की सूची दी गई है, अनुसूची -1 में ऐसे व्यक्ति तथा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब हैं जिनका 2 लाख से अधिक आय पर निर्धारित किया गया है, तथा अनुसूची-II में ऐसे फर्म/व्यक्तियों के समुदाय तथा कम्पनी हैं जिनका 10 लाख से अधिक आय पर निर्धारण किया गया है (i) प्रस्थिति—व्यक्तियों के लिए "व्य" हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए "हि" पंजीकृत फर्म के लिए "एफ" व्यक्तियों के समुदाय के लिए "व्यसमु" तथा कम्पनी के लिए "क" (ii) निर्धारण वर्ष (iii) विवरणी में दर्शायी आय (iv) निर्धारित की गयी आय (v) देय कर (vi) निर्धारितों द्वारा अदा किए गए कर की दर्शाता है।

अनुसूची -I

1. श्री राम गोपाल माहेश्वरी, नागपुर (1) व्य (2) 83-84 (3) 5,26,930 (4) 5,35,590 (5) 3,31,296 (6) 3,31,296
2. श्री प्रकाशचन्द्र माहेश्वरी, नागपुर (1) हि (2) 83-84 (3) 4,74,500 (4) 4,83,130 (5) 3,04,381 (6) 3,04,381
3. श्री प्रमल के. माहेश्वरी, नागपुर (1) हि (2) 83-84 (3) 4,81,000 (4) 4,89,650 (5) 3,03,473 (6) 3,03,473
4. श्री विनोदकुमार माहेश्वरी, नागपुर (1) हि (2) 83-84 (3) 4,79,400 (4) 4,88,050 (5) 3,07,417 (6) 3,07,417
5. श्री बतवारी लाल पुरोहित, नागपुर (1) व्य (2) 83-84 (3) 1,79,170 (4) 2,18,850 (5) 1,22,249 (6) 96,060
6. श्री भगवानदास पुरोहित, नागपुर (1) व्य (2) 83-84 (3) 2,46,680 (4) 2,78,920 (5) 1,61,895 (6) 1,40,500
7. श्री आसनदास लक्ष्मणदास, नागपुर (1) व्य (2) 85-86 (3) 2,79,988 (4) 2,78,540 (5) 1,50,129 (6) 1,50,980
8. श्री नारायणदास आसनदास, नागपुर (1) व्य (2) 85-86 (3) 2,78,770 (4) 2,78,770 (5) 1,50,270 (6) 1,50,980
9. श्री मयनमल आसनदास, नागपुर (1) व्य (2) 85-86 (3) 2,80,418 (4) 2,78,970 (5) 1,50,394 (6) 1,51,340
10. श्री पुरुषोत्तमदास आसनदास, नागपुर (1) व्य (2) 85-86 (3) 2,80,660 (4) 2,79,210 (5) 1,50,543 (6) 1,51,050
11. श्री लक्ष्मीनारायण सोवेंकी, अमरावती (1) व्य (2) 85-86 (3) 4,74,700 (4) 4,74,700 (5) 2,63,458 (6) 2,63,458
12. श्री कैलाशचन्द्र सोवेंकी, अमरावती (1) व्य (2) 85-86 (3) 3,46,946 (4) 3,35,450 (5) 1,85,355 (6) 1,85,355
13. श्रीमती सुरजीबाई जैन, अमरावती (1) व्य (2) 85-86 (3) 2,62,640 (4) 2,77,405 (5) 1,46,895 (6) 1,11,795
14. श्रीमती तारादेवी एम. सैनी, अमरावती (1) व्य (2) 85-86 (3) 5,27,070 (4) 5,36,255 (5) 3,20,784 (6) 3,20,784

15. श्री मारवाट हिंसा, नागपुर। (1) हि (2) 35-3
(3) 2,32,622 (4) 2,42,125 (5) 1,49,441 (6) 1,20,291
16. श्री जगन्नाथ एम. जडिया, नागपुर। (1) व्य (2) 85-86
(3) 2,14,820 (4) 2,21,330 (5) 1,30,506 (6) —
17. श्री बजाज मधुरकुमार, वर्धा। (1) व्य (2) 84-85
(3) 2,91,386 (4) 2,91,390 (5) 1,73,766 (6) 1,73,766
18. श्री बजाज मधुरकुमार, वर्धा। (1) व्य (2) 85-86 (3)
3,11,950 (4) 3,11,950 (5) 1,70,800 (6) 1,70,800
19. श्री बजाज रघुलकुमार वर्धा। (1) हि (2) 84-85
(3) 2,19,720 (4) 2,22,760 (5) 1,35,333 (6) 1,35,333
20. श्री शेखरकुमार बजाज, वर्धा। (1) व्य (2) 84-85
(3) 3,18,990 (4) 3,18,990 (5) 1,92,326 (6) 1,92,326
21. श्रीमती कुमुद बजाज, वर्धा। (1) व्य (2) 85-86
(3) 2,26,770 (4) 2,26,770 (5) 1,18,095 (6) 1,18,095
22. श्री कमलनयन बजाज, वर्धा। (2) हि (2) 85-86
(3) 4,45,125 (4) 4,45,120 (5) 2,85,426 (6) 2,85,426
23. श्रीमती रूपारानी बजाज, वर्धा। (1) व्य (2)
85-86 (3) 2,28,805 (4) 2,28,890 (5) 1,19,407 (6)
1,19,407
24. श्री नामदेव प्रभुदास, नागपुर। (1) व्य (2) 85-86 (3)
— (4) 2,13,780 (5) 1,12,152 (6) 1,10,058
25. श्री मो. अकजल, नागपुर। (1) व्य (2) 85-86 (3)
(4) 2,63,610 (5) 1,61,307 (6) 42,517
26. श्रीमती विमलादेव गोयतका, अकोला। (1) व्य (2)
83-84 (3) 1,05,580 (4) 2,28,770 (5) 1,28,796 (6) 47,655
27. श्री आर. एम. वानखेडे, अकोला। (1) व्य (2) 81-82
(3) 29,100 (4) 6,05,610 (5) 3,7,6822 (6) 5,300
28. श्री आर. एम. वानखेडे, अकोला। (1) व्य (2) 82-83
(3) 74,600 (4) 6,34,876 (5) 3,96,134 (6) 440
29. श्री आर. एम. वानखेडे, अकोला। (1) व्य (2) 83-84
(3) (—) 1,10,500 (4) 4,25,560 (5) 2,58,677 (6) —
30. श्रीमती प्रमिला के. राठी, अमरावती। (1) व्य (2) 85-
86 (3) 2,10,370 (4) 2,10,400 (5) 1,11,623 (6)
1,11,623
31. श्री अजय के. राठी, अमरावती। (1) व्य (2) 85-86
(3) 2,18,710 (4) 2,18,710 (5) 1,16,764 (6) 1,16,76
32. श्री चन्द्रमल गंगाधर अग्रवाल, गोंदिया। (1) हि (2)
83-84 (3) 15,200 (4) 2,38,740 (5) 1,66,275 (6)
2,450
33. श्री डी. के. नवगिरे, मागीदार—मै. डी. के. नवगिरे एवं
कं. धोली, नागपुर। (1) व्य (2) 83-84 (3) 77,110 (4)
2,98,050 (5) 2,31,130 (6) 46,635
34. श्री रमेश श्री. उपगंलावर, चन्द्रपुर। (1) हि (2) 85-86
(3) 3,19,120 (4) 3,19,120 (5) 1,90,839 (6) 1,90,839
35. श्री सुधाकर श्री. उपगंलावर, चन्द्रपुर। हि (2) 85-86
(3) 2,01,810 (4) 2,01,810 (5) 1,07,118 (6) 1,07,118
36. श्री जुलाबराज जी, उपगंलावर, चन्द्रपुर। (1) हि (2) 85-85
(3) 5,53,945 (4) 5,68,550 (5) 3,89,129 (6) 3,89,129
37. श्री नारायण श्री. उपगंलावर, चन्द्रपुर। (1) हि (2)
85-86 (3) 4,08,660 (4) 4,08,660 (5) 2,37,857 (6)
2,37,857

38. श्री मुरलीधर श्री. उपगंलावर चन्द्रपुर। (1) हि (2)
85-86 (3) 2,95,800 (4) 3,19,860 (5) 2,11,978 (6)
2,11,978

39. श्री रामकृष्ण श्री. उपगंलावर, चन्द्रपुर। (1) हि (2)
85-86 (3) 5,15,980 (4) 5,15,980 (5) 3,54,582 (6)
3,54,582

40. श्री रत्नसी डो. पटेल, चन्द्रपुर। (1) हि (2) 84-85
(3) 5,11,000 (4) 5,11,000 (5) 1,54,406 (6) 4,54,606

41. श्री रत्नसी डी. पटेल, चन्द्रपुर। (1) हि (2) 84-85
(3) 9,20,000 (4) 9,20,000 (5) 6,70,868 (6) 6,70,868

42. श्री जयवंत सिंह छत्तारमित्र (1) हि (2) 85-86 (3)
2,77,942 (4) 2,77,942 (5) 1,55,433 (6) 1,55,433

अनुसूची—II

43. श्री नर आरम प्रेस, नागपुर। (1) पक (2) 83-84 (3)
29,23,240 (4) 30,33,490 (4) 7,85,442 (6) 7,56,335

44. बजाज स्टॉल इन्स्ट्रूज प्रा. लि. कं., नागपुर। (1) कं
(2) 83-84 (3) 21,75,100 (4) 25,04,800 (5) 13,01,23
(6) 16,01,080

45. बजाज इन्स्ट्रूज प्रा. लि. कं., नागपुर। (1) कं (2) 83-84
(3) 18,02,800 (4) 21,35,830 (5) 12,45,600 (6)
12,45,600

46. मै. विदर्भ नितिकर कारपोरेशन (1) पक (2) 83-84 (3)
8,44,360 (4) 16,09,860 (5) 7,49,010 (6) 2,17,242

47. श्री सहाराष्ट्र सीड कारो. अकोला। (1) कं. (2) 83-84
(3) (—) 8,93,995 (4) 27,70,922 (5) 15,621 (6)
11,323

48. अकोला आयल इन्स्ट्रूज, अकोला। (1) कं. (2) 83-84
(3) (—) 21,63,405 (4) 37,07,230 (5) 25,753 (6)
1,229

49. श्री जय फिल्मस, अमरावती। (1) पक (2) 85-86
(3) 10,95,260 (4) 14,07,760 (5) 3,64,345 (6) 3,64,345

50. श्री मोहनस डिस्टिलरी, मागीदार, नागपुर। (1) हि (2)
85-86 (3) 11,31,630 (4) 12,31,990 (5) 3,15,987
(6) 3,16,887

51. श्री डी. के. नवगिरे एवं कं., नागपुर। (1) पक (2) 83-84
(3) 10,79,740 (4) 10,98,890 (4) 3,25,033 (6)
3,26,063

52. श्री बाराका टैलरशॉप, नागपुर। (1) पक (2) 85-85
(3) 1,28,800 (4) 12,88,000 (5) 3,49,455 (6)
3,49,455

53. श्री जनता वस्त्र मंडार, चन्द्रपुर। (1) पक (2) 83-86
(3) 11,74,000 (4) 11,74,000 (5) 3,17,773 (6)
3,17,773

54. श्री जनता सूटिंग सेक्टर, चन्द्रपुर। (1) पक (2)
85-86 (3) 11,45,000 (4) 11,45,000 (5) 3,08,668
(6) 3,08,668

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
INCOME-TAX

Nagpur, the 1st May, 1987

S.O. 2511. —Following is the list of the names and other particulars of the assesses namely Individuals and HUFs assessed on an income over Rs. 2 lakhs in Schedule-I and Firms, AOP and Companies assessed on an income over Rs.10 Lakhs in Schedule-II, during the financial year 1985-86 (i) Indicates Status- 'I' for Individuals 'H' for Hindu Undivided Families, 'RF' for Registered Firms, 'AOP' for Association of Persons and Co. for Companies (ii) for assessment year, (iii) for income returned, (iv) for income assessed, (v) for tax payable and (vi) for tax paid by the assessee :—

SCHEDULE - I

1. Shri Ramgopal Maheshwari, Nagpur. (i) I (ii) 83-84 (iii) 5,26,930 (iv) 5,35,590 (v) 3,31,296 (vi) 3,31,296.
2. Shri Prakashchandra Maheshwari, Nagpur, (i) H (ii) 83-84 (iii) 4,74,500 (iv) 4,83,130 (v) 3,04,381 (vi) 3,04,381.
3. Shri Praful K. Maheshwari, Nagpur. (i) H (ii) 83-84 (iii) 4,81,000 (iv) 4,89,650 (v) 3,08,473 (vi) 3,08,473.
4. Shri Vinod Kumar Maheshwari, Nagpur, (i) H (ii) 83-84 (iii) 4,79,400 (iv) 4,88,050 (v) 3,07,417 (vi) 3,07,417.
5. Shri Banwarilal Purohit, Nagpur. (i) I (ii) 83-84 (iii) 1,79,170 (iv) 2,18,850 (v) 1,22,249 (vi) 96,060.
6. Shri Bhagawandas Purohit, Nagpur. (i) I (ii) 83-84 (iii) 2,46,680 (iv) 2,78,920 (v) 1,61,895 (vi) 1,40,500.
7. Shri Assandas Laxmandas, Nagpur. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,79,988 (iv) 2,78,540 (v) 1,50,129 (vi) 1,50,980.
8. Shri Narayandas Assandas, Nagpur. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,78,770 (iv) 2,78,770 (v) 1,50,270 (vi) 1,50,980.
9. Baghanmal Assandas, Nagpur. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,80,418 (iv) 2,78,970 (v) 1,50,394 (vi) 1,51,340.
10. Shri Purushottamdas Assandas, Nagpur. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,80,660 (iv) 2,79,210 (v) 1,50,543 (vi) 1,51,050.
11. Shri Laxminarayan Solanki, Amravati. (i) I (ii) 85-86 (iii) 4,74,700 (iv) 4,74,700 (v) 2,63,458 (vi) 2,63,458.
12. Shri Kailaschandra Solanki, Amravati. (i) I (ii) 85-86 (iii) 3,46,946 (iv) 3,35,450 (v) 1,85,355 (vi) 1,85,355.
13. Smt. Surjibai Jain, Amravati. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,62,640 (iv) 2,77,405 (v) 1,46,895 (vi) 1,11,795.
14. Smt. Taradevi M. Saini, Amravati. (i) I (ii) 85-86 (iii) 5,27,070 (iv) 5,36,255 (v) 3,20,784 (vi) 3,20,784.
15. Shri Maghanmal Hiromal, Nagpur. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,32,622 (iv) 2,42,125 (v) 1,48,441 (vi) 1,70,291.
16. Shri Jagannath M. Jadiya, Nagpur. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,14,820 (iv) 2,21,330 (v) 1,30,506 (vi) —
17. Shri Bajaj Madhukumar, Wardha. (i) I (ii) 84-85 (iii) 2,91,386 (iv) 2,91,390 (v) 1,73,766 (vi) 1,73,766.
18. Shri Bajaj Madhukumar, Wardha. (i) I (ii) 85-86 (iii) 3,11,950 (iv) 3,11,950 (v) 1,70,800 (vi) 1,70,800.
19. Shri Bajaj Rahukumar, Wardha. (i) H (ii) 84-85 (iii) 2,19,720 (iv) 2,22,760 (v) 1,35,333 (vi) 1,35,333.
20. Shri Shekharkumar Bajaj, Wardha. (i) I (ii) 84-85 (iii) 3,18,990 (iv) 3,18,990 (v) 1,92,326 (vi) 1,92,326.
21. Smt. Kumud Bajaj, Wardha. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,26,770 (iv) 2,26,770 (v) 1,18,095 (vi) 1,18,89.
22. Shri Kamalnayan Bajaj, Wardha. (i) H (ii) 85-86 (iii) 4,45,125 (iv) 4,45,120 (v) 2,85,426 (vi) 2,85,426.
23. Smt. Ruparani Bajaj, Wardha. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,28,805 (iv) 2,28,890 (v) 1,19,407 (vi) 1,19,407.
24. Shri Namdeo Prabhudas, Nagpur. (i) I (ii) 85-86 (iii) — (iv) 2,13,780 (v) 1,12,152 (vi) 1,10,758.
25. Shri Mohd. Afzal, Nagpur. (i) I (ii) 85-86 (iii) — (iv) 2,63,610 (v) 1,61,307 (vi) 42,517.
26. Smt. Vimlabai Goenka, Akola. (i) I (ii) 83-84 (iii) 1,05,580 (iv) 2,28,770 (v) 1,28,796 (vi) 47,651.
27. Shri R.S. Wankhade, Akola. (i) I (ii) 81-82 (iii) 29,100 (iv) 6,05,610 (v) 3,76,822 (vi) 5,300.
28. Shri R.S. Wankhade, Akola. (i) I (ii) 82-83 (iii) 74,600 (iv) 6,34,876 (v) 3,96,134 (vi) 445.
29. Shri R.S. Wankhade, Akola. (i) I (ii) 83-84 (iii) — (iv) 1,10,500 (iv) 4,25,560 (v) 2,58,677 (vi) —
30. Smt. Pramila K. Rath, Amravati. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,10,370 (iv) 2,10,400 (v) 1,11,623 (vi) 1,11,623.
31. Shri Ajay K. Rath, Amravati. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,18,710 (iv) 2,18,710 (v) 1,16,764 (vi) 1,16,764.
32. Shri Chandumal Gangadhar Agarwal, Gondia. (i) H (ii) 83-84 (iii) 15,200 (iv) 2,38,740 (v) 1,66,275 (vi) 2,458.
33. Shri D.K. Navgire P/o M/s.D.K. Navgire & Co. Dhuleti, Nagpur (i) I (ii) 83-84 (ii) 77,110 (iv) 2,98,858 (v) 2,31,139 (vi) 46,635.
34. Shri Ramesh B. Uppanlawar, Chandrapur. (i) H (ii) 85-86 (iii) 3,19,120 (iv) 3,19,120 (v) 1,90,839 (vi) 1,90,839.
35. Sudhakar B. Uppanlawar, Chandrapur. (i) I (ii) 85-86 (iii) 2,01,810 (iv) 2,01,810 (v) 1,07,118 (vi) 1,07,118.
36. Gulabrao G. Uppanlawar, Chandrapur. (i) H (ii) 85-84 (iii) 5,53,945 (iv) 5,68,550 (v) 3,89,129 (vi) 3,89,129.
37. Narayan B. Uppanlawar, Chandrapur. (i) H (ii) 85-86 (iii) 4,08,660 (iv) 4,08,660 (v) 2,37,857 (vi) 2,37,857.
38. Shri Murlidhar B. Uppanlawar, Chandrapur. (i) H (ii) 85-86 (iii) 2,95,800 (iv) 3,19,860 (v) 2,11,978 (vi) 2,11,978.
39. Shri Ramkrishna B. Uppanlawar, Chandrapur. (i) H (ii) 85-86 (iii) 5,15,980 (iv) 5,15,980 (v) 3,54,582 (vi) 3,54,582.
40. Ratansi D. Patel, Chandrapur (i) H (ii) 84-85 (iii) 5,11,000 (iv) 5,11,000 (v) 4,45,606 (vi) 4,54,606.
41. Ratansi D. Patel, Chandrapur (i) H (ii) 84-85 (iii) 9,20,000 (iv) 9,20,000 (v) 6,70,868 (vi) 6,70,868.
42. Shri Jeswantsingh Chhattarsingh (i) H (ii) 85-86 (iii) 2,77,942 (iv) 2,77,942 (v) 1,55,438 (vi) 1,55,438.

SCHEDULE -II

43. M/s. Nav Bharat Press, Nagpur. (i) RF (ii) 83-84 (iii) 29,23,240 (iv) 30,33,490 (v) 7,85,442 (vi) 7,56,335

44. Bajaj Steel Industries, Pvt. Ltd. Company, Nagpur. (i) Co. (ii) 83-84 (iii) 21,75,100 (iv) 25,04,800 (v) 16,10,080 (vi) 16,01,080.

45. Bajaj Plastic Ltd., Co., Nagpur. (i) Co (ii) 83-84 (iii) 18,02,600 (iv) 21,35,830 (v) 12,45,600 (vi) 12,45,600

46. M/s. Vidarbha Liqueur Corporation. (i) R (ii) 83-84 (iii) 8,44,360 (iv) 16,09,860 (v) 7,40,010 (vi) 2,17,242

47. M/s. Maharashtra Steel Corpn., Akola (i) Co. (ii) 83-84 (iii) (-) 8.93,995 (iv) 27,70,922 (v) 15,621 (vi) 11,323

48. Akola Oil Industries, Akola (i) Co. (ii) 83-84 (iii) (-) 21,63,405 (iv) 37,07,230 (v) 25,758 (vi) 1,229

49. M/s. Jai Films, Amraoti. (i) RF (ii) 85-86 (iii) 18,95,260 (iv) 14,07,760 (v) 3,64,345 (vi) 3,64,345.

50. M/s. Somras Distillers, Gandhibagh, Nagpur (i) RF (ii) 85-86 (iii) 11,31,680 (iv) 12,31,990 (v) 3,16,887 (vi) 3,16,887.

51. M/s. D.K. Navgire & Co., Nagpur (i) RF (ii) 83-84 (iii) 10,79,740 (iv) 10,98,890 (v) 3,26,083 (vi) 3,26,088.

52. M/s. Balaji Textiles, Chandrapur (i) RF (ii) 85-86 (iii) 1,28,800 (iv) 12,88,000 (v) 3,42,455 (vi) 3,49,455.

53. M/s. Janta Vastu Bhandar, Chandrapur (i) RF (ii) 85-86 (iii) 11,74,000 (iv) 11,74,000 (v) 3,17,773 (vi) 3,17,773.

54. M/s. Janta Sutting Centre, Chandrapur (i) RF (ii) 85-86 (iii) 11,45,000 (iv) 11,45,000 (v) 3,08,668 (vi) 3,808,688.

[F.No.Recy/287/42A/86-87]

का. आ. 2512.—निम्न सूची में दर्शाए व्यक्तिओं पर, वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान 5000/- रुपए से अधिक की शास्ति लगायी गयी थी । (1) प्राप्ति—व्यक्तियों के लिए "अ", हिन्दु अविभाजित कुटुम्ब के लिए "हि", पंजीकृत फर्म के "वक", प्रपंजीकृत फर्म के लिए "प्रवक", कम्पनी के लिए "क", सहकारी समिति के लिए "समिति", तथा व्यक्तियों के समुदाय के लिए "असमूह" (ii) निर्धारण वर्ष (iii) शास्ति की राशि (iv) धारा, जिसके अधीन शास्ति लगायी गयी, को इंगित करता है:—

अनुसूची

- श्री राम प्रसाद अगुजी साहू, वर्धा । (1) व्य (2) 79-80 (3) 7,935 (4) 271 (1)(ग)
- मै. जॉन्स ट्रेडिंग कं. नागपुर । (1) पक (2) 81-82 (3) 7,487 (4) 273 (1)(ख)
- मै. नारायणदास सोनावाल, भावर्षी । (1) पक (2) 81-82 (3) 13,000 (4) 271 (1)(ग)
- दादाभाई बंजीबाई (हिरनबाई) जाल करीटेबल ट्रस्ट, कापटी । (1) व्यसमू (2) 79-80 (3) 26,542 (4) 140 (क) (3)
- श्री नन्द किशोर अग्रवाल, नागपुर । (1) व्य (2) 84-85 (3) 10,766 (4) 273 (2)(ख)
- मै. एकनाथ मुकाराम दोबले, नागपुर । (1) पक (2) 82-83 (3) 85,000 (4) 271 (1)(ग)
- मै. खरे ब्रदर्स, नागपुर । (1) पक (2) 81-82 (3) 18,500 (4) 271 (1)(ग)
- श्री आई. पी. खरे, नागपुर । (1) व्य (2) 81-82 (3) 13,300 (4) 271 (1)(ग)
- मै. अमर ट्रेडिंग कं. अमरावती । (1) पक (2) 85-86 (3) 5,552 (4) 271 (1)(क)
- मै. सपना इंडस्ट्रीज, अमरावती । (1) पक (2) 85-86 (3) 5,000 (4) 273 (1)(ख)
- श्री शरदचन्द्र बालपांडे, नागपुर । (1) व्य (2) 81-82 (3) 1,45,460 (4) 271(1)(ग)

- श्री शरदचन्द्र बालपांडे, नागपुर । (1) व्य (2) 81-82 (3) 10,910 (4) 273 (2)(ख)
- श्री शरदचन्द्र बालपांडे, नागपुर । (1) व्य (2) 81-82 (3) 90,148 (4) 271 (1)(क)
- श्री शरदचन्द्र बालपांडे, नागपुर । (1) व्य (2) 81-82 (3) 14,546 (4) 271 (1)(ख)
- मै. ज्वाला इंडस्ट्रीज, नागपुर । (1) पक (2) 81-82 (3) 6,190 (4) 271 (1)(क)
- कुलीचन्द्रजी दुग्गड़, चन्द्रपुर । (1) व्य (2) 83-84 (3) 12,329 (4) 271 (1)(ग)
- श्री प्रकाश डी. दुग्गड़, चन्द्रपुर । (1) व्य (2) 84-85 (3) 6,440 (4) 273(2)(ख)
- मै. सुभाष ट्रेडिंग, नागपुर । (1) पक (2) 81-82 (3) 5,240 (4) 271 (1)(क)
- मै. सुभाष ट्रेडिंग, नागपुर । (1) पक (2) 82-83 (3) 5,240 (4) 271 (1)(क)
- मै. कोंकाबाई रहमनखली (1) पक (2) 81-82 (3) 11,045 (4) 271 (1)(क)
- श्री एम. बी. डोंगरे, कंजोवालवेठ, बबुलखेड़ा, नागपुर । (1) व्य (2) 76-77 (3) 7,140 (4) 271 (1)(क)
- श्री एम. बी. डोंगरे, नागपुर । (1) व्य (2) 76-77 (3) 320 (4) 273 (1)(ख)
- श्री एम. बी. डोंगरे, नागपुर । (1) व्य (2) 77-78 (3) 7,000 (4) 271 (1)(क)
- श्री एम. बी. डोंगरे, नागपुर । (1) व्य (2) 77-78 (3) 2,260 (4) 273 (1)(ख)
- श्री एम. बी. डोंगरे, नागपुर । (1) व्य (2) 78-79 (3) 6,344 (4) 217 (1) (क)
- श्री एम. बी. डोंगरे, नागपुर । (1) व्य (2) 78-79 (3) 410 (4) 273 (क)(ख)
- श्री एम. बी. डोंगरे, नागपुर । (1) व्य (2) 80-81 (3) 260 (4) 273 (1)(ख)
- श्री एम. बी. डोंगरे, नागपुर । (1) व्य (2) 80-81 (3) 2,170 (4) 271 (1)(क)
- मै. शक्ति आटोमोबाइल, चन्द्रपुर । (1) पक (2) 83-84 (3) 6,688 (4) 271 (1)(क)
- मै. शक्ति आटोमोबाइल, चन्द्रपुर । (1) पक (2) 81-82 (3) 14,480 (4) 271 (1)(क)
- श्री ए. जी. पाकरी, चन्द्रपुर । (1) व्य (2) 80-81 (3) 5,926 (4) 271 (1)(क)
- श्री एम. जी. पाकरी, चन्द्रपुर । (1) व्य (2) 80-81 (3) 5,337 (4) 271 (1) (क)
- मै. बजरंग आहल मित्र एवं दास मिल, मून । (1) पक (2) 83-84 (3) 7,854 (4) 271 (1)(क)
- मै. बजरंग आहल मित्र एवं दास मिल, मून । (1) पक (2) 82-83 (3) 5,080 (4) 271 (1)(क)
- मै. विनोदमित्र एम. कंठा, चन्द्रपुर । (1) पक (2) 81-82 (3) 25,750 (4) 271 (1)(क)
- मै. दिशोराम एम. कंठा, चन्द्रपुर । (1) पक (2) 82-83 (3) 14,740 (4) 271 (1)(क)

[का. सं. वसूची/287/42ए/86-87]

S.O. 2512.—Following is the list of persons on whom penalty not less than Rs.5000/-was imposed during the F.Y. 1985-86 (i) indicating status "I" for Individual, "H" for Hindu Undivided Families, "RF" for Registered Firms, "URF" for Unregistered Firms "CO" for Companies and "STY" for Co-operative Society "AOP" for Association of Persons (ii) for Assessment Year (iii) Amount of penalty (iv) Section Under which the penalty was imposed :

SCHEDULE

- Shri Ramprasad Agnuji Sahu, Wardha. (i) I (ii) 79-80 (iii) 7,935 (iv) 271(1)(c).

2. M/s. Chand Trading Co., Nagpur. (i) RF (ii) 81-82 (iii) 7,487 (iv) 273(i)(b).
3. M/s. Narayandas Sonalal, Arvi. (i) RF (ii) 81-82 (iii) 13,000 (iv) 271(1)(c).
4. Dadabhai Doshibai (Hiranbai) Zal Charitable Trust, Kamptee. (i) AOP (ii) 79-80 (iii) 26,542 (iv) 140(AX3).
5. Shri Nandkishore Agrawal, Nagpur. (i) I (ii) 84-85 (iii) 10,766 (iv) 273 (2)(b).
6. M/s. Eknath Tukaram Dhoble, Nagpur. (i) (i) RF (ii) 82-83 (iii) 85,000 (iv) 271(1)(c).
7. M/s. Khare Brothers, Nagpur. (i) RF (ii) 81-82 (iii) 18,500 (iv) 271(1)(c).
8. Shri I.P. Khare Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) (iii) 13,300 (iv) 271(1)(c).
9. M/s. Amar Trading Co., Amraoti. (i) RF (ii) 85-86 (iii) 5,552 (iv) 271(1)(a).
10. M/s. Sapna Industries, Amravoti. (i) RF (ii) 85-86 (iii) 5,000 (iv) 273(i)(b).
11. Shri Sharadchandra Balpande, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 1,45,460 (iv) 271(i)(c).
12. Shri Sharadchandra Balpande, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 10,910 (iv) 273(2)(b).
13. Shri Sharadchandra Balpande, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 90,148 (iv) 271(1) (a)
14. Shri Sharadchandra Balpande, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 14,546 (iv) 271(1)(b).
15. M/s. Jawala Industries, Nagpur. (i) RF (ii) (ii) 81-82 (iii) 6,190 (iv) 271(1)(a).
16. Dulichandji Duggad, Chandrapur. (i) I (ii) 83-84 (iii) 12,329 (iv) 271(1)(c).
17. Shri Prakash D. Duggad, Chandrapur. (i) I (ii) 84-85 (iii) 6,440 (iv) 273(2)(b).
18. M/s. Subhash Trading, Nagpur. (i) RF (ii) 81-82 (iii) 5,240 (iv) 271(1)(a).
19. M/s. Subhash Trading, Nagpur. (i) RF (ii) (ii) 82-83 (iii) 5,240 (iv) 271(1)(a).
20. M/s. Kikabhai Rehamatali (i) RF (ii) 81-82 (iii) 11,045 (iv) 271(1)(a).
21. Shri S.V. Dongre, Kunjilalpath, Babulkheda, Nagpur. (i) I (ii) 76-77 (iii) 7,140 (iv) 271(1)(a).
22. Shri S.V. Dongre, Nagpur. (i) I (ii) 76-77 (iii) 320 (iv) 273(1)(b).
23. Shri S.V. Dongre, Nagpur. (i) I (ii) 77-78 (iii) 7,000 (iv) 271(1)(a).
24. Shri S.V. Dongre, Nagpur. (i) I (ii) 77-78 (iii) 2,260 (iv) 273(1)(b).
25. Shri S.V. Dongre, Nagpur. (i) I (ii) 78-79 (iii) 6,344 (iv) 271 (i) (ii)
26. Shri S.V. Dongre, Nagpur. (i) I (ii) 78-79 (iii) 410 (iv) 273(1)(b).
27. Shri S.V. Dongre, Nagpur. (i) I (ii) 80-81 (iii) 260 (iv) 273(1)(b).
28. Shri S.V. Dongre, Nagpur. (i) I (ii) 80-81 (iii) 2,170 (iv) 271(1)(a).

29. M/s. Shakti Automobiles, Chandrapur. (i) RF(ii) 83-84 (iii) 6,688 (iv) 271(1)(a).
30. M/s. Shakti Automobiles, Chandrapur. (i) RF (ii) 81-82 (iii) 14,480 (iv) 271(1)(a).
31. Shri A.G. Pophali, Chandrapur. (i) I (ii) 80-81 (iii) 5,926 (iv) 271(1)(a).
32. Shri N.G. Pophali, Chandrapur. (i) I (ii) 80-81 (iii) 5,337 (iv) 271(1)(a).
33. M/s. Bajrang Oil Mill & Dal Mill, Mul. (i) RF (ii) 83-84 (iii) 7,854 (iv) 271(1) (a).
34. M/s. Bajrang Oil Mill & Dal Mill, Mul. (i) RF (ii) 82-83 (iii) 5,030 (iv) 271(1)(a).
35. M/s. Dilipsing S. Kanda, Chandrapur. (i) RF (ii) 81-82 (iii) 25,750 (iv) 271(1)(a).
35. M/s. Dilipsing S. Kanda, Chandrapur. (i) RF (ii) 82-83 (iii) 14,740 (iv) 271(1)(a).

[No. R-287/42 A/86-87]

का. प्रा. 2513.—विगत वर्ष 1985-86 को आय के लिए ऐम व्यक्ति को सूचा नीचे प्रस्तुत की जा रही है जिसका 10 लाख रु. से अधिक शुद्ध धन पर निर्धारण किया गया है। (1) प्रास्थिति—व्यक्तियों के लिए "अप", हिंदु परिवार कुल के लिए "पि" व्यक्तियों के समुदाय के लिए "अपम", व्यापारियों के लिए "अप" (2) निर्धारण वर्ष (3) जिसकी में वर्गीकृत धन/निर्धारित धन (4) निर्धारित द्वारा देय कर (5) निर्धारित द्वारा अदा किए गए कर, को दर्शाता है।

अनुसूची

1. श्रीमती चंद्रदेवी सराफ (स्वर्गीय) वैज उत्तराधिकारी श्री मोहिन्द-दास सराफ, नागपुर। (1) अ (2) 81-82 (3) 23,17,100/28, 24,437 (4) 94,971 (5) 91,542
2. श्रीमती स्वर्णलतादेवी सराफ, नागपुर। (1) अ (2) 81-82, (3) 11,31,500/12,85,963 (4) 20,529 (5) 20,529
3. श्रीमती छायादेवी सराफ, नागपुर। (1) अ (2) 81-82 (3) 11,21,157/12,11,063 (4) 20,081 (5) 20,081
4. श्रीमती निशादेवी सराफ, नागपुर। (1) अ (2) 81-82 (3) 10,99,800/10,98,118 (4) 16,693 (5) 16,253
5. श्री मनोज कुमार सराफ, मुमतर। (1) अ (2) 81-82 (3) 10,37,000/10,54,475 (4) 15,385 (5) 15,385
6. स्वर्गीय श्रीमती गोदावरीदेवी सराफ, वैज उत्तराधिकारी, श्री गुणप्रसाद सराफ, मुमतर। (1) अ (2) 81-82 (3) 9,92,100/ 10,73,610 (4) 14,958 (5) 13,060
7. श्री अनुराग तरंग ट्रस्ट, वर्धा। (1) व्यसम् (2) 84-85 (3) 21,95,085/21,31,100 (4) 63,935 (5) 63,935
8. श्री अनुराग तरंग ट्रस्ट, वर्धा। (1) व्यसम् (2) 83-84 (3) 22,47,250/21,81,800 (4) 65,454 (5) 65,454
9. श्री अनुराग तरंग ट्रस्ट, वर्धा। (1) व्यसम् (2) 82-83 (3) 23,48,457/22,80,100 (4) 68,402 (5) 68,402
10. श्री सुनैयना ट्रस्ट, वर्धा। (1) व्यसम् (2) 84-85 (3) 21,90,189/21,87,800 (4) 65,634 (5) 65,634
11. श्री सुनैयना ट्रस्ट, वर्धा। (1) व्यसम् (2) 83-84 (3) 21,10,934/21,07,000 (4) 63,210 (5) 63,210
12. श्री सुनैयना ट्रस्ट, वर्धा। (1) व्यसम् (2) 82-83 (3) 22,32,598/22,31,000 (4) 66,931 (5) 66,931
13. श्री सुनैयना ट्रस्ट, वर्धा। (1) व्यसम् (2) 81-82 (3) 13,42,054/13,26,300 (4) 39,788 (5) 39,788

14. श्री कुमुद ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 84-85 (3) 19,19,209/19,11,600 (4) 57,347 (5) 57,347
15. कुमुद ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 83-84 (3) 12,54,677/12,38,900 (4) 37,167 (5) 37,167
16. श्री कुमुद ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 82-83 (3) 16,69,600/16,57,200 (4) 49,715 (5) 49,715
17. श्री कुमुद ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 81-82 (3) 22,86,700/22,86,200 (4) 68,587 (5) 68,587
18. श्री कुशाग्र ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (3) 84-85 (3) 20,03,764/19,45,400 (4) 58,362 (5) 58,362
19. श्री कुशाग्र ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 83-84 (3) 18,43,331/17,93,500 (4) 53,806 (5) 53,806
20. श्री कुशाग्र ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 82-83 (3) 20,25,080/19,66,100 (4) 58,983 (5) 58,983
21. श्री संजीवनयन ट्रस्ट, वर्धा । (1) व्यसम् (2) 81-82 (3) 15,05,600/15,36,900 (4) 44,767 (5) 44,767
22. श्री संजीवनयन ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 82-83 (3) 23,60,800/23,61,900 (4) 71,845 (5) 71,845
23. श्री संजीवनयन ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 83-84 (3) 22,68,300/22,69,400 (4) 68,082 (5) 68,082
24. श्री संजीवनयन ट्रस्ट वर्धा । (1) व्यसम् (2) 84-85 (3) 24,33,800/24,51,600 (4) 76,330 (5) 76,330
25. श्रीमती विमलादेवी बजाज ट्रस्ट, वर्धा । (1) व्यसम् (2) 81-82 (3) 12,92,600/13,24,200 (4) 39,736 (5) 39,736
26. श्री रामकृष्ण बजाज ट्रस्ट, वर्धा । (1) व्यसम् (2) 84-85 (3) 11,79,100/11,87,200 (4) 35,617 (5) 35,617
27. श्री रामकृष्ण बजाज ट्रस्ट, वर्धा । (1) व्यसम् (2) 83-84 (3) 9,76,700/10,00,300 (4) 30,010 (5) 30,010
28. श्री रामकृष्ण बजाज ट्रस्ट, वर्धा । (1) व्यसम् (2) 82-83 (3) 14,12,800/14,41,700 (4) 43,250 (5) 43,250
29. श्री रामकृष्ण बजाज ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 81-82 (iii) 20,31,700/20,50,200 (iv) 61,507 (v) 61,507
30. श्री भवन्त ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 83-84 (iii) 10,24,900/10,09,200 (iv) 30,275 (v) 30,275
31. श्री मिनाक्षी ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 84-85 (iii) 12,97,600/13,14,900 (iv) 39,447 (v) 39,447
32. श्री मिनाक्षी ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 83-84 (iii) 9,70,900/10,02,500 (iv) 30,074 (v) 30,074
33. श्री मिनाक्षी ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 82-83 (iii) 12,47,000/12,68,500 (iv) 38,056 (v) 38,056
34. श्री मिनाक्षी ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 81-82 (iii) 15,62,900/15,72,300 (iv) 47,169 (v) 47,169
35. श्री कमलनयन बजाज ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 84-85, (iii) 16,09,500/12,76,000 (iv) 38,281 (v) 38,281
36. श्री कमलनयन बजाज ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 83-84 (iii) 11,26,700/11,32,600 (iv) 33,979 (v) 33,979
37. श्री कमलनयन बजाज ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 82-83 (iii) 17,51,900/17,58,700 (iv) 52,760 (v) 52,760
38. श्री कमलनयन ट्रस्ट, वर्धा । (i) व्यसम् (ii) 81-82 (iii) 25,99,600/26,12,100 (iv) 84,355 (v) 84,355
39. श्री खालदास मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 84-85 7,47,503/17,54,200 (iv) 41,460 (v) 8,700
40. श्री गिरधरदास मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 84-85 5,74,938/16,84,800 (iv) 37,988 (v) 5,280
41. श्री शिशिरकुमार बजाज, वर्धा । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 94,10, 10,00/94,80,600 (iv) 4,27,782 (v) 4,24,247
42. श्री शिशिरकुमार बजाज, वर्धा । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 98,46,500/1,02,71,400 (iv) 4,67,321 (v) 4,46,223
43. श्री राहुलकुमार बजाज, वर्धा । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 1,83,24,900/1,84,72,200 (iv) 8,77,360 (v) 8,69,993
44. श्री राहुलकुमार बजाज, वर्धा । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 1,90,90,700/1,97,22,900 (iv) 9,39,887 (v) 08,288
45. श्री रामकृष्ण बजाज, वर्धा । (i) हि (ii) 83-84 (iii) 51,95,500/55,57,000 (iv) 2,51,632 (v) 2,33,524
46. श्री रामकृष्ण बजाज, वर्धा । (i) हि (ii) 84-85 (iii) 50,91,500/54, (iv) 2,47,192 (v) 2,28,328
47. श्री मधुरकुमार बजाज, वर्धा । (i) हि (ii) 84-85 (iii) 26,08,300/28,76,200 (iv) 1,17,559 (v) 1,04,162
48. श्री शेखरकुमार बजाज, वर्धा । (i) हि (ii) 84-85 (iii) 36,15,300/42,45,400 (iv) 1,86,022 (v) 1,54,514
49. श्री शेखरकुमार बजाज, वर्धा । (i) हि (ii) 83-84 (iii) 33,41,100/38,77,000 (iv) 1,67,599 (v) 1,40,807
50. श्री प्रनुरंग जैन, वर्धा । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 14,00,000/17,36,500 (iv) 40,573 (v) 40,573
51. श्री प्रनुरंग जैन, वर्धा । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 12,43,500/12,53,400 (iv) 21,351 (v) 21,053
52. श्री तरंग जैन, वर्धा । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 15,86,200/15,70,600 (iv) 32,281 (v) 22,335
53. श्री तरंग जैन, वर्धा । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 12,44,390/14,20,700 (iv) 26,371 (v) 21,088
54. श्री गिरधरदास मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 6,11,873/15,33,100 (iv) 30,403 (v) 6,946
55. श्री विनयकुमार मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 5,74,596/10,08,500 (iv) 14,005 (v) 6,373
56. श्रीमती सरलादेवी मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 11,47,688/16,50,400 (iv) 36,270 (v) 24,172
57. श्रीमती सुर्याकांतदेवी मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 7,94,854/13,10,100 (iv) 23,052 (v) 12,135
58. श्रीमती शान्तादेवी मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 8,78,429/12,74,400 (iv) 21,983 (v) 14,261
59. श्री रणछोदास मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 5,10,064/11,09,700 (iv) 17,040 (v) 5,634
60. श्री प्रवणकुमार मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 9,40,456/12,29,400 (iv) 20,631 (v) 20,631
61. श्री खालदास मोहता, हिंगनघाट । (i) हि (ii) 85-86 (iii) 7,34,871/13,52,600 (iv) 41,380 (v) 19,227
62. श्री गिरधरदास मोहता, हिंगनघाट । (i) हि (ii) 85-86 (iii) 5,06,839/11,82,300 (iv) 32,866 (v) 14,897
63. श्री खालदास मोहता, हिंगनघाट । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 7,29,374/15,96,900 (iv) 33,593 (v) 3,634
64. श्री रणछोदास मोहता, हिंगनघाट । (i) हि (ii) 85-86 (iii) 5,47,663/10,20,400 (iv) 24,769 (v) 13,320
65. श्री हरगोविन्द बजाज, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 8,70,725/10,68,200 (iv) 15,796 (v) 15,796

66. श्री गंगाबिसल बजाज, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 7,51,959/10,11,200 (iv) 14,086 (v) 14,086 ।
67. श्रीमती जुवेदाबाई अम्बुल्लाभाई, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 7,97,612/10,26,482 (iv) 14,180 (v) 14,180 ।
68. श्रीमती जुवेदाबाई अम्बुल्लाभाई, नागपुर । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 7,57,950/10,13,950 (iv) 13,754 (v) 13,754 ।
69. श्रीमती जुवेदाबाई अम्बुल्लाभाई, नागपुर । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 12,16,800/12,67,700 (iv) 21,148 (v) 21,148 ।
70. श्रीमती जुवेदाबाई अम्बुल्लाभाई, नागपुर । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 11,18,328/11,34,620 (iv) 17,240 (v) 17,240 ।
71. श्रीमती सकीनाबाई युसुफभली, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 10,06,400/12,31,142 (iv) 20,082 (v) 20,082 ।
72. श्रीमती सकीनाबाई युसुफभली, नागपुर । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 9,88,700/12,69,200 (iv) 21,190 (v) 21,190 ।
73. श्रीमती सकीनाबाई युसुफभली, नागपुर । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 5,65,800/16,31,200 (iv) 33,635 (v) 33,635 ।
74. श्रीमती सकीनाबाई युसुफभली, नागपुर । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 11,50,028/12,13,800 (iv) 19,577 (v) 19,577 ।
75. श्री असगरअली हसनअली, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 16,85,664/14,49,400 (iv) 31,220 (v) 31,220 ।
76. श्रीमती मरावेवी रुइया, नागपुर । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 9,47,216/10,56,700 (iv) 15,451 (v) 12,443 ।
77. श्री ए. बाय. खरे, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 8,40,270/13,06,800 (iv) 22,955 (v) 1,760 ।
78. श्री ए. बाय. खरे, नागपुर । (i) व्य (ii) 82-83 (iii) 8,93,250/13,95,515 (iv) 25,615 (v) ।
79. श्री ए. बाय. खरे, नागपुर । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 7,07,780/15,61,300 (iv) 31,915 (v) 7,750 ।
80. श्री कंजी हरीलाल वेगड, उमरेड । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 4,40,500/10,10,800 (iv) 14,074 (v) 10,953 ।
81. श्री हेमराज हरीलाल वेगड, उमरेड । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 3,31,800/10,70,400 (iv) 15,862 (v) 2,047 ।
82. श्री मंगलाल हरीलाल वेगड, नागपुर । उमरेड । (i) व्य (ii) 85-86 (iii) 4,69,800/10,04,200 (iv) 13,877 (v) 3,413 ।
83. श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल, नागपुर । (i) हि (ii) 81-82 (iii) 9,79,400/12,41,297 (iv) 14,730 (v) ।
84. श्री विजयप्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) हि (ii) 81-82 (iii) 3,33,500/10,17,502 (iv) 19,310 (v) ।
85. श्री विजयप्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) हि (ii) 82-83 (iii) 3,24,800/10,09,216 (iv) 19,081 (v) ।
86. श्रीमती चन्द्रकला कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 5,44,500/12,12,292 (iv) 15,568 (v) ।
87. श्रीमती चन्द्रकला कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 82-83 (iii) 6,07,000/12,72,970 (iv) 16,165 (v) ।
88. श्रीमती चन्द्रकला कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 7,30,700/12,71,127 (iv) 13,687 (v) ।
89. श्रीमती चन्द्रकला कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 7,84,00/13,35,980 (iv) 23,830 (v) ।
90. श्री ब्रह्मप्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 5,16,900/11,33,069 (iv) 13,799 (v) ।
91. श्री ब्रह्मप्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 82-83 (iii) 5,51,600/11,68,757 (iv) 14,085 (v) ।
92. श्री ब्रह्मप्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 6,68,400/11,96,707 (iv) 12,674 (v) ।
93. श्री ब्रह्मप्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 2,13,300/12,40,301 (iv) 13,099 (v) ।
94. श्री शिव प्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 81-82 (iii) 4,52,700/10,93,658 (iv) 13,315 (v) ।
95. श्री शिव प्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 82-83 (iii) 4,93,600/1,33,368 (iv) 14,094 (v) ।
96. श्री शिव प्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 83-84 (iii) 6,06,400/11,40,016 (iv) 17,951 (v) ।
97. श्री शिव प्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) व्य (ii) 84-85 (iii) 5,08,000/10,70,804 (iv) 12,041 (v) ।
98. श्री भजय प्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) हि (ii) 81-82 (iii) 5,59,600/11,61,676 (iv) 26,989 (v) ।
99. श्री भजय प्रकाश कनोरिया, नागपुर । (i) हि (ii) 82-83 (iii) 6,36,776/12,92,852 (iv) 31,721 (v) ।
100. श्री भजय प्रकाश कनोरिया, नागपुर । (1) हि (2) 83-84 (3) 6,30,900/12,00,160 (4) 27,458 (5) —।
101. श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, नागपुर । (1) हि (2) 82-83 (3) 9,84,700/12,30,437 (4) 13,160 (5) —।
102. श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, नागपुर । (1) हि (2) 83-84 (3) 83,500/12,48,596 (5) 13,614 (5) —।
103. श्री बनीप्रसाद कनोरिया, नागपुर । (1) व्य (2) 81-82 (3) (-) 11,650/10,17,181 (4) 14,264 (5) —।
104. श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, नागपुर । (1) हि (2) 84-85 (3) 11,09,200/15,68,548 (4) 25,711 (5) —।
105. श्रीमती राधाबाई एस. तापनीवाल, अकोला । (1) व्य (2) 82-83 (3) 8,06,400/11,75,625 (4) 19,020 (5) 19,020 ।
106. श्री धीसूलाल जी. बजाज, वैद्य उत्तरा राम निर्देवन बजाज, तेल्हारा । (1) व्य (2) 83-84 (3) 19,12,518/13,22,165 (4) 22,735 (5) शून्य ।
107. श्री श्यामसुन्दर एम. कछोलिया, नवली । (1) हि (2) 83-84 (3) 10,30,805/10,30,805 (4) 14,675 (5) 14,675 ।
108. श्री श्यामसुन्दर एम. कछोलिया, नवली । (1) हि (2) 84-85 (3) 1,60,368/11,60,368 (4) 18,562 (5) 18,562 ।
109. श्रीमती ग्यारिसबाई एम. कछोलिया, नवली । (1) व्य (2) 83-84 (3) 10,61,109/10,61,109 (4) 15,583 (5) 15,583 ।
110. श्रीमती ग्यारिसबाई एम. कछोलिया, नवली । (1) व्य (2) 84-85 (3) 10,93,484/10,93,484 (4) 16,553 (5) 16,553 ।
111. श्री श्यामसुन्दर एम. कछोलिया, नवली । (1) हि (2) 85-86 (3) 12,40,600/12,40,608 (4) 21,430 (4) 21,430 ।
112. श्रीमती निर्मलादेवी सिकची, अमरावती । (1) व्य (2) 85-86 (3) 12,06,900/12,06,900 (4) 19,375 (5) 19,375 ।
112. श्रीमती निर्मलादेवी सिकची, अमरावती । (1) व्य (2) 85-86 (3) 12,06,900/12,06,900 (4) 19,375 (4) 19,375 ।
113. श्री एच. जे. कल्मेली, अमरावती । (1) व्य (2) 85-86 (3) 10,18,800/10,17,800 (4) 13,860 (5) 13,860 ।
114. श्री धार. धार. लाहोटी, अमरावती । (1) व्य (2) 85-86 (3) 11,67,785/11,84,285 (4) 18,725 (5) 18,725 ।
115. श्रीमती नरायणी धार. देडा, अमरावती । (1) व्य (2) 85-86 (3) 13,52,400/13,52,400 (4) 23,611 (5) 23,611 ।
116. श्रीमती वर्षाबेन प्रफुल्ल पटेल, गोंदिया । (1) व्य (2) 85-86 (3) 15,67,000/15,67,000 (4) 32,105 (5) 32,105 ।

117. श्रीमती पद्मादेवी बरी, सिविल लाइन्स, नागपुर। (1) अ (2) 81-82 (3) 10,43,200/10,43,200 (4) 14,608 (5) 10,990
118. श्री एम. जी. पटेल, चन्द्रपुर। (1) (1) अ (2) 85-86 (3) 14,22,507/16,21,307 (4) 34,820 (5) 34,820।
119. श्री सी. जी. पटेल, चन्द्रपुर। (1) अ (2) 85-86 (3) 13,59,066/13,35,256 (5) 23,810 (5) 23,810।
120. श्री राजा सी. पटेल, (1) अ (2) 85-86 (3) 10,41,337/10,53,530 (4) 15,370 (5) 15,370।
121. श्रीमती लतीताबेन सी. पटेल, चन्द्रपुर। (1) अ (2) 85-86 (3) 15,98,667/15,45,959 (4) 33,048 (5) 3,148।
122. श्रीमती प्रमिला ए. मुनीत, यवतमाल। (1) अ (2) 85-86 (3) 11,93,915/11,93,915 (4) 19,567 (5) 19,567।
123. श्रीमती प्रमिता जे. मुनीत, यवतमाल। (1) अ (2) 85-86 (3) 11,88,300/11,88,300 (4) 19,398 (5) 19,398।
124. श्रीमती मंदिनी डो. मुनीत, यवतमाल। (1) अ (2) 85-86 (3) 14,68,550/14,68,550 (5) 27,808 (5) 27,806।
125. श्रीमती गुलाबार्ई एच. मुनीत, यवतमाल। (1) अ (2) 85-86 (3) 12,49,060/12,49,060 (4) 21,221 (5) 21,221।
126. श्रीमती माणिक आर. मुनीत, यवतमाल। (1) अ (2) 85-86 (3) 12,81,600/12,81,600 (4) 22,197 (5) 22,197।
127. श्रीमती पंजकुलानार्ई आर. सुराना, पांडरकवडा। (1) अ (2) 85-86 (3) 10,52,900/10,52,900 (4) 15,318 (5) 15,318।
128. श्रीमती मेनार्ई पी. सुराना, पांडरकवडा। (1) अ (2) 85-86 (3) 13,36,400/13,36,400 (4) 23,843 (5) 23,843।
129. श्री रत्नलाल मिश्रीमल सुराना, पांडरकवडा। (1) अ (2) 85-86 (3) 10,80,400/10,80,400 (4) 16,163 (5) 16,163।

[क्र. सं. वसूली/ 287/42 ए / 86-87]

टी. एस. श्रीनिवासन,
प्रायकर आयुक्त

S.O.2513—Following is the list of persons who have been assessed on net Wealth over Rs. 10 Lakhs during the Financial Year 1985-86 indicating (i) Status 'I' for individuals and 'H' for HUFs, 'AOP' for Association of persons and 'T' for Trusts (ii) Asstt. Year (iii) for Wealth returned/wealth assessed (iv) for tax payable by the assessee (v) Tax paid by the assessee.

SCHEDULE

1. Smt. Chandadevi Saraf (Late) L/H Shri Govindas Agrawal, Nagpur (i) I (ii) 81-82 (iii) 28, 47, 100 28,24,434 (iv) 94,271 (v) 91,542.
2. Smt. Swarnlatadevi Saraf, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 11,31,500/12,85,953 (iv) 20,520 (v) 20,529.
3. Smt. Chhayadcyi Saraf, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 11,21,157/12,11,063 (iv) 20,081 (v) 20,081.
4. Smt. Nishadevi Saraf Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 10,99,800/10,98,118 (iv) 16,693 (v) 16,253.
5. Shri Manojkumar Saraf, Tumsar. (i) I (ii) 81-82 (iii) 10,37,000/10,54,475 (iv) 15,385 (v) 15,385.
6. Late Smt. Godawaridevi Saraf, L/H Shri Durgaprasad Saraf, Tumsar. (i) I (ii) 81-82 (iii) 9,92,100/10,73,610 (iv) 15,598 (v) 13,060.

7. Shri Anurang Tarang Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 84-85 (iii) 21,95,885/21,31,100 (iv) 63,935 (v) 63,935.
8. Shri Anurang Tarang Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 22,47,250/21,81,800 (iv) 65,454 (v) 65,454.
9. Shri Anurang Tarang Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 82-83 (iii) 23,48,457/22,80,100 (iv) 68,402 (v) 68,402.
10. Shri Sunayana Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 84-85 (iii) 21,90 189/21,87,800 (iv) 65,634 (v) 65,634.
11. Shri Sunayana Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 21,10,934/21,07,000 (iv) 63,210 (v) 63,210.
12. Shri Sunayana Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 82-83 (iii) 22,32,598/22,31,000 (iv) 66,131 (v) 66,931.
13. Shri Sunayana Trust Wardha. (i) AOP (ii) 81-82 (iii) 13,42,054/13,26,300 (iv) 39,788 (v) 39,788.
14. Shri Kumud Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 1984-85 (iii) 19,10,209/19,11,600 (iv) 57,347 (v) 57,347.
15. Shri Kumud Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 12,54,677/12,38,900 (iv) 37,167 (v) 37,167.
16. Shri Kumud Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 82-83 (iii) 16,60,600/16,57,200 (iv) 49,715 (v) 49,715.
17. Shri Kumud Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 81-82 (iii) 22,86,700/22,86,200 (iv) 68,587 (v) 68,587.
18. Shri Kushagra Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 84-85 (iii) 20,03,764/19,45,400 (iv) 58,362 (v) 58,362.
19. Shri Kushagra Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 18,43,381/17,93,500 (iv) 53,806 (v) 53,806.
20. Shri Kushagra Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 82-83 (iii) 20,25,080/19,66,100 (iv) 58,983 (v) 58,983.
21. Shri Sanjivnayan Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 81-82 (iii) 15,05,600/15,36,900 (iv) 44,767 (v) 44,767.
22. Shri Sanjivnayan Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 82-83 (iii) 23,60,000/23,61,900 (iv) 71,845 (v) 71,845.
23. Shri Sanjivnayan Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 22,68,300/22,69,400 (iv) 68,082 (v) 68,082.
24. Shri Sanjivnayan Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 84-85 (iii) 24,33,800/24,51,600 (iv) 76,330 (v) 76,330.
25. Smt. Vimladevi Bajaj Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 81-82 (iii) 12,92,600/13,24,200 (iv) 39,736 (v) 39,736.
26. Shri Ramkrishna Bajaj Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 84-85 (iii) 11,79,100/11,87,200 (iv) 35,617 (v) 35,617.
27. Shri Ramkrishna Bajaj Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 9,76,700/10,00,300 (iv) 30,010 (v) 30,010.
28. Shri Ramkrishna Bajaj Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 82-83 (iii) 14,12,800/14,41,700 (iv) 43,250 (v) 43,250.
29. Shri Ramkrishna Bajaj Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 81-82 (iii) 20,31,700/20,50,200 (iv) 61,507 (v) 61,507.

30. Shri Anant Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 10,24,900/10,09,200 (iv) 30,275 (v) 30,275.

31. Shri Minakshi Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 84-85 (iii) 12,97,600/13,14,900 (iv) 39,447 (v) 39,447.

32. Shri Minakshi Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 9,70,900/10,02,500 (iv) 30,074 (v) 30,074.

33. Shri Minakshi Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 82-83 (iii) 12,47,000/12,68,500 (iv) 38,056 (v) 38,056.

34. Shri Minakshi Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 81-82 (iii) 15,62,900/15,72,300 (iv) 47,169 (v) 47,169.

35. Shri Kamalnayan Bajaj, Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 84-85 (iii) 16,09,500/12,76,000 (iv) 38,281 (v) 38,281.

36. Shri Kamalnayan Bajaj Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 83-84 (iii) 11,26,700/11,32,600 (iv) 33,979 (v) 33,979.

37. Shri Kamalnayan Bajaj Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 82-83 (iii) 17,51,900/17,58,700 (iv) 52,760 (v) 52,760.

38. Shri Kamalnayan Bajaj Trust, Wardha. (i) AOP (ii) 81-82 (iii) 25,99,600/26,12,100 (iv) 84,355 (v) 84,355.

39. Shri Gwalddas Mohata, Hinghanghat. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 7,47,503/17,54,200 (iv) 41,460 (v) 8,700.

40. Shri Girdherdas Mohta, Hinghanghat. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 5,74,938/16,84,800 (iv) 37,988 (v) 5,280.

41. Shri Shishirkumar Bajaj, Wardha. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 94,10,000/94,80,600 (iv) 4,27,782 (v) 4,24,247.

42. Shri Shishirkumar Bajaj, Wardha. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 98,46,500/1,02,71,400 (iv) 4,67,321 (v) 4,46,223.

43. Shri Rahulkumar Bajaj, Wardha. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 1,83,24,900/1,84,72,200 (iv) 8,77,360 (v) 8,60,993.

44. Shri Rahulkumar Bajaj, Wardha. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 1,90,90,700/1,97,22,900 (iv) 9,39,897 (v) 9,08,288.

45. Shri Ramkrishna Bajaj, Wardha. (i) H (ii) 83-84 (iii) 51,95,500/55,57,600 (iv) 2,51,632 (v) 2,33,524.

46. Shri Ramkrishna Bajaj, Wardha. (i) H (ii) 84-85 (iii) 50,91,500/54,69,800 (iv) 2,47,192 (v) 2,23,328.

47. Shri Madhirkumar Bajaj, Wardha. (i) H (ii) 84-85 (iii) 26,08,300/28,76,200 (iv) 1,17,559 (v) 1,04,165.

48. Shri Shekharkumar Bajaj, Wardha. (i) H (ii) 84-85 (iii) 36,15,300/42,45,400 (iv) 1,86,022 (v) 1,54,514.

49. Shri Shekharkumar Bajaj, Wardha. (i) H (ii) 83-84 (iii) 33,41,100/38,77,000 (iv) 1,67,599 (v) 1,40,807.

50. Shri Anurang Jain, Wardha. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 14,00,000/17,36,500 (iv) 40,573 (v) 40,573.

51. Shri Anurang Jain, Wardha. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 12,43,500/12,53,400 (iv) 21,351 (v) 21,053.

52. Shri Tarang Jain, Wardha. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 12,82,200/15,70,600 (iv) 32,281 (v) 22,335.

53. Shri Tarang Jain, Wardha. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 12,44,390/14,20,700 (iv) 26,371 (v) 21,088.

54. Shri Girdhardas Mohta Higanghat. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 6,11,873/15,33,100 (iv) 30,403 (v) 6,946.

55. Shri Vinaykumar Mohta, Higanghat. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 5,74,596/10,08,500 (iv) 14,005 (v) 6,373.

56. Smt. Sarladevi Mohta, Higanghat. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 11,47,688/16,50,400 (iv) 36,270 (v) 24,172.

57. Smt. Suryakantadevi Mohta, Hinganghat. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 7,94,854/13,10,100 (iv) 23,052 (v) 12,135.

58. Smt. Shantadevi Mohta, Higanghat. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 8,78,429/12,74,400 (iv) 21,983 (v) 14,261.

59. Shri Ranchhoddas Mohta, Higanghat. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 5,10,064/11,09,700 (iv) 17,040 (v) 5,634.

60. Shri Arunkumar Mohta, Higanghat. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 9,40,456/12,29,400 (iv) 20,631 (v) 20,631.

61. Shri Gwalddas Mohta, Higanghat. (i) H (ii) 85-86 (iii) 7,34,871/13,52,600 (iv) 41,380 (v) 19,227.

62. Shri Girdhardas Mohta, Higanghat. (i) H (ii) 85-86 (iii) 5,06,639/11,82,380 (iv) 32,866 (v) 14,897.

63. Shri Gwalddas Mohta, Higanghat. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 7,29,774/15,96,900 (iv) 33,593 (v) 3,634.

64. Shri Ranchhoddas Mohta, Higanghat. (i) H (ii) 85-86 (iii) 5,47,663/10,20,400 (iv) 24,769 (v) 13,320.

65. Shri Hargovind Bajaj, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 8,70,725/10,68,200 (iv) 15,796 (v) 15,796.

66. Shri Gangabisan Bajaj, Nagpur (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 7,51,959/10,11,200 (iv) 14,086 (v) 14,086.

67. Smt. Zubedabai Abdullahbai, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 7,97,612/10,28,482 (iv) 14,180 (v) 14,180.

68. Smt. Zubedabai Abdullahbai, Nagpur. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 7,57,950/10,13,950 (iv) 13,754 (v) 13,754.

69. Smt. Zubedabai Abdullahbai, Nagpur. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 12,16,800/12,67,700 (iv) 21,148 (v) 21,148.

70. Smt. Zubedabai Abdullahbai, Nagpur. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 11,18,328/11,34,620 (iv) 17,240 (v) 17,240.

71. Smt. Sakinabai Yusufali, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 10,06,400/12,31,142 (iv) 20,082 (v) 20,082.

72. Smt. Sakinabai Yusufali, Nagpur. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 9,88,700/12,69,200 (iv) 21,190 (v) 21,190.

73. Smt. Sakinabai Yusufali, Nagpur. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 5,65,800/16,31,200 (iv) 33,635 (v) 33,635.

74. Smt. Sasinabai Yusufali, Nagpur. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 11,50,028/12,13,800 (iv) 15,977 (v) 19,577.

75. Shri Asagarali Hasanali, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 16,85,664/15,49,400 (iv) 31,220 (v) 31,220.
76. Smt. Ramadevi Ruiya, Nagpur. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 9,47,216/10,56,700 (iv) 15,451 (v) 12,443.
77. Shri A.Y. Khare, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 8,40,270/13,06,800 (iv) 22,955 (v) 1,760.
78. Shri A.Y. Khare, Nagpur. (i) 1 (ii) 82-83 (iii) 8,93,250/13,95,515 (iv) 25,615 (v) —
79. Shri A.Y. Khare, Nagpur. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 7,07,780/15,61,300 (iv) 31,815 (v) 7,750.
80. Shri Kanji Harilal Wegad, Umred. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 4,40,500/10,10,800 (iv) 14,074 (v) 10,953.
81. Shri Hemraj Harilal Wegad, Umred. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 3,31,800/10,70,400 (iv) 15,862 (v) 2,047.
82. Shri Maganlal Harilal Wegad, Umred. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 4,69,800/10,94,200 (iv) 13,877 (v) 3,413.
83. Shri Surendrakumar Agarwal, Nagpur. (i) H (ii) 81-82 (iii) 9,79,400/12,41,297 (iv) 14,730 (v) —
84. Shri Vijayprakash Kanoria, Nagpur. (i) H (ii) 81-82 (iii) 3,33,500/10,17,502 (iv) 19,310 (v) —
85. Shri Vijayprakash Kanoria, Nagpur. (i) H (ii) 82-83 (iii) 3,24,800/10,09,216 (iv) 19,081 (v) —
86. Smt. Chandrakala Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 5,44,500/12,12,292 (iv) 15,568 (v) —
87. Smt. Chandrakala Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 82-83 (iii) 6,07,000/12,72,970 (iv) 16,165 (v) —
88. Smt. Chandrakala Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 7,30,000/12,71,127 (iv) 13,687 (v) —
89. Smt. Chandrakala Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 7,84,000/13,35,980 (iv) 23,830 (v) —
90. Shri Bramhaprakash Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 5,16,900/11,33,069 (iv) 13,799 (v) —
91. Shri Bramhaprakash Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 82-83 (iii) 5,51,000/11,66,757 (iv) 14,065 (v) —
92. Shri Bramhaprakash Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 6,68,400/11,96,707 (iv) 12,674 (v) —
93. Shri Bramhaprakash Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 2,13,300/12,40,301 (iv) 13,099 (v) —
94. Shri Shivprakash Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 4,52,700/10,93,658 (iv) 13,315 (v) —
95. Shri Shivprakash Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 82-83 (iii) 4,93,600/11,33,368 (iv) 14,094 (v) —
96. Shri Shivprakash Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 6,06,400/14,01,016 (iv) 17,951 (v) —
97. Shri Shivprakash Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 5,08,000/10,70,854 (iv) 12,041 (v) —
98. Shri Ajayprakash Kanoria, Nagpur. (i) H (ii) 81-82 (iii) 5,59,500/11,61,676 (iv) 26,989 (v) —
99. Shri Ajayprakash Kanoria, Nagpur. (i) H (ii) 82-83 (iii) 6,36,776/12,92,852 (iv) 31,721 (v) —
100. Shri Ajayprakash Kanoria, Nagpur. (i) H (ii) 83-84 (iii) 6,30,900/12,00,160 (iv) 27,458 (v) —
101. Shri Surendrakumar Agarwal, Nagpur. (i) H (ii) 82-83 (iii) 9,84,700/12,40,437 (iv) 13,160 (v) —
102. Shri Surendrakumar Agarwal, Nagpur. (i) H (ii) 83-84 (iii) 9,83,500/12,48,596 (iv) 13,614 (v) —
103. Shri Beniprasad Kanoria, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) —/11,650/10,17,181 (iv) 14,264 (v) —
104. Shri Surendrakumar Agarwal, Nagpur. (i) H (ii) 84-85 (iii) 11,09,200/15,68,548 (iv) 24,711 (v) —
105. Smt. Radhabai S. Toshniwal, Akola. (i) 1 (ii) 82-83 (iii) 8,06,400/11,75,625 (iv) 19,028 (v) 19,020
106. Shri Ghisulal G. Bajaj, L/H Ramniranjan Bajaj, Telhara. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 9,12,518/13,22,165 (iv) 22,735 (v) NIL.
107. Shri Shyamsundar M. Kacholiya Navli. (i) H (ii) 83-84 (iii) 10,30,805/10,30,805 (iv) 14,675 (v) 14,675.
108. Shri Shyamsundar M. Kacholiya Navli. (i) H (ii) 84-85 (iii) 11,60,368/11,60,368 (iv) 18,562 (v) 18,562.
109. Smt. Gyarisbai M. Kacholia, Navli. (i) 1 (ii) 83-84 (iii) 10,61,109/10,61,109 (iv) 15,583 (v) 15,583.
110. Smt. Gyarisbai M. Kacholia, Navli. (i) 1 (ii) 84-85 (iii) 10,93,084/10,93,484 (iv) 16,553 (v) 16,553.
111. Shri Shyamsundar M. Kacholia, Navli. (i) H (ii) 85-86 (iii) 12,40,608/12,40,608 (iv) 21,430 (v) 21,430.
112. Smt. Nirmladevi Sikchi, Amraoti. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 12,96,900/12,06,900 (iv) 19,375 (v) 19,375.
113. Shri H. J. Kalantri, Amraoti. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 10,17,800/10,17,800 (iv) 13,860 (v) 13,860.
114. Shri R. R. Lahoti, Amraoti. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 11,67,785/11,84,285 (iv) 18,725 (v) 18,725.
115. Smt. Narayani R. Heda, Amraoti. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 13,52,400/13,52,400 (iv) 23,611 (v) 23,611.
116. Smt. Varshaben Prafulla Patel, Gondia. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 15,67,000/15,67,000 (iv) 32,105 (v) 32,105.
117. Smt. Padmadevi Buty, Civil Lines, Nagpur. (i) 1 (ii) 81-82 (iii) 10,43,200/10,43,200 (iv) 14,608 (v) 10,990.
118. Shri M. G. Patel, Chandrapur. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 14,22,507/16,21,367 (iv) 34,820 (v) 34,820.
119. Shri C. G. Patel, Chandrapur. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 13,59,066/13,35,256 (iv) 23,810 (v) 23,810.
120. Shri Raja C. Patel, Chandrapur. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 10,41,337/10,53,530 (iv) 15,370 (v) 15,370.
121. Smt. Lalitaben C. Patel, Chandrapur. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 15,98,667/15,45,959 (iv) 31,048 (v) 3,148.
122. Smt. Premila A. Munot, Yavatmal. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 11,93,915/11,93,915 (iv) 19,567 (v) 19,567.
123. Smt. Amita J. Munot, Yavatmal. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 11,88,300/11,88,300 (iv) 19,398 (v) 19,398.
124. Smt. Nandini D. Munot, Yavatmal. (i) 1 (ii) 85-86 (iii) 14,63,550/14,68,550 (iv) 27,806 (v) 27,806.

125. Smt. Gulabbai H. Munot, Yavatmal. (i) I (ii) 85-86 (iii) 12,49,060/12,49,060 (iv) 21,221 (v) 21,221.

126. Smt. Manik R. Munot, Yavatmal. (i) I (ii) 85-86 (iii) 12,81,600/12,81,600 (iv) 22,197 (v) 22,197.

127. Smt. Panchfulabai R. Surana, Pandharkawada. (i) I (ii) 85-86 (iii) 10,52,900/10,52,900 (iv) 15,318 (v) 15,318.

128. Smt. Mainabai P. Surana, Pandharkawada. (i) I (ii) 85-86 (iii) 13,36,400/13,36,400 (iv) 23,843 (v) 23,843.

129. Shri Ratanlal Mishrimal Surana, P'kawada. (i) I (ii) 85-86 (iii) 10,80,400/10,80,400 (iv) 16,163 (v) 16,163.

[No. Recy/287/42-A/86-87]

T. S. SRINIVASAN, Commissioner of Income Tax
Vidarbha : Nagpur.

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 31st August, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 2514.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 542 dated the 11th February, 1987, published in the Gazette of India dated the 28th February, 1987, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at pages 908 to 909,—

(i) in plot numbers to be acquired in village Gowari, for "29 to 70, 99 part" read "29 to 70, 98, 99 part";

(ii) in plot numbers to be acquired in village Pimpri, for 29 to 40" read "19 to 40".

[No. 43019/21/84-CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

मई दिवसी, 1 सितम्बर, 1987

शुद्धि-पत्र

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1987

शुद्धि-पत्र

का. आ. 2514.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 28 फरवरी, 1987 के पृष्ठ 907-908 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 542 तारीख 11 फरवरी, 1987 में,

1. उक्त अधिसूचना के पृष्ठ 907 पर—

(i) टिप्पण-1 में "रेखांक सं. सी -1 (ई) ii/जेजेमार्/363-986" के स्थान पर "रेखांक सं. सी -1 (ई) iii/जे.जे. थार/363-986" पढ़ें।

(ii) अनुसूची में क्र. सं. 3 के सामने स्तम्भ "क्षेत्र हेक्टरों में" की विद्यमान प्रविष्टि "192.67" के स्थान पर "129.67" पढ़ें।

2. उक्त अधिसूचना के पृष्ठ 908 पर—

(i) दूसरी पंक्ति में "भाग 16 भाग 18" के स्थान पर "भाग 16, भाग 17, भाग 18" पढ़ें।

(ii) पंक्ति 11 में, "भाग 1, 2, 3, भाग 4" के स्थान पर "भाग 1, 2, भाग 3, 4" पढ़ें।

(iii) पंक्ति 19 में "288/3, 289/3" के स्थान पर "288/3" पढ़ें।

(iv) पंक्ति सं. 21 में, "और प्लॉट संख्यांक 101" के स्थान पर "और गीशबरी ग्राम में प्लॉट सं. 101" पढ़ें।

(v) पंक्ति 22 के अन्त में, "6, 9 में से होकर" के स्थान पर "6, 7 में से होकर" पढ़ें।

(vi) पंक्ति 36 में "1230 और 218" के स्थान पर "230 और 218" पढ़ें।

[सं. 43019/21/84-सी. ए.]

समय सिंह, अधीक्षक सचिव

का. आ. 1515.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 28 फरवरी, 1987 के पृष्ठ 910 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 543, तारीख 11 फरवरी, 1987 में—

पृष्ठ 910 पर पंक्ति 2 में,

"उल्लिखित भूमि में कोयला" के स्थान पर "उल्लिखित भूमि में कोयला" पढ़ें।

पंक्ति 10 में,

"कनकट, सहडोल, के स्थान पर "कनकट, सहडोल" पढ़ें।

पंक्ति 11 में, "नियंत्रक, काउन्सिल हाउस" के स्थान पर "नियंत्रक, काउन्सिल हाउस" पढ़ें।

अनुसूची में "जिला सहडोल" के स्थान पर "जिला सहडोल" पढ़ें।

स्तम्भ 5 में "क्षेत्र एकड़ों में" के स्थान पर "क्षेत्र हेक्टरों में" पढ़ें।

क्रम संख्या 1 में,

ग्राम, तहसील तथा जिला स्तरों के नीचे "माहीमर", "मान्हेगढ़, तथा "बहडोल" के स्थान पर क्रमशः "नहीमर", "बांधवाड़", तथा सहडोल" पढ़ें। और जहां कहीं भी "मान्हेगढ़ तथा सहडोल" शब्द प्रयुक्त हुए हों उन्हें "बांधवाड़ तथा सहडोल" पढ़ें।

क्रम संख्या 3 में,

ग्राम स्तर के नीचे "बिलारिकोव" के स्थान पर "बिलारिकोव" पढ़ें।

क्रम संख्या 8 में,

ग्राम स्तर के नीचे "गुटुर 6" के स्थान पर "गुटुरा" पढ़ें।

सीमा वर्णन में—

रेखांक-अ में "नाहपुर", "बांधवाड़" और "माहीमर" के स्थान पर क्रमशः "लानपुर", "बांधवाड़" और "माहीमर" पढ़ें।

रेखांक-ग में "कोडीमर", "मिलारिकोव", डेगडवाला तथा "छोटा ग्राम" के स्थान पर क्रमशः "महियार", "बिलारिकोव", "डेगडवाला" तथा "कोटा ग्राम" पढ़ें।

रेखा ग--घ में "ग्राम कोटा" तथा "डेगरनाला" के स्थान पर क्रमशः "ग्राम कोटा" तथा "डेगरनाला" पढ़ें।

रेखा ड--क में, "बिलरिकोप" और "जालपुर" के स्थान पर "बिलारिकोप" और "जालपुर" पढ़ें।

[नं. 43015/23/86--सी ए]

New Delhi, the 1st September, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 2515:—In the notification of the Government of India, Ministry of Energy, Department of Coal S. O. No. 543 dated the 11th February, 1987 published in the Gazette of India, part II, section 3, sub-section (ii) dated the 28th February, 1987 at pages 910-911,—

at page 911, in the Schedule

(1) in serial No. 3 for "Bilerikop"

read "Bilarikop"; and

under the boundary description heading,—

in line A-B for "point in village Lalpur"

read point 'A' in village Lalpur";

and

in line C-D for "Bandna-Putpura"

read "Bandha-Putpura".

[No. 43015/23/86-CA]

का. आ. 2516:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाययुक्त भूमि में उन्निहित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है:

अतः केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोयले का पर्वक्षण करने के अपने प्राणय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1 (ई)/III जे. आर. / 392-0687, तारीख 11 जन, 1987 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व विभाग) कोल एस्टेट मिनिंग लाइम्स, नागपुर--440001 के कार्यालय में या कलक्टर चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में प्रत्यक्ष कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितयुक्त सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नगरों, बाटों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पच्चे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, चेरटन कोलफील्ड्स लि., कोल एस्टेट मिनिंग लाइम्स, नागपुर--440001 को भेजेंगे।

अनुसूची

बिकर--चिचोली अनाक

चन्द्रपुर क्षेत्र

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

पर्वक्षण के लिए अधिसूचित भूमि

क. सं. ¹	ग्राम का नाम	पटवारी तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियाँ
1.	बिकर (स्टेशन)	बिकर	राजुरा चन्द्रपुर	621.91	भाग
2.	सुबे	बिकर	राजुरा चन्द्रपुर	740.27	भाग
3.	चिचोली जुझक	घनौरा	राजुरा चन्द्रपुर	1744.33	भाग
4.	कवितपेठ	घनौरा	राजुरा चन्द्रपुर	942.13	पूर्ण
5.	घनौरा	घनौरा	राजुरा चन्द्रपुर	1284.79	पूर्ण

कुल क्षेत्र : 5333.43 हेक्टर (लगभग)

या

13179.44 एकड़ (लगभग)

सीमा बणन

क--ख

रेखा दक्षिण मध्य रेल की पूर्वी दिशा के बिन्दु "क" से आरंभ होती है और ग्राम बिकर स्टेशन में से होकर जाती है, तब घनौरा और सिन्धा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और वर्धा नदी के मध्य में बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख--ग

रेखा घनौरा, कवितपेठ और चिचोली जुझक ग्रामों की बाहरी सीमा के साथ-साथ वर्धा नदी में से होकर जाती है और नदी की दिशा में बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग--घ

रेखा अन्तरगांव और चिचोली जुझक ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और दक्षिण मध्य रेल की पूर्वी सीमा पर बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ--क

रेखा दक्षिण मध्य रेल की पूर्वी सीमा की अर्जित की गई भूमि के साथ-साथ चिचोली जुझक, सुबेग्राम और बिकर स्टेशन में से होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/13/87--सी. ए.]

समय सिंह, अवर सचिव

S.O. 2516.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan bearing No. C-1(E)/III/JR/392-0687 dated the 11th June, 1987 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 or at the office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act

to the Revenue Officer, Western Coalfields, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification.

THE SCHEDULE
WIRUR-CHINCHOLI BLOCK
CHANDRAPUR AREA
DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

Sl. No.	Name of village	Patwari saza.	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wirur (Station)	Wirur (Station)	Rajura	Chandrapur	621.91	Part
2.	Subai	Wirur (Station)	Rajura	Chandrapur	740.27	Part
3.	Chincholi Buzruk	Dhanora	Rajura	Chandrapur	1744.33	Part
4.	Kavitpeth	Dhanora	Rajura	Chandrapur	942.13	Full
5.	Dhanora	Dhanora	Rajura	Chandrapur	1284.79	Full

Total area : 5333.43 hectares (approximately), or 13179.44 acres (approximately).

Boundary description :

A-B : Line starts from point 'A' on the eastern side of Soth Central Railway and passes through village Wirur Station then proceeds along the common boundary of villages Dhanora and Sindhi and meets at mid-stream of Wardha River at point 'B'.

B-3 : Line passes through River Wardha along the outer boundary of villages Dhanora, Kavitpeth and Chincholi Buzruk and meets at the down stream at point 'C'.

C-D : Line passes along the common boundary of villages Antargaon and Chincholi Buzruk and meets on the Eastern boundary of South Central Railway at point 'D'.

D-A : Line passes through villages Chincholi Buzruk, Subai and Wirur Station along the Eastern boundary of South Central Railway acquired land and meets on the starting point at 'A'.

[No. 43015/13/87-CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूच नं. 119 से जी. जी. ऐस. V तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : भरुच	तालुका : अंकलसर		
गांव	क्रांक नं.	हेक्टेयर	ग्राम.	सेन्टीग्र
सरपात	308	0	23	40

[सं. O-12016/5/87-ओ. एन. जी. -बी. -4]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1987

का. आ. 2517.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 534 तारीख 6-2-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 31st August, 1987

S.O. 2517.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 534 dated 6th February, 1987 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 119 to to G.G.S. 5.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Sarthar	308	0	23	40

[No. O-12016/5/87-ONG-D4]

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1987

का० जा० 2518—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का० जा० सं० 962 तारीख 25-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी० एल० एच० एच० (बी० 33) से बंगाल जी० जी० एस० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य :	गुजरात	जिला	ख	तालुका	मेहसाना
गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	घर०		सेन्टीयर
मीठा	400/1	0	03		84

[सं० O-12016/26/87-अं० एन० जी० डी०-4]

New Delhi, the 31st August, 1987

S.O. 2518.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 962 dated 25-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from BLHH (B-33) to Balol GGS

Stat : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Mitha	400/1	0	03	84

[No. O-12016/26/87-ONG-4]

का० जा० 2518—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग की अधिसूचना का० जा० सं० 311 तारीख 20-1-1987 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एंगोमेट ६० एफ० (एम० से एन० के० से होते हुए) एम० एम० सी० टो०एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका :	मेहसाणा	
गांव	गव्हे नं०	हेक्टेयर	अर०	सेन्टीयर
कसलपुरा	940	0	03	60
	कार्ट ट्रैक	0	01	20
	827	0	10	44
	826	0	08	88
	831	0	01	44
	832	0	03	00

[सं० O-12016/3/87-ओ०एन०जी०डी०-4]

S.O. 2519.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 311 dated 20-1-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNBF to (Via SNK) S.S. CTF i.e. N.E. corner S.S.CTF.

State : Gujarat	District : Mehsana Taluka : Mehsana			
Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
Kasalpura	940	0	03	60
	Cart track	0	01	20
	827	0	10	44
	826	0	08	88
	831	0	07	44
	832	0	03	00

[No. O-12016/3/87-ONG-D.4]

का०आ० 2520.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०आ०सं० 4515 तारीख 9-12-86 द्वारा केन्द्रीय सरकारने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः संश्लेष अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजह से और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

इसने ने पक्के तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : भरुच	तालुका :	वाघरा	
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	अर०	सेन्टीयर
अटासी	275	0	25	00
	274	0	08	00
	276	0	00	08
	271	0	34	00
	270	0	12	00
	240	0	37	00
	241/ए	0	28	00
	242	0	20	00
	243/बी	0	05	00
	343/ए	9	00	32
	247/ए	0	07	00
	239	0	00	16

[सं० O-12016/215/86 अर०एम०जी०डी०-4]

S.O. 2520.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 4515 dated 9-12-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen-

tral Government vests on this date of the publication of declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe line from Dahej to Palej

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Wagara

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centiare
Atali	275	0	25	00
	274	0	08	00
	276	0	00	08
	271	0	34	00
	270	0	12	00
	240	0	37	00
	241/A	0	28	00
	242	0	20	00
	243/B	0	05	00
	243/A	0	00	32
	247/A	0	07	00
	239	0	00	16

[No. O-12016/215/86-ONG-D4]

कां.आ. 2521.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बी०एन०एच डब्ल्यू (40) से बलोल जी०जी०एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपराप्त अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग) के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तनशक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बड़ोदरा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ;

अनुसूची

बी० ए० ग्ल० एच० डब्ल्यू० (40) से बलोल जी०जी०एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य	गुजरात	जिला व तालुका	मेहसाणा
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर० सेन्टीयर
बलोल	822/2	0	02 40
	822/1	0	06 72
	803	0	07 68
	850/2	0	06 36
	879	0	04 92
	887	0	12 00
	895	0	03 36
	898	0	06 12
	899	0	15 60

[सं० O 12016/62/87 ओ०एन०जी०सी०-4]

S.O. 2521.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from BLHW(40) to BALOL GGS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from BLHW (40) to Balol GGS.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
Balol	822/2	0	02	40
	822/1	0	06	72
	803	0	07	68
	850/2	0	06	36
	879	0	04	92
	887	0	12	00
	895	0	03	36
	898	0	06	12
	899	0	15	60

[No. O-12016/62/87-ONG-D-4]

का.आ. 2522.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम० एम. डी० आ० से एम० एन० डी० आर० उपस्थान तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपराप्त अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग) के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तनशक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बड़ोदरा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एस० एन० डी० सी० में एस० एन० डी० आर० से उत्तर संथाल तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला व तालुका मेहसाणा

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर०	सेन्टीयर
बलोल	1626	0	03	72
	1406	0	09	00
	1407	0	06	60
	1408	0	01	92

[सं० O-12016/64/87-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2522.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from S.N.D.O. to S.N.D.R. to North Santhal Gas in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNDO to STDR to North Santhal GGS

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Balol	1626	0	03	72
	1406	0	09	00
	1407	0	06	60
	1408	0	01	92

[No. O-12016/64/87-ONG-D. 4]

का०आ० 2523:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गजेरा-1 से डबका जी०सी०एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये, पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के लिये पाइपलाइन बिछाने के लिए आशय राक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशय करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

गजेरा-1 से डबका जी० सी० एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला भरुच तालुका : जंबुसर

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	आर०	सेन्टीयर
गजेरा	1403	0	17	40
	1401	0	00	90
	1391	0	15	30
	1682	0	04	50

[सं० O-12016/65/87-ओ० एन०जी०डी० 4]

S.O. 2523.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gajera-1 to Dabaka Gas in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Gajera-1 to Dabaka GCS.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Gajera	1403	0	17	40
	1401	0	00	90
	1391	0	15	30
	1682	0	04	50

[No. O-12016/65/87-GNOD-4]

का०आ० 2524:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन० एन० ए०सी० लिब-1 ई० से०पी० एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में निम्नलिखित कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई प्रविणत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एम्. एन. एम. सी. में लिख-1 ई. पी. एम. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा

गाँव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	अरे०	सेन्टीयर
मुदरडा	392	0	04	08
	356	0	08	40
	358	0	06	24
	384	0	06	24
	383	0	06	00
	382	0	05	04
	379	0	12	12
	371	0	14	16
	369	0	13	08
	347	0	05	04
	346	0	07	08
	341	0	09	60
	342	0	08	88
	343	0	00	48
	334	0	03	72
	324	0	09	00
	325	0	13	32
	322	0	06	34
	321	0	08	40
	320	0	03	60

[मं० O-12016/64/87-आर०एम०जी०डी० 4]

S.O. 2524.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from LNAB to LINCH-1 F.P.S. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from LNAB to LINCH-1 EPS

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hactare	Ac	Centiare
Mudarda	392	0	04	08
	356	0	08	40
	358	0	06	24
	384	0	06	24
	383	0	06	00
	382	0	05	04
	379	0	12	12
	371	0	14	16
	369	0	13	08
	347	0	05	04
	346	0	07	08
	341	0	09	60
	342	0	08	88
	343	0	00	48
	334	0	03	72
	324	0	09	00
	325	0	13	32
	322	0	06	34
	321	0	08	40
	320	0	03	60

[No. O-12016/64/87-ONG-D-4]

का. आ. 2525—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन, अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 3535 तारीख 26-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उन धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी वापसों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गंधार से परवाजन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात

जिला: भरुच तालुका: वागरा

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टी- यर
1	2	3	4	5
मुलेर	197	0	36	00
	198	0	00	30
	196	0	20	00
	214	0	34	00
	191	0	24	00
	187/ए	0	00	70
	190	0	27	60
	188	0	06	60
	189	0	16	00
	176	0	06	80
	247	0	11	00
	248	0	04	60
	249	0	00	15
	250	0	06	00
	253	0	10	00
	279	0	27	20
	273	0	24	40
	270	0	11	60
	269	0	04	00
	271	0	04	20
	272	0	04	50
	267	0	24	00
	266	0	03	40
	काट्टेक	0	04	00
	469	0	03	20
	470/बी	0	54	60
	552	0	16	00
	551	0	16	00
	109	0	14	00
	556	0	26	40
	360	0	6	00
	424	0	16	00
	3	0	31	00
	44	0	36	00
	5	0	29	00
	6/पी	0	29	00
	7	0	32	25
	11	0	29	00
	10	0	26	00
	63	3	06	00

[सं O-12016/153/86-ओ एन जी.-डी 4)]

S.O. 2525.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3535 dated 26-9-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

87/1035 GI—5.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from gandhar to Pakhajan

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Wagara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Muler	197	0	36	00
	198	0	00	30
	196	0	20	00
	214	0	34	00
	191	0	24	00
	187/A	0	00	70
	190	0	27	60
	188	0	06	60
	189	0	16	00
	176	0	06	80
	247	0	11	00
	248	0	03	60
	249	0	00	15
	250	0	06	00
	253	0	10	00
	279	0	27	20
	273	0	24	40
	270	0	11	60
	269	0	04	00
	271	0	04	20
	272	0	04	50
	267	0	24	00
	266	0	03	40
	Lart track	0	04	00
	469	0	03	20
	470/B	0	54	60
	552	0	16	00
	551	0	16	00
	109	0	14	00
	556	0	26	40
	360	0	6	00
	424	0	16	00
	3	0	31	00
	44	0	36	00
	5	0	29	00
	6/p	0	29	00
	7	0	32	25
	11	0	29	00
	10	0	26	00
	63	3	06	00

[No. O-12016/153/86-ONG-D. 4]

का. आ. 2526:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ०सं० 4213 तारीख 9-12-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कलोल-392 से जी०जी०एस० III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात तालुका: कलोल जिला: मेहसाना

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
वडास्वामी	340	0	06	30
	341	0	06	90
	339	0	20	25
	335	0	16	40
	333	0	10	50
	334	0	08	60

[सं० O-12016/206/86-ओ एन जी-डी 4]

S.O. 2526.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 4213 dated 9-12-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead

of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Kalol-392 to GGS III-Kalol.

State : Gujarat Taluka : Kalol District : Mehsana.

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Wadawaswami	340	0	06	30
	341	0	06	90
	339	0	20	25
	335	0	16	40
	333	0	10	50
	334	0	08	60

[No. O-12016/206/86/ONG-D-4]

का०आ० 2527-यतः पेट्रोलियम और खनिजपाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ०सं० 4207 तारीख 9-12-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के-387 से जी०जी०एस० IV तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला: मेहसाना तालुका कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
शुलासन	962	0	07	30
	961	0	07	50

[सं० O-12016/210/86-ओ एन जी-डी 4]

S.O. 2527.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 4207 dated 9-12-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962),

the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from K-387 to GGS VI.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centi-are
1	2	3	4	5
Zhulasan	962	0	07	30
	961	0	07	50

[No. O-12016/210/86-ONG-D-4]

का.आ. 2528-पत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना कां०आ०सं० 2991 तारीख 11-8-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में सभ्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन के निम्न अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सभ्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सभ्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सभ्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विधान के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्न दर्शाती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजह से और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी वातावरण से स्वतः रूप से, बोधगम्य में प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

उत्तका जी०सी०००एम० ग सरसावती तक पाइप लाइन विधान के लिये।

राज्य गुजरात जिला: बड़ोदा तालुका: पादरा

गांव	ब्लॉक नं	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
राजूपुरा	156	0	03	92
	158	0	04	88
	159	0	02	10
	160	0	02	00
	161	0	03	84
	174	0	10	06
	175	0	04	80
	176	0	03	50

[नं O-12016/125/86-ओ एन जी -डी-4]

S.O. 2528.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2991 dated 11-8-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Dabka GCS to Sarsawan

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centi-are
1	2	3	4	5
Rajupura	156	0	03	92
	158	0	04	98
	159	0	02	40
	160	0	02	00
	161	0	03	84
	174	0	10	06
	175	0	04	80
	176	0	03	50

[No. O-12016/125/86-ONG-D-4]

का.आ. 2529.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ.सं. 773 तारीख 11-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.एन.डी.बी. (एस-104) में (एस-60) में पुराने ग्रार.आ.पू. से एस.एन.डी.बी. से एस.एम.सी.टी.एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे न.	हेक्टेयर	आर.	सेटीयर
सयाल	814	0	01	08
	813	0	08	28
	810	0	14	52
	808/1	0	03	96
	807/2	0	04	80
	807/1	0	07	32
काटे ट्रैक		0	00	72
	806	0	01	20

[म. O-12016/20/87-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2529.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O.No. 773 dated 11-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipe line.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And further in exercise of exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNDB (S-104) to (S-60) to Old ROU from SNBO to S.S. CTF.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana.

Village	Survey No.	Hectare	Arc	Centi-are
1	2	3	4	5
Santhal	814	0	01	08
	813	0	08	28
	810	0	14	52
	808/1	0	03	96
	807/2	0	04	80
	807/1	0	07	32
	Cart track	0	00	72
	806	0	01	20

[No. O-12016/20/87-ONG-D4]

का.आ. 2530.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ.सं. 776 तारीख 11-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.एन.सी.आई. से एस.एन.ए.सी.एफ. से पुराने ग्राम. आ. य.

से सी.टी. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला व तालुका : मेहसाना				
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेटीयर	
कसलपुरा	608	0	04	92	
	607	0	11	76	
	601	0	03	72	

[सं. O-12016/23/87-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2530.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 776 dated 11-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNCI to SNCF to Old ROU to CTF.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana.

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-ar	
1	2	3	4	5	
Kasalpura	608	0	04	92	
	607	0	11	76	
	601	0	03	72	

[No. O-12016/23/87-ONG-D4]

का.आ. 2531.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्जन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2880 तारीख 25-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइन का बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और याः सन 1987 में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्जन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और और, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है।

और और उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और रासायनिक गैस आयोग में, सभी शर्तों के मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

इक्का जी सी एस. से सरसावती तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : बड़ोदरा	तालुका : पादरा			
गांव	संक्षेप नं.	हेक्टेयर	आर.	सेटीयर	
1	2	3	4	5	
सांभा	कार्ट ट्रेक	0	01	60	
	699	0	07	28	
	700	0	06	08	
	701	0	06	72	
	702/2	0	03	20	
	702/1	0	02	90	
	703	0	00	25	
	706	0	10	40	
	688	0	06	88	
	687	0	01	20	
	707	0	00	25	
	कार्ट ट्रेक	0	01	20	
	791/1	0	06	00	
	795	0	05	60	
	796	0	04	16	
	1504	0	01	28	
	797	0	03	20	
	789/1	0	07	50	
	806/ए	0	06	00	
	807	0	04	80	
	775	0	09	28	
	773	0	02	88	
	कानस	0	01	28	
	816	0	01	60	
	812	0	07	04	
	813	0	00	25	
	593	0	01	60	
	595	0	03	20	
	594	0	05	30	
	590	0	04	80	
	589/2	0	04	00	
	कार्ट ट्रेक	0	00	96	
	491	0	00	25	
	499	0	09	60	
	500	0	01	60	

1	2	3	4	5
	498	06	06	10
	497	03	03	28
	496	01	01	60
	495	04	04	00
	कार्ट ट्रैक	00	00	00

[सं. O-12016/113/86-आ.एन.जी.-डी-4]

S.O. 2531.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2880 dated 25-7-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Dabka G.C.S. to Sarswani		State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Mobha	Carttrack	0	01	60
	699	0	07	28
	700	0	06	08
	701	0	06	72
	702/2	0	03	20
	702/1	0	02	90
	703	0	00	25
	706	0	10	40
	688	0	06	88
	687	0	01	20
	707	0	00	25
	Cart track	0	01	20
	791/1	0	06	00
	795	0	05	60
	796	0	04	16
	1504	0	01	28
	794	0	03	20
	780/1	0	07	50
	806/A	0	06	00
	807	0	04	80
	745	0	09	28
	773	0	02	88
	Kans	0	01	28
	816	0	01	60
	812	0	07	04

1	2	3	4	5
	813	0	00	25
	593	0	01	60
	595	0	03	20
	594	0	08	80
	590	0	04	80
	589/2	0	04	00
	Cart track	0	00	96
	491	0	00	25
	499	0	09	60
	500	0	01	60
	498	0	06	40
	497	0	03	28
	496	0	01	60
	495	0	04	00
	Cart Track	0	00	80

[No. O-12016/113/86-ONG-D4]

का.आ. 2532.—यत्. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2993 तारीख 11-8-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आणख घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत्. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस आरा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेज और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डबका जी.सी.एन. स. गणराज्य तथा पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य गुजरात जिला पड़रदा तालुका पादरा				
गांव	ब्लॉक नं.	हैक्टेयर	ग्रा. सटीयर	सटीयर
मरमावनी	969	0	01	52
	968	0	06	00
	967	0	05	68
	966	0	01	00
	1934	0	00	91
	965	0	04	83
	963	0	04	76
	962	0	00	96
	931	0	12	60

[सं. O-12016/123/86-ओ एन जी डी-4]

S.O. 2532—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2993 dated 11-8-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from DABKA GCS to Sarswani

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Sarswani	969	0	01	52
	968	0	06	00
	967	0	05	68
	966	0	04	00
	1934	0	00	91
	965	0	04	88
	963	0	04	76
	962	0	00	96
	981	0	13	60

[No. O-12016/123/86-ONG-D4]

का.आ. 2533.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2989 तारीख 11-8-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डबका जी.सी.एम. से सरसावनी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : पादरा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
अंती	25/1	0	09	68
	26	0	03	76
	28	0	04	64
	29	0	02	08
	30	0	02	16
	31	0	04	24
काटें ट्रेक		0	01	40
61/2		0	05	44
60/1/ए		0	02	40
66/6		0	00	80
66/2-3-4-5		0	02	64
66/1		0	01	60
57/8		0	00	25
57/1/ए		0	06	08
काटें ट्रेक		0	00	96
68		0	05	60
452/1		0	03	00
450		0	04	64
451/2		0	00	64
448/1		0	03	92
446/2		0	03	60
446/1		0	03	36
445		0	05	36
440		0	04	50
441		0	00	50
442/1		0	04	80
काटें ट्रेक		0	01	60
428/1		0	01	40
427/2		0	05	20
427/1		0	06	15
काटें ट्रेक		0	00	40
419/2		0	06	64
काटें ट्रेक		0	01	20
343		0	06	08
344		0	07	68
काटें ट्रेक		0	00	40
408		0	09	60
407		0	04	80
406		0	06	25
357		0	09	12
355/1		0	08	00
355/2		0	00	56
354		0	13	92
369		0	03	60
370/2		0	04	64

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
एन्टी	370/1	0	04	80		441	0	00	50
	371	0	06	40		442/1	0	04	80
	374/3	0	10	48		Cart track	0	01	60
कानस		0	00	40		428/1	0	01	40

[सं. O-12016/128/86-ओ एन जी सी-4]

S.O. 2533.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2998 dated 11-8-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government :

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline :

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from DABAKA GCS to Sarswani.

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Anti	25/1	0	09	68
	26	0	03	76
	28	0	04	64
	29	0	02	08
	30	0	02	16
	31	0	04	24
	Cart track	0	01	40
	61/2	0	05	44
	60/1/A	0	02	40
	66/6	0	00	80
	66/2+3+	0	02	64
	4+5			
	66/1	0	01	60
	57/8	0	00	25
	57/1/A	0	06	08
	Cart track	0	00	96
	68	0	05	60
	452/1	0	03	00
	450	0	04	64
	451/2	0	00	64
	448/1	0	03	92
	446/2	0	03	60
	446/1	0	03	36
	445	0	05	36
	440	0	04	50

1	2	3	4	5
	441	0	00	50
	442/1	0	04	80
	Cart track	0	01	60
	428/1	0	01	40
	427/2	0	05	20
	427/1	0	06	16
	Cart track	0	00	40
	419/2	0	06	64
	Cart track	0	01	20
	343	0	06	08
	344	0	07	68
	Cart track	0	00	40
	408	0	09	60
	407	0	04	80
	406	0	06	25
	357	0	09	12
	355/1	0	08	00
	355/2	0	00	56
	354	0	13	92
	369	0	03	60
	370/2	0	04	64
	370/1	0	04	80
	371	0	06	40
	374/3	0	10	48
	Kans	0	00	40

[No. O-12016/28/86-ONG-D4]

का.प्र. 2534—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्र.सं. 2771 तारीख 25-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था।

और यतः मन्त्रम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डबका जी.सी.एम. से सरसावनी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : बड़ोदरा	तालुका : पादरा		
गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटोयर
1	2	3	4	5
जलाखपुर	476	0	06	40
	477	0	06	40

1	2	3	4	5
जलालपुर	कार्ट ट्रैक	0	01	68
	489	0	01	60
	488	0	03	20
	490	0	04	40
	490	0	03	60
	493	0	04	48
	494	0	06	32
	496	0	07	60
	कार्ट ट्रैक	0	00	50
	497	0	00	58
	498	0	05	60
	499	0	02	08
	510	0	12	80
	509	0	01	20
	कार्ट ट्रैक	0	00	80
	11	0	09	52
	63	0	10	40
	क.ट.ट्रैक	0	00	25
	62/पी	0	10	72
	61	0	04	56
	60	0	05	00
	59	0	04	00
	58	0	00	80
	135	0	08	00
	136	0	08	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	56
	137	0	03	20
	139	0	09	80
	140	0	02	08
	160	0	00	96
	159	0	04	48
	158	0	06	08
	157	0	04	52
	156	0	09	44
	153	0	03	12
	152	0	07	20

[सं. O-12016/115/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2534.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2771 dated 25-7-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs 87/1035 GI-6.

that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Dabka G.C.S. to Sarsawani.

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centi-are
1	2	3	4	5
Jalalpur	476	0	06	40
	477	0	06	40
	Cart track	0	01	68
	489	0	01	60
	488	0	03	20
	490	0	04	40
	490	0	03	60
	493	0	04	48
	494	0	06	32
	496	0	07	60
	Cart track	0	00	50
	497	0	00	68
	498	0	05	60
	499	0	02	08
	510	0	12	80
	509	0	01	20
	Cart track	0	00	80
	11	0	09	52
	63	0	10	40
	Cart track	0	00	25
	62/P	0	10	72
	61	0	04	56
	60	0	05	00
	59	0	04	00
	58	0	00	80
	135	0	08	00
	136	0	08	00
	Cart track	0	00	56
	137	0	03	20
	139	0	09	80
	140	0	02	08
	160	0	00	96
	159	0	04	48
	158	0	06	08
	157	0	04	52
	156	0	09	44
	153	0	03	12
	152	0	07	20

[No. O-12016/115/86-ONG-D-4]

का.आ. 2535.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की शर्त सूचना का.आ.सं. 2275 तारीख 22-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्टें दे दी हैं।

और आगे, यह: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी.जी.एस.-1 से जी.जी.एस-5

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका : कलोल		
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	घार.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
कलोल	252/311	0	06	08
	252/308	0	05	72
	252/307	0	08	36
	252/306	0	09	20
	कार्ट ट्रैक	0	01	12
	252/207/1	0	07	00
	252/207/2	0	06	84
	252/209/1	0	05	50
	252/216	0	00	65
	252/215/1	0	06	96
	कार्ट ट्रैक	0	01	28
	252/227	0	03	84
	252/231	0	04	64
	252/230/पी	0	09	92
	195	0	09	36
	194/1+2	0	00	80
	196	0	02	24
	177/1	0	11	72
	कार्ट ट्रैक	0	00	48
	176	0	08	16
	174/2	0	05	12
	174/1	0	03	20
	कार्ट ट्रैक	0	01	76
	72	0	00	80
	73	0	25	60
	75	0	01	33
	56	0	06	40
	58/2	0	05	24
	58/1	0	05	00
	59	0	08	32
	44	0	06	72

[सं. O-12016/78/86-ओ एन जी-डी-4]

sition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GGS I To GGS V.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Aro	Centi are
1	2	3	4	5
Kalol	252/311	0	06	08
	252/308	0	05	72
	252/307	0	08	36
	252/306	0	09	20
	Cart track	0	01	12
	252/207/1	0	07	00
	252/207/2	0	06	84
	252/209/1	0	05	50
	252/216	0	00	65
	252/215/1	0	06	96
	Cart track	0	01	28
	252/227	0	03	84
	252/231	0	04	64
	252/230/P	0	09	92
	195	0	09	36
	194/1+2	0	00	80
	196	0	02	24
	177/1	0	11	72
	Cart track	0	00	48
	176	0	08	16
	174/2	0	05	12
	174/1	0	03	20
	Cart track	0	01	76
	72	0	00	80
	73	0	25	60
	75	0	01	33
	56	0	06	40
	58/2	0	05	24
	58/1	0	05	00
	59	0	08	32
	44	0	06	72

[No O-12016/78/86-ONG-D-4]

S.O. 2535.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2275 dated 22-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqui-

का. आ. 2536—यह: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन बिल में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1982 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और

प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. मा. सं. 3733 तारीख 20-10-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राथम्य घोषित कर दिया था।

और यतः सलम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

झालोरा-22 से जी. जी. एस. झालोरा-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात जिला-मेहसाना, तालूका :-कडी

गांव	खंड नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
मनीपुर	173	0	15	00

[सं. O-12016/170/86-ओ.एन.जी.सी.-4]

S.O. 2536.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3733 dated 20-10-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Jhalora-22 to GGS Jhalora-I

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No	Hectare	Are	Centi-are
Manipur	173	0	15	00

[No O-12016/170/86-ONG-D4]

का. मा. 2537.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. मा. सं. 3862 तारीख 29-10-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राथम्य घोषित कर दिया था।

और यतः शम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कुप नं. वासना-7 से वासना-3 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात जिला-खेड़ा तालूका-मेहमवादा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
महीज	1240	0	04	50
	1227	0	10	35
	1256	0	17	70
	1255	0	01	50
	1273	0	09	00
	1274	0	06	60
	1275	0	18	00
	1277	0	06	30
	1278	0	20	50
	1292	0	18	45
	1296	0	10	65
	1294	0	06	30
	1312	0	12	30

[सं. O-12016/179/86-ओ.एन.जी.सी.-4]

S.O. 2537.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3862 dated 29-10-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And Further Whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No Wasna-7 to Wasna-3
State : Gujarat District : Kalra Taluka : Mehmabad

Village	Block No	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
abij	1240	0	04	50
	1227	0	10	35
	1256	0	17	70
	1255	0	01	50
	1273	0	09	00
	1274	0	06	60
	1275	0	18	00
	1277	0	06	30
	1278	0	20	50
	1292	0	18	45
	1295	0	10	65
	1294	0	06	30
	1312	0	12	30

[No. O—12016/179/86-ONG-D 4]

का. प्रा. 2538.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 4209 तारीख 9-12-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूखण्डों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूखण्डों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भूखण्डों में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

भूखण्ड

के-320 से जी. जी. एस. VIII तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य:—गुजरात जिला:—मेहसाणा तालुका:—कलोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
कलोल	19	0	16	80
	18/2	0	17	25
	18/1	0	01	50

ह./-

(सक्षम प्राधिकारी)

हुते गुजरात राज्य एरिया, वडोदरा

[सं. O—12016/208/86-ओ एन जी-सी.-4]

पो. के. राजगोपा न, डेस्क अधिकारी

S.O. 2538.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 4209 dated 9-12-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And Whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And Further Whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from K-320 to GGS VIII.
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Kalol	19	0	16	80
	18/2	0	17	25
	18/1	0	01	50

Sd/-

(Competent Authority)

for Gujarat State Area Vadodara

[No O—12016/208/86-ONG-D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer.

साद्य और नागरिक प्रमाणन संस्थान

(नागरिक प्रति विभाग)







भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1987

क्र० आ० 2539.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम (4) के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन मानक चिह्नों के डिजाइन उनके शाब्दिक तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, वे निर्यातित कर दिये गये हैं।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और इसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के निमित्त ये मानक चिह्न उनके सामने दी गई तिथियों से लागू होंगे:—

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न का डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.		सफेद पोर्टलैंड सीमेंट	IS 8042-1978 सफेद स्तम्भ पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	(2) में दिखाई गई निश्चित शैली और परस्पर सम्बद्ध अनुपात में "ISI" प्रत्यक्ष भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें भारतीय मानक की संख्या डिजाइन में दिखाये अनुसार मोनोग्राम के ऊपर अंकित हो।	1983-07-01
2.		क्विलेफास, तकनीकी	IS 8072-1975 क्विलेफास, तकनीकी की विशिष्टि	स्तम्भ (2) में दिखाई गई निश्चित शैली और परस्पर सम्बद्ध अनुपात में "ISI" प्रत्यक्ष भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें भारतीय मानक की संख्या डिजाइन में दिखाये अनुसार मोनोग्राम के ऊपर अंकित हो।	1983-04-16
3.		ब्यूटाक्लोर प्रेस्यूल	IS 9362-1980 ब्यूटाक्लोर प्रेस्यूल की विशिष्टि	यथोपरि	1983-11-18
4.		हायड्रोजन प्रेस्यूल	IS 9369-1980 हायड्रोजन प्रेस्यूल की विशिष्टि	यथोपरि	1984-08-18
5.		मिथाईल पैराथियोस सांद्र	IS 9372-1980 मिथाईल पैराथियोस की विशिष्टि	यथोपरि	1984-12-01
6.		ईथियोस तकनीकी	IS 10369-1982 ईथियोस तकनीकी की विशिष्टि	यथोपरि	1984-05-16

[सं० सी०एम०डी० 13: 8]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)







BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 25th August, 1987

S.O. 2539. —In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution Certification Marks Rules, 1955 Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s), design (s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each:

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the design of the Standard Mark	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		White portland cement	IS : 8042-1978 Specification for white portland cement (First revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being super-scribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1983-07-01
2.		Quinalphos, technical	IS : 8072-1975 Specification for quinalphos, technical	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being super-scribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1983-04-16
3.		Butachlor granules	IS : 9362-1980 Specification for butachlor granules.	—do—	1983-11-16
4.		Diazinon granules	IS : 9369-1980 Specification for diazinon granules	—do—	1984-08-16
5.		Methyl parathion technical concentrates	IS : 9372-1980 Specification methyl parathion technical concentrates	—do—	1984-12-01
6.		Ethion technical	IS : 10369-1982 Specification for ethion technical	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being Super-scribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1984-05-16

[No. CMD/13 : 9]

क्र० आ० 2840 :—भारतीय मानक संस्था प्रमाणन मुहर (विनियम (7) के उपविध (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की नीस अनुसूची में दिये गये व्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहरांकन फीस	प्रभाव की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	सफेद पोर्टलैंड सीमेंट	IS : 8042 1978 सफेद पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक टन	20 पैसे	1983-07-01

1	2	3	4	5	6
2. क्लिनेलकांस, तकनीकी	IS : 8072 1975 क्लिनेलकांस, तकनीकी की विधि	100 किग्रा०	1. रु० 20.00 प्रति इकाई, पहली 500 इकाइयों के लिए, 2. रु० 10.00 प्रति इकाई, 501 वीं इकाई से 1500 इकाइयों तक के लिए, और 3. रु० 2.00 प्रति इकाई, 1501-वीं इकाई और उससे अधिक के लिए	1983-04-16	
3. ब्यूटाक्लोरे प्रेन्स	IS : 9362 1980 ब्यूटाक्लोरे प्रेन्स की विधि	एक टन	1. रु० 10.00 प्रति इकाई, पहली 500 इकाइयों के लिए, 2. रु० 5.00 प्रति इकाई, 501 वीं इकाई से 1000 इकाइयों तक के लिए, और 3. रु० 2.00 प्रति इकाई, 1001 वीं इकाई और उससे अधिक के लिए	1983-11-16	
4. ज़ायज़िनॉन प्रेन्स	IS : 9369 1980 ज़ायज़िनॉन प्रेन्स की विधि	एक टन	1. रु० 30.00 प्रति इकाई, पहली 500 इकाइयों के लिए, 2. रु० 20.00 प्रति इकाई, 501 वीं इकाई से 1000 इकाइयों तक के लिए 3. रु० 10.00 प्रति इकाई, 1001 वीं इकाई और उससे अधिक के लिए	1984-08-16	
5. मिथाईल पैराथियॉन तकनीकी सांद्र	IS : 9372 1980 मिथाईल पैराथियॉन तकनीकी सांद्र की विधि	100 लीटर	1. रु० 10.00 प्रति इकाई, पहली 500 इकाइयों के लिए, 2. रु० 5.00 प्रति इकाई, 501 वीं इकाई से 1000 इकाइयों तक के लिए, और 3. रु० 3.00 प्रति इकाई, 1001 वीं इकाई और उससे अधिक के लिए	1984-12-01	
6. इंधियान तकनीकी	IS : 10369 1982 ई. थि-यान तकनीकी की विधि	100 किग्रा०	1. रु० 10.00 प्रति इकाई, पहली 500 इकाइयों के लिए, 2. रु० 5.00 प्रति इकाई, 501 वीं इकाई और उससे अधिक के लिए	1984-05-16	

[सं० सी०एम०डी०/13:10]
बी०एन० सिंह, अपर महानिदेशक

S.O. 2540 —In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking fee per unit	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	White portland cement	IS : 8042-1978 Specification for white portland cement (first revision)	One Tonne	20 Paise	1983-07-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Quinalphos, technical	IS : 8072-1975 Specification for quinalphos, technical	100 kg	(i) Rs. 20.00 per unit for the 1983-04-16 first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above	
3.	Butachlor granules	IS : 9362-1980 Specification for butachlor granules.	One Tonne	(i) Rs. 10.00 per unit for the 1983-11-16 the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1000 units and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1001st unit and above	
4.	Diazinon granules	IS : 9369-1980 Specification for diazinon granules	One Tonne	(i) Rs. 30.00 per unit for the 1984-03-16 first 500 units; (ii) Rs. 20.00 pr unit for the 501st to 1000 units and (iii) Rs. 10.00 per unit for the 1001st unit and above	
5.	Methyl parathion technical concentrates	IS : 9372-1980 Specification for methyl parathion technical concentrates.	100 litres	(i) Rs. 10.00 per unit for 1984-12-01 the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1000 units and (iii) Rs. 3.00 per unit for the 1001st unit and above.	
6.	Ethion technical	IS : 10359-1982 Specification for ethion technical	100 Kg	(i) Rs. 10.00 per unit for 1984-05-16 first 500 units and (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st unit and above.	

[No. CMD/13 : 10]

B. N. SINGH, Addl. Director General

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1987

का. प्रा. 2541.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में मेरठ विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

डॉक्टर आक मेडीसिन (बाल चिकित्सा) एम. डी.
(बाल चिकित्सा)

टिप्पण: उपर्युक्त अर्हता यदि मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा एम. एस. एल. आर. एम. मेडिसिन कालेज, मेरठ में प्रशिक्षित छात्रों को अनुवर्त की गई है तो मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

[संख्या 11015/23/87-एम. ई. (पी)]
अ.र. श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 1st September, 1987

S.O. 2541.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) the Central Government, after consulting the Medical Council of India hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said schedule, after the entries relating to the University of Meerut, the following entries shall be inserted, namely :—

“Doctors of Medicine
(Paediatrics)

M.D. (Paed).

Note.—The above qualification shall be recognised medical qualification when granted by Meerut University in respect of the students being trained at L.L.R.M. Medical College, Meerut

[No. V. 11015/23/87-ME(P)]
R. SRINIVASAN, Under Secy.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1987

का. आ. 2542.—चूंकि कमांडर के चेलिया जिन्हें गोदी अधिकारी और नौवहन कंपनियों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार तत्कालीन परिवहन मंत्रालय (जल-भूतल परिवहन विभाग) (परिवहन पक्ष) की दिनांक 25 अक्टूबर, 1986 की अधिसूचना का. आ. 786 (घ) के द्वारा कोचीन डॉक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, भारतीय नौवहन निगम की सेवा से सेवा-निवृत्त हो गये हैं ;

और चूंकि इस प्रकार डॉक लेबर बोर्ड में रिक्ति हो गई है,

इसलिए अब केन्द्र सरकार, गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुपालन में रिक्ति को अधिसूचित करते हैं।

[का. सं. एन डी एक्स/6/85-यू. एस. (एल) (i)]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 31st August, 1987

S.O. 2542.—Whereas Commander K. Chelliah who was appointed as a member of the Cochin Dock Labour Board representing the employers of Dock Workers and Shipping Companies by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport (Department of Surface Transport), (Transport Wing) No. S.O. 786 (E), dated the 25th October, 1986 has since retired from the service of Shipping Corporation of India;

And whereas the vacancy has thus occurred in the said Dock Labour Board;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LDX/6/85-US(L),ii]

का.आ. 2543:—केन्द्र सरकार, गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (1) के दूसरे परन्तुक के साथ पठित गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) के अनुपालन में भारतीय नौवहन निगम की सेवा से सेवा-निवृत्त हुए कमांडर के. चेलिया के स्थान पर श्री पी. जी. एन कुट्टी को कोचीन डॉक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और निर्देश देती है कि भारत सरकार, तत्कालीन परिवहन मंत्रालय (जल-भूतल परिवहन विभाग) (परिवहन पक्ष), की अधिसूचना का. आ. सं. 786(घ) दिनांक 25 अक्टूबर, 1986 में निम्नलिखित संशोधन किये जाएँगे, मुख्यतः:—

उक्त अधिसूचना में, “गोदी मजदूरों और नौवहन कंपनियों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह” शीर्ष के संशोधित मत संख्या 3 में “कमांडर के. चेलिया” के प्रविष्टि के स्थान पर “श्री पी. जी. एन. कुट्टी” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[का. सं. एन डी एक्स/6/85-यू. एस. (एल) (II)]

सुदेश कुमार, सचिव

S.O. 2543.—In pursuance of sub-section (3) of Section 5A of the Dock Workers (Regulation of employment) Act, 1948 (9 of 1948) read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri P. G. N. Kuttly as a member of the Cochin Dock Labour Board vice Commander K. Chelliah who has since retired from the service of Shipping Corporation of India and directs that the following amendment shall be made in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry

of Transport (Department of Surface Transport), (Transport Wing) No. S.O. 786(E), dated the 25th October, 1986, namely:—

In the said notification, under the heading “Members representing the employers of Dock Workers and Shipping Companies”, against item 3, for the entry “Commander K. Chelliah”, the entry “Shri P. G. N. Kuttly” shall be substituted.

[F. No. LDX/6/85-US(I)(ii)]
SUDESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

का. आ. 2544:—इससे उपायध अनुसूची में विकसित विभिन्न डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीमों का और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे, केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की धारा अनुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तत्कालीन दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार दिया जाएगा ;

उक्त प्रारूप की बाबत पूर्वोक्त अवधि के अन्तर्गत में पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप स्कीम

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम डॉक कर्मकार (नियोजन विनियमन) संशोधन स्कीम, 1987 है।

(2) यह राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होगी।

2. इससे उपायध अनुसूची के स्वम्भ 2 में उल्लिखित डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीमों को उस रीति से संशोधित किया जाएगा जैसी उसके स्वम्भ 3 में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3
1.	मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956	(i) खण्ड 7 के उपखण्ड (i) में,— (क) भद (ग) में, “रहित-स्वीकृत नियोजकों और” शब्दों का खोप दिया जाएगा; (ख) भद (घ) में, “न्याय-योजन करने” शब्दों का खोप दिया जाएगा; (ii) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का खोप दिया जाएगा; (iii) खण्ड 13 में, उपखण्ड (1) में, भद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित भद रखा जाएगी, अर्थात्:— (ग) ऐसे व्यक्तियों का जिन्हें मुम्बई पत्तन न्याय के प्रव्यय द्वारा नौवहन के रूप में छुट्ट कराने के लिए

1	2	3
		अनुज्ञति दी गई है। अनुज्ञति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया सनझा जाएगा।
	(iv) खण्ड 44 के उपखण्ड (1) की मद (ii) में उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे जाते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।	
	(v) खण्ड 48 में, उपखण्ड (2) का लोप किया जाएगा।	
2. भद्रास डाँक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956	(i) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में, (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जाएगा;	
	(ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जाएगा;	
	(ii) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;	
	(iii) खण्ड 15 में, उपखण्ड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात्:—	
	"(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें भद्रास पत्तन न्याम के अध्यक्ष द्वारा नौभारत के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञति दी गई है, अनुज्ञति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया सनझा जाएगा";	
	(iv) खण्ड 45 के उपखण्ड (i) की मद (ii) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे जाते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।	
	(v) खण्ड 49 में, उपखण्ड (2) का लोप किया जाएगा।	
3. कोचीन डाँक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959	(i) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में, (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जाएगा;	

1	2	3
		(ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जाएगा;
	(ii) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;	
	(iii) खण्ड 15 में, उपखण्ड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—	
	"(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कोचीन पत्तन न्याम के अध्यक्ष द्वारा नौभारत के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञति दी गई है, अनुज्ञति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया सनझा जाएगा; "	
	(iv) खण्ड 45 के उपखण्ड (1) की मद (ii) में, उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहाँ वे जाते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा;	
	(v) खण्ड 49 में उपखण्ड (2) का लोप किया जाएगा;	
4. विशाखापटनम् डाँक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1959	(i) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में, (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जाएगा;	
	(ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जाएगा;	
	(ii) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;	
	(iii) खण्ड 14 में, उपखण्ड (1) में मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—	
	"(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें विशाखापटनम् पत्तन न्याम के अध्यक्ष द्वारा नौभारत के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञति दी गई है, अनुज्ञति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया सनझा जाएगा।	

1	2	3	1	2	3
		(iv) खण्ड 44 के उपखण्ड (1) की मद (ii) में, उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा;		(ii) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;	
		(v) खण्ड 48 में उपखण्ड (2) का लोप किया जाएगा;		(iii) खण्ड 16 में, उपखण्ड (1) में मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात्— (ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिए अनुशक्ति दी गई है, अनुशक्ति के बाधुरहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।	
5. भारमुगाओं डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965		(i) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,— (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जाएगा; (ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जाएगा;		(iv) खण्ड 46 के उपखण्ड (1) की मद (ii) में, उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा;	
		(ii) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जाएगा,		(v) खण्ड 50 में, उपखण्ड (2) का लोप किया जाएगा।	
		(iii) खण्ड 16 में, उपखण्ड (1) में, (ग) के स्थान पर पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें भारमुगा ओ पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिए अनुशक्ति दी गई है, अनुशक्ति के बाधुरहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा। "	7. कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970	(i) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,— (क) मद (घ) में "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जाएगा। (ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जाएगा;	
		(iv) खण्ड 46 के उपखण्ड (1) की मद (ii) में उपमद (ख) में, "बोर्ड," शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।		(ii) खण्ड 8 में, उपखण्ड (ख) का लोप किया जाएगा।	
		(v) खण्ड 50 में, उपखण्ड (2) का लोप किया जाएगा।		(iii) खण्ड 17 में, उपखण्ड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात्— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिए, अनुशक्ति दी गई है, अनुशक्ति के बाधुरहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा। "	
6. कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969		(i) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,— (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जाएगा; (ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जाएगा;		(iv) खण्ड 48 के उपखण्ड (1) की मद (ii) में, उपमद	

1	2	3
		(ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "प्रबन्धक" शब्द रखा जाएगा;
		(v) खण्ड 52 में, उपखण्ड (2) का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० एल० बी०-13013/7/87-गल० IV]
बी० शंकरानिगम, निदेशक

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2544—The following draft of a Scheme further to amend various Dock Workers (Regulation of Employment) Schemes, specified in the Schedule annexed hereto, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft before the expiry of the aforesaid period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. The Dock Workers (Regulation of Employment) Schemes mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto shall be amended in the manner specified in column (3) thereof.

SCHEDULE

Sl. No.	Short title	Amendment
1	2	3
1. The Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956		(i) in clause 7, in sub-clause (1), (a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted; (b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted; (ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted; (iii) in clause 15, in sub-clause (1) for item (c), the following item shall be substituted, namely:— "(c) persons who have been licensed to function

1	2	3
		as stevedores by the Chairman of Bombay Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.";
	(iv)	in clause 44, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board", at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted;
	(v)	in clause 48, sub-clause (2) shall be omitted.
2. The Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956.		(i) in clause 7, in sub-clause (1),—(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted; (b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted; (ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted; (iii) in clause 15, in sub-clause (1) for item (c) the following item shall be substituted, namely:— "(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the Chairman of Madras Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.";
	(iv)	In clause 45, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board", at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted;
	(v)	in clause 49, sub-clause (2) shall be omitted.
3. The Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959		(i) in clause 7, in sub-clause (1), (a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted; (b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted; (ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted; (iii) In clause 15, in sub-clause (1), for item (c) the following item shall be substituted namely:— "(c) persons who have been licensed to function as stevedores by the Chairman of Cochin Port

1	2	3	1	2	3
		Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.			during the currency of the licence.”;
		(iv) in clause 45, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;			(iv) in clause 46, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;
		(v) in clause 49, sub-clause (2) shall be omitted.			(v) in clause 50, sub-clause (2) shall be omitted;
4. The Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959.		(i) in clause 7, in sub-clause (1)—(a) in item (c), the words “registered employers and” shall be omitted; (b) in item (d), the word “adjusting” shall be omitted;	6. The Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969.		(i) in clause 7, in sub-clause (1),—(a) in item (c), the words “registered employers and” shall be omitted; (b) in item (d), the word “adjusting” shall be omitted;
		(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;			(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;
		(iii) in clause 14, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely:— “(c) persons who have been licensed to function as stevedores by the Chairman of Visakhapatnam Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”;			(iii) in clause 16, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely:— “(c) persons who have been licensed to function as stevedores by the Chairman of the Kandla port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”;
		(iv) in clause 44, in sub-clause (1), in item (ii); in sub-item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;			(iv) in clause 46, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;
		(v) in clause 48, sub-clause (2) shall be omitted.			(v) in clause 50, sub-clause (2) shall be omitted.
5. The Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965.		(i) in clause 7, in sub-clause (1),—(a) in item (c), the words “registered employers and” shall be omitted; (b) in item (d), the word “adjusting” shall be omitted;	7. The Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970		(i) in clause 7, in sub-clause (1),—(a) in item (d), the words “registered employers and” shall be omitted;
		(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;			(b) in item (c), the word “adjusting” shall be omitted;
		(iii) in clause 16, in sub-clause (1), for item (c), the following shall be substituted, namely:— “(c) persons who have been licensed to function as stevedores by the Chairman of Mormugao Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme			(ii) in clause 8, sub-clause (b) shall be omitted;
					(iii) in clause 17, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely:— “(c) persons who have been licensed to function as stevedores by the

1 2 3

New Delhi, the 3rd September, 1987

Chairman of Calcutta port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”;

(iv) in clause 48, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;

(v) in clause 52, sub-clause (2) shall be omitted.

[File No. LB-13013/7/87-L.IV]

V. SANKARALINGAM, Director

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1987.

का. प्रा. 2545:—अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) के खंड 3 के उप-खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री आर. सी. रेखी को भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 3500-4000 रुपये के अनुसूची “सी” वेतनमान में, उनके कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पूर्णकालिक सचिव (इंजीनियरी) के रूप में नियुक्त करती है।

[ए. सी. 24020/4/85-ए. (एफ-II)]

अरुणा माखन, वित्त नियंत्रक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st September, 1987

S.O. 2545.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri R. C. Rekhi, as the whole-time Member (Engineering) in the International Airports Authority of India, in the Schedule ‘C’ scale of pay of Rs. 3500—4000, for a period of three years from the date of his assuming charge of the post.

[No. AV-24020/4/85-A (F. III)]

ARUNA MAKHAN, Financial Controller

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

का. प्रा. 2506:—पवन हंस लिमिटेड (जो पहले भारतीय हेलीकाप्टर निगम के रूप में प्रचलित था) के शासन और संस्था प्रशासनिक नियम 38(ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी, वायुसेना मुख्यालय के उप-सेनाध्यक्ष के स्थान पर जिनकी नियुक्ति इस मंत्रालय की 7 जनवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या ए. सी.-13015/10/86-ए. सी. के द्वारा अधिसूचित की गई थी, तत्काल से और 6 जनवरी, 1989 तक वायुसेना मुख्यालय में परिचालन निदेशक (परिवहन एवं मेरिट टाइप) को पवन हंस लिमिटेड के बोर्ड में पदेन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

[संख्या ए. सी.-13016/10/86-ए. सी.]

एस. बैंकोबाचार्य, धवर सचिव

S.O. 2546.—In exercise of the powers conferred by Article 38(a) of the Memorandum and Articles of Association of Pawan Hans Ltd. (formerly known as Helicopter Corporation of India), the President is pleased to appoint Director of Operations (Transport & Maritime), Air Headquarters, as ex-officio Director of the Board of Pawan Hans Ltd., with immediate effect and until 6th January, 1989 in place of Vice Chief of Air Staff, Air Headquarters whose appointment was notified vide this Ministry's notification No. AV-13015/10/86-AC, dated the 7th January, 1987.

(A.V.-13015/10/86-AC)

S. VENKOBACHAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1987

का. प्रा. 2547:—केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 482 में, जिनमें दिनांक 17 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 1843 द्वारा संशोधन किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है।

सारणी में क्रमांक 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाय, अर्थात्:—

“26. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), त्रिपुरा अगस्त”

[जैड-20025/28/86-सी. एल. टी.]

राम कानूगा, धवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st August, 1987

S.O. 2547.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 482 dated the 29th January, 1981 and further amend by Notification No. S.O. 1843 dated the 17th April, 1985, in the Table after serial No. 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“26. Labour Enforcement

Officer (Central), Agartala, Tripura.

[File No. Z-20025/28/86-C.L.T.]

RAM KANUGA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1987

का. प्रा. 2548:—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अनुभाग अधिकारी श्री के. एन. एस. नायर को 1, सितम्बर, 1987 से अगले आदेश जारी होने तक उत्प्रवास संरक्षी, त्रिबेन्गल के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए-22012(1)/86-उत्प्रवास-II]

इन्दर सिंह, धवर सचिव

New Delhi, the 31st August, 1987

S.O. 2548.—In exercise of the powers conferred by Section 3, sub-section (1) of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri K.N.S. Nair, Section Officer as Protector of Emigrants, Tripura, with effect from 1st September, 1987, till further orders.

[No. A-22012(1)/86-Emig. II]
INDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1987

का. भा. 2549.—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली अप्रैल, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शाए जायेंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अधिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिप्राय पहले ही संदत्त किए, जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जायेंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (5) नियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस नियमित अधिदत्त नियम का कोई अन्य पक्षधारी,
 - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को महापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
 - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
 - (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
 - (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के संबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किसी उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उनके भारमाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के तालमेल में संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों

ऐसे निरीक्षक या अन्य पक्षधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकारी या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पक्षधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में गये गए, किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं. एम.-38014/68/86-एस.एस.-1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट की मूललक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट की मूललक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 31st August, 1987

S.O. 2549.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam from the operation of the said Act for a period with effect from 1st April, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/68/86-SS. I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का. घा. 2550. केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की समस्तुषंगी कोल इंडिया प्रेस, रांची के नियमित कर्मचारियों का उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह नारीश भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देनी है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पवां धाम वर्णित किए जाएंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रमुखियाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदन अधिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अनिवाय पहल्वे ही संदन किए, जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विनिष्टियों गहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधिनियम उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (5) नियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राविष्ट नियम का कोई अन्य पदधारी,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

- (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
- (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुखियाओं को, जो ऐसी प्रमुखियाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकव और वस्तु रूप में पाने का हकार बना हुआ है या नहीं; या
- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे कि ही उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए गणक होगा,

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संवाय से संबंधित ऐसी लेखा बहियां और अन्य वस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने से या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिनके जाने में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पाम यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा बही या अन्य वस्तावेजों की नकल करना या उससे उद्वरण लेना।

[स एन-38014/59/86-एस एस-1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 2550.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Coal India Press, Ranchi, a subsidiary of the Coal India Limited from the operation of the said Act for a period with effect from 1st July, 1985 upto and inclusive of the 30-9-1987.

The above exemption is subject to the following conditions namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—
 - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
 - (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

16. No. S-38014/59/86-SSI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

87/1035 GH -8.

का. आ. 2551.—सैनर्स क्लब टैम्पो लि०, बाभेयूणे रोड अकुरुडी पुणे-411035 (एम. एच./5354) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी एक अनिवार्य या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हों वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहयोग बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2314 तारीख 6-5-1983 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 21-5-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-5-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निरदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों या प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निरदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रज्ञापन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुगोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में निर्दिष्टित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा। जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी दान के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्दाय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिका वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. समूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के लिए पर-प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो सके, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपनी अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपनी दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की इस मानदिक केमा स्कीम के, जिस स्थापन वाले अपने अपना चुका है, प्रवेश नहीं कर पाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत, भारतीय के जीवन प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रहता है और पालिसी की अवधि में जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के भुगतान में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन गुण सदस्यों के नामनिर्देशनियों या विधिकारियों की की यदि वह छूट में ही रहती हो तो इस स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के भुगतान का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर या अनारोप जीवन बीमा निगम, बीमाकृत प्राण के हकदार नामनिर्देशनियों/विधिकारियों को इस स्कीम का भुगतान करने का अधिकार प्रदान करने में परंपरिक में पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एन-35014/103/87-एम, एम.-2]

S.O. 2551.—Whereas Messrs. Bajaj Tempo Limited, Bombay—Pune Road, Akurdi, Pune-411035 (MH/5354) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S. O. 2314 dated the 6-5-1983 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-5-1986 upto and including the 20-5-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No S-35014/103/87-SS-II]

का. प्र. 2551—केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन में सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की सहमति पर यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रमाण उपबंध प्रनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :-

1. मैसर्स बिजय साधनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, गांधीनगर, विजयवाड़ा-3

2. मैसर्स ई पी एफ डिपार्टमेंटल कौन्सिल, कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आरक्षक-11 और सी पी कमलेश्वर, विजयवाड़ा

3. मैसर्स रत्ना कमलकण्ठ श्री-6 ए पी आई ई, आटोमनगर, विशाखा-पट्टनम

4. मैसर्स ईस्ट कोस्ट इन्सुरेंस अफर अरकेड, वायटेल रोड, विशाखापट्टनम

प्र. १-सी

1. उक्त योजना के अन्तर्गत में निम्नलिखित प्राथमिक शैक्षणिक विधि-
साधन उद्योगों को ऐसा विनिर्दिष्ट करना और उसे देना रखना तथा
निरीक्षण करके ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय
पर निर्दिष्ट करे।

2. निष्ठाभावा, ऐन निरीक्षा, प्रसारण का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय गयेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम का धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अर्थात् सत्य-समय पर निर्दिष्ट करे ।

4. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत जेबाना का जना, विवरणियाँ का प्रस्तुत किया जाता, बीमा पोलिस का मर्यादा का अन्तर्गण, निराकरण प्रभावों का मर्यादा यदि भी है, हानि वाले धन का उचित नियोजक द्वारा किया जाएगा।

1. त्रियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमानित सामाजिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस सुधारण की प्रति तथा कमराजियों हो वह समस्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थान के क्लर्क-मैजिस्ट्रेट पर प्रेषित करेंगे।

५. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी अधिनियम विधि का या उन अधिनियम को अधीन छूट प्राप्त किसी स्थान की मरिच विधि का पहले श्री मद्रस्य है उसी स्थान में नियोजित किया जाता है या नियोजक राज्य का होगा क्योंकि क मद्रस्य के रूप में उत्तरात्म तुला उषा मिया जी, मन्त्री राज्य का नियम अधिनियम भारतीय अधिनियम सीमा नियम को मद्रस्य करेगा ।

७. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा। जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अन्तर्कूल हों, जो उक्त स्कीम के अंतर्गत प्रतर्जित हैं।

7. सामूहिक बागा स्कीम में किसानों को दोनो प्रकार के ऋण मिलेंगे। यदि किसानों की मूल्य पर इस स्कीम के धारित भण्डेय रहम उन रहम में कम जो कर्मचारियों को इस शर्त में मंजूर होंगे जब वह उचित स्कीम के दोनो शीला-तो, नियोजक कर्मचारियों के विधिक वारिस/वामनिर्देशिका को कर के रूप में दोनो रहमों के अन्तर में अन्तर रहम का मन्जूर

४. सामूहिक स्वाम के उद्भववादी में हांड भी अंगीकार प्रातिष्ठक
पण्य निधि आयुक्त उद्धाना के पूर्व समुदाय के बिना नहीं किया
गया और जहाँ किसी संगठन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल
पड़ने की सम्भावना हो, वहाँ प्रातिष्ठक निधि आयुक्त अना
मोदन देम से पूर्व कर्मचारियों को अना दृष्टिकोण रखने करने का
नियुक्त प्रयत्न देगा ।

७. यदि किसी कारणवश स्थापन के सम्बन्धी भारतीय जीवन नीतिमा निगम की उस सामूहिक नीति स्वीकृत है, जिसे स्थापन पहले अग्रता प्रका है, अग्रणी नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अग्रणी सम्बन्धियों का प्राप्त होने वाले फायदे अग्रता नीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रह जा सकता है।

10. यदि किसी कारणवश, निर्माता ग्राहक को त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति प्रदान करने के बजाय प्रमाणित निष्पत्ति प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो निर्माता को ग्राहक को त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

[S. 350; 9(36) / 87-SS-11]

का. आ. 255-1-—एसमें दृष्टिगत एन्वैस्मैन्टिज कम्पनी लि.,
हाकखाना—हीरापुर, जिला-सम्बलपुर (उड़ीसा) (ओ. आर/332),
(जिसे एसमें एसके पश्चात्, उक्त स्थापन कइल गया है) के कर्मचारी कृषिप
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे
एसमें एसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कइल गया है) की धारा 17 की उप-
धारा (2क) के प्रतीन कृषि निधि के लिए प्रावधान किया है ;

और कर्मचारी नरकर का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान के कर्मचारी किसी पृथक् अधिदान या प्रीमियम का मुद्दा ही नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम का सामाजिक बीमा स्कीम के अर्धान जीवन बीमा के रूप में जो कायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन कायदों से अधिक अनुकूल है जो उक्त कर्मचारी विशेष मरुद्द बीमा स्कीम 1976 (जिसे हमसे डा. वि. पा. त. उ. वि. में कड़ा गया है) के अर्धान प्रयोज्य है।

पता: केंद्रीय सरकार, उक्त पोष्टनियम को प्रायः 17 को उपभार।
(26) द्वारा प्रदान गतिविधि का प्रदान करने हुए और भारत सरकार के
धर्म मंत्रालय की अधिसूचना मद्रास का प्रा. 2716 तारीख 1-7-1982
के अनुसरण में और इसमें उपायुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंगीत
रहते हुए, उक्त स्थापन का, 24-7-1985 में तीन वर्षों की अवधि के लिए
जिसमें 23-7-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के
प्रावधान से छट देवी है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मूल मदों के नामनिर्देशनियों या वित्तिक बरिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उस स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किंग नरेश की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राज के हकदार नामनिर्देशित/वित्तिक बरिसों का उन राज का मन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दायें का प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/102/87-एस. एस-2]

New Delhi, the 1st September, 1987

S.O. 2553.--Whereas Messrs. Indian Aluminium Company Limited, At Post--Hirakad District--Sambalpur (Orissa) (OR/332) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2716 dated the 1-7-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-7-1985 upto and inclusive of the 23-7-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, then the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014/102/87-SS.II]

का. आ. 2554.--प्रेसमें टाटा एल्यूमीनियम लि., जेडर डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल एरिया, बी. रोड, बीराम (एम. पी. 2288) (जिसे हमें, इसके पश्चात् उस स्थापन कहा गया है) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रयोग उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे हमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है:

और केन्द्रीय सरकार को समाधान हो गया है कि उस स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् प्रविधय या प्रीमियम का मन्दाय किए बिना है, लाइफ कवर स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जा फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों में अधिक अनुकूल है जा उन्हें कर्मचारी निधेय महत्व बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमें इसके पश्चात् उस स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के प्रम सलाय की अधिलेखना संख्या आ. 1772 तारीख 17-5-1984 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुपूर्वों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उस स्थापन को 2-6-1987 में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 1-6-1990 भी सम्मिलित है उस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुपूर्व

1. उस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त मध्य प्रदेय को ऐसी विधिवत प्रवेक्षण और ऐसी सेवा प्रदान करना निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो केन्द्रीय सरकार समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. लाइफ कवर स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रमारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रामोदित लाइफ कवर स्कीम के नियमों को एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पढ़ने ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक लाइफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा।

6. यदि लाइफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुवैय हैं।

7. लाइफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिभर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. लाइफ कवर स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिबुद्ध प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, लाइफ कवर स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी राशि से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. उक्त स्थापन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पांच लाख रुपए लाइफ कवर फण्ड के नाम से जमा कराएगा और इसमें से निकाली गई राशि को समय-समय पर पूरा करेगा। किसी भी समय यह राशि उपरोक्त फण्ड में पांच लाख रुपए से कम नहीं रहनी चाहिए। अगर कभी भी यह पाया गया कि फण्ड की राशि पांच लाख रुपए से कम है तो छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्ति-क्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होता, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रवेष्ट दशा में हर प्रकार के पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[(संख्या एन-35014/120/81-पी. एक-2 (एन. एन-2))]

S.O. 2554.—Whereas Messrs Tata Exports Limited, Leather Division Industrial Area, A.B. Road, Dewas-MP (MP/2288) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the said establishment in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S. O. 1772 dated the 17-5-84 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempt the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-6-1987 upto and inclusive of the 1-6-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme, including maintenance or accounts, submission of returns, and payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is a ready a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Life Cover Scheme.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the establishment as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme

are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. The said establishment shall deposit a sum of rupees Five Lakhs in the State Bank of India under suitable entitlement (to be called Life Cover Fund) and the employer shall ensure by replenishment of the short fall from time to time so that at no time the amount in the Life Cover Fund is less than rupees five lakhs. Where for any reason the employer fails to replenish the Life Cover Fund and the amount thereof is less than rupees five lakhs, there exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Life Cover Scheme the employer of the said establishment shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/120/81-PF-II SS.II]

का. आ. 2555.—मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स लि., पेपर टाउन भद्रावती-577302, शिमोगा (के. एन/41), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट किए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, लाइफ कवर स्कीम के अधीन जीवन बीमा के तहत जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप महबूब बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 159 तारीख 20-12-1984 के अनुसरण में और इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 5-1-1988 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 4-1-1991 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करें।

3. लाइफ कवर स्कीम के प्रशासन में निम्न अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित लाइफ स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए,

तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक लाइफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा।

6. यदि लाइफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. लाइफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दाय रकम उस स्कीम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्दाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामानिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. लाइफ कवर स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चित अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, लाइफ कवर स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. उक्त स्थापन स्टेट बैंक आफ इंडिया में पांच लाख रुपए लाइफ कवर फण्ड के नाम से जमा कराएगा और इसमें से निकाली गई राशि को समय-समय पर पूरा करेगा। किसी भी समय यह राशि उपरोक्त फण्ड में पांच लाख रुपए से कम नहीं रहनी चाहिए। अगर कभी भी यह पाया गया कि फण्ड की राशि पांच लाख रुपए से कम है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[(संख्या एम-35014/159/74-एम. एस-4 (एमएस-2)]

S.O. 2555.—Whereas Messrs Mysore Paper Mills Limited, Paper Town, Bhadravati-577302, Shimoga (KN/41) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the said establishment in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour S.O.159 dated the 20-12-84 and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 5-1-1988 upto and inclusive of the 4-1-1991.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, and payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Life Cover Scheme.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee, the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amount payable Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the establishment as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. The said establishment shall deposit a sum of rupees Five lacs in the State Bank of India under suitable entitlement (to be called Life Cover Fund) and the employer shall ensure by replenishment of the short fall from time to time so that at no time the amount in the Life Cover Fund is less than rupees five lakhs. Where for any reason the employer fails to replenish the Life Cover Fund and the amount thereof is less than rupees five lakhs, there exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme

but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Life Cover Scheme the employer of the said establishment shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/159/84-SS-IV SS.II]

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1987

का. आ. 2556.—सैवर्ग—हिन्दोस्तान मशीन टूल्स लि., एच. एम. टी. कालोनी, -वर्तमान-683503 (के. आर./2357) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारों भविष्य निधि और प्रकोष्ठ उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किरी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निवेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुसूची है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1227 तारीख 3-3-1982 के अनुसार और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 20-3-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 19-3-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, केरला को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निरदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रश्नों का प्रत्येक मास को गनादिन के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निरदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रश्नों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुसूचित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उन्हें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसकी स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उदात्त फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुवैय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. समूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है और पतिसी की व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संशय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-3/014/105/87-एन. एस.-2]

New Delhi, the 2nd September, 1987

S.O. 2556.—Whereas Messrs Hindustan Machine Tools Limited HMT Colony, Ernakulam-683503 (KR/2357) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1227 dated the 3-3-1982 and subject to the

conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 20-3-1985 upto and inclusive of the 19-3-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Kerala and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No. S. 35014/105/87-SS. II]

A. K. BHATTARAI Under Secy

नई दिल्ली, 8 मिनम्बर, 1987

का. आ. 25574/मंत्रालय राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के अर्थ मंत्रालय की तारीख 20 जून 1987 की अधिसूचना संख्या का. आ. 375 के अन्तर्गत भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अप्रैल 1987 से 30 मिनम्बर 1987 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की और अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: अर्थात्:—

(1) पूर्वोक्त कारखाना जिसमें कर्मचारी नियोजित है एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्जित किए जाएंगे;

(2) हम छूट के हतियान भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्रमुविधान प्राप्त करने रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे बापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उक्त अधिनियम की बाबत जिसके दौरान उक्त कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे, इसमें, हमारे, पश्चात् उक्त अधिनियम कड़ा गया है) ऐसी बिगिस्टियों ऐसे प्राकृत में और ऐसे बिगिस्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के अधीन उक्त अधिनियम की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी:

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिनियम की बाबत दी गई किसी विवरणी की बिगिस्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए; या

(ii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 द्वारा तथा अर्पेसित रजिस्टर और अभिलेखा उक्त अधिनियम के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुविधानों को जो ऐसी प्रमुविधान हैं जिनके प्रतिकलक्षण इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है तक और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि उक्त अधिनियम के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशकत होगा—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभाग में कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी

उचित समय पर प्रवेश करना और उसके सारमाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय में संबंधित ऐसी निष्ठावहियां और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनको परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकारी या सेवक की या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया गया या ऐसे किसी व्यक्ति की जिनके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास वह विश्वास करने का यकिनयुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापना कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, निष्ठावहियां या अन्य दस्तावेज को नकल करना या उसमें उद्धरण लेना।

सूची

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद का कार्यालय भारत भवन, 496, कुरुक्षेत्र रोड, बम्बई-400038
2	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिबीजन, माहल बम्बई - 400074
3	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बम्बई क्षेत्र कार्यालय, भारत भवन, 496, कुरुक्षेत्र रोड, बम्बई-38
4	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. बम्बई डिबीजन कार्यालय ई व फ सेंटर टावर 12वीं मंजिल, बपी पेट्रोल, बम्बई-35
5	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., एयर क्राफ्ट सर्विस स्टेशन गानाकुल हवाई अड्डा (घरेलू) गानाकुल, बम्बई 400057
6	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम प्रशिक्षण केंद्र, ट्राम्बे हाऊस जूहू बम्बई 400054
7	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मेरिन ड्रायल टर्मिनल बुचर अहमदाबाद, बम्बई
8	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मिबनी, बम्बई 15
9	महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मनेट रोड, वाडी बन्दर बम्बई 400009

1	2	3	4	1	2	3	4
10. महाराष्ट्र	बम्बई	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., टास्के डिस्ट्रिक्ट यूनिट, रिफाइनरी रोड, माहुल, बम्बई 400074		26. गुजरात	सांघीनगर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., कान्हावा इंगटनिशन पोस्ट बाक्स नं. 33, डाकघर गौरीधाम, गुजरात	
11. महाराष्ट्र	नागपुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन "कनोरा हाऊस" पाम रोड, पोस्ट बाक्स नं. 17, नागपुर 1		27. गुजरात	अहमदाबाद	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., अहमदाबाद डिस्ट्रीबुशन कार्यालय, मिशन रोड, भाद्रा पोस्ट बाक्स नं. 52, अहमदाबाद।	
12. महाराष्ट्र	पूना	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., 11 डा. कोयली रोड, पोस्ट बाक्स नं. 61, पूना-1		28. गुजरात	वडोदा	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिस्ट्रिक्ट यूनिट (कोयली), जवाहर नगर, जिला वडोदा, पिन कोड 391321	
13. महाराष्ट्र	अकोला	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो रेलवे स्टेशन के नजदीक, अकोला, 40001		29. गुजरात	अहमदाबाद	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिस्ट्रिक्ट यूनिट, साबरमती इन्फ्रस्ट्रक्चर्स, अहमदाबाद 380019	
14. महाराष्ट्र	अमरावती	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो मोरशी रोड, अमरावती, 444601		30. गुजरात	भावनगर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., एविएशन सर्विस स्टेशन, सिविल एरोड्राम, भावनगर।	
15. महाराष्ट्र	मनमाड	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो पो. बा. नं. 6 मनमाड।		31. गुजरात	भुज	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., एविएशन सर्विस पोस्ट बाक्स नं. 29, भुज-370001	
16. महाराष्ट्र	नागपुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो फूल मार्फिट के सामने, नागपुर 440016		32. गुजरात	सुरत	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो सहार गेट के बाहर, सुरत-398003	
17. महाराष्ट्र	पूना	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., 40/41 डा. अम्बेडकर रोड पोस्ट बाक्स 208, आर. टी. ओ. के पीछे पूना 411001		33. गुजरात	अहमदाबाद	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., अहमदाबाद बोटलिंग, प्लांट, अहमदाबाद।	
18. महाराष्ट्र	शोलापुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, पोस्ट पाक्स नं. 2 शोलापुर।		34. मध्य प्रदेश	भोपाल	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., भोपाल डिस्ट्रीबुशन कार्यालय, सी/2, बी.डी.एच. कालोनी, नगर निगम वेस्ट हाउस के सामने, लिंक रोड नं. 3 के नजदीक, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462016	
19. महाराष्ट्र	सांगली	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., अन्वय वाडी मिनाज जिला सांगली 406410		35. मध्य प्रदेश	ग्वालियर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., एविएशन सर्विस स्टेशन, पोस्ट बाक्स नं. 9 ग्वालियर-474002	
20. महाराष्ट्र	अमरावती	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो सी/ओ आई.ओ. सी डिपो, विजया मिल के पीछे बबनरा जिला अमरावती-701		36. मध्य प्रदेश	ग्वालियर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर-474032	
21. महाराष्ट्र	पूना	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., लोनी डिस्ट्रिक्ट यूनिट, सी/ओ एच पी सी एल इन्स्टालेशन लोनी, जिला पूना।		37. मध्य प्रदेश	रायपुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., रायपुर एविएशन सर्विस स्टेशन, रायपुर-77	
22. महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., कोल्हापुर डिपो रेलवे स्टेशन के नजदीक, कोल्हापुर।		38. मध्य प्रदेश	इन्दौर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो 26, पार्क रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश)-452003	
23. महाराष्ट्र	नागपुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., व्यापरी, डिपो (एल. पी. जी.) व्यापरी जिला नागपुर		39. मध्य प्रदेश	खंडवा	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., खंडवा डिपो (मध्य प्रदेश)-450001	
24. गोवा	पणजी	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., गोवा डिस्ट्रीबुशन कार्यालय, "इमान" डा. गिमुन लेन्स रोड पणजी 403001					
25. गोवा	बास्को-डी-गामा	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिस्ट्रिक्ट यूनिट, बास्को-डी-गामा (गोवा) 403002					

1	2	3	4	1	2	3	4
40.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिपो साउथ मिक्सि लाइन्स, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	53.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., एविगेशन गविस स्टेशन, दम दम हवाई अड्डा, दम दम, कलकत्ता ।
41.	मध्य प्रदेश	रायचाम	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिपो रायचाम (म.प्र.)-457001	54.	बिहार	पटना	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., पटना डिबोजनल कार्यालय, प्रदर्शनी रोड, पोस्ट बाक्स सं. 20 पटना ।
42.	मध्य प्रदेश	सतना	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., सतना डिपो, सतना ।	55.	बिहार	बेगूसराय	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बाहकी डिस्पेंच यूनिट, पोस्ट बाक्स सं. 1, बगौली आयाल रिफाइनरी, जिला बेगूसराय-85144 ।
43.	मध्य प्रदेश	रायपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., रायपुर डिपो, तेलधानी बेक, डाकघर रायपुर-492001	56.	बिहार	धनबाद	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., धनबाद डिपो, धनबाद बाजार, पो.बा. 36, डाकघर, धनबाद ।
44.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय, 31, बिनाथ बादल, दिनेश बाग, पोस्ट बाक्स सं. 360, कलकत्ता-700001	57.	बिहार	रांची	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., रांची डिपो, स्टेशन रोड, डाकघर बुटिया, रांची-834001
45.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिबोजनल कार्यालय, 31 ब्रिन्कोच बादल दिनेश मार्ग, पोस्ट बाक्स सं. 360, कलकत्ता-700001	58.	बिहार	सिंहभूम	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., टाटा नगर डिपो, बर्मा माहूल्स, गृहस भोड रोड, डाकघर टाटा नगर, जिला सिंहभूम-831003
46.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मोरीग्राम डिस्पेंच यूनिट मार्फत आई.ओ.सी. इन्सटालेशन, पोस्ट आफिस राधादाशी हावड़ा ।	59.	बिहार	पटना	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., पटना डिस्पेंच यूनिट, पो.बा. नं. 27, पटना-800001 ।
47.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., हल्दिबा डिस्पेंच यूनिट डाकघर हल्दिया आयाल रिफाइनरी, मिदनापुर	60.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., भुवनेश्वर डिबोजनल कार्यालय, प्लॉट सं. 121ब, सूर्य नगर यूनिट 7, डाकघर भुवनेश्वर पो.बा. नं. 165 भुवनेश्वर-751003
48.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., राजबन्ध डिस्पेंच यूनिट मार्फत आई.ओ.सी. इन्सटालेशन, डाकघर राजबन्ध, जिला बर्दवान-713212	61.	उड़ीसा	कटक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., कटक डिपो, शेखर डाकघर कटक-753003
49.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., जलपाईगुडी डिस्पेंच यूनिट, मार्फत आई.ओ.सी. इन्सटालेशन, डाकघर भक्ति नगर, जिला जलपाईगुडी-731425	62.	उड़ीसा	सम्बलपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., सम्बलपुर डिपो, डाकघर मोरीपुरा, जिला सम्बलपुर-768002
50.	पश्चिम बंगाल	24 परगना	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बज बज इन्सटालेशन, जिला 24 परगना-743319	63.	उड़ीसा	गंजम	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बरहमपुर डिपो, डाकघर, बरहमपुर, जिला गंजम-768008
51.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., शालगांव डिपो, डाकघर शोर पेर, जलपाईगुडी-735204	64.	असम	बोन्गेगांव	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बोन्गेगांव डिस्पेंच यूनिट, मार्फत आई.ओ.सी. डाकघर देलीगांव-गौनालपुरा-783385
52.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., राजबन्ध डिपो डाकघर राजबन्ध, जिला बर्दवान ।	65.	असम	दुलीगांव	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., दुलीगांव डिस्पेंच यूनिट, (एल.पी.जी.) मार्फत आई.ओ.सी., दुलीगांव-783385, गोना कुरा

1	2	3	4	1	2	3	4
66. अरुम	गौहाटी	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिस्पेंच यूनिट, मार्फत एच.पी.सी. एल., गौहाटी-781020		79. उत्तर प्रदेश	कानपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिस्पेंच यूनिट, मार्फत आई.ओ.सी. इन्स्टालेशन, डाकघर, पाकी पावर हाउस, कानपुर-208020	
67. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	नई दिल्ली	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, ई.सी.ई. हाउस, पो.बा. सं. 7, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001		80. उत्तर प्रदेश	कानपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., कानपुर डिपो, फजलगंज, कानपुर-208012	
68. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	नई दिल्ली	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., दिल्ली डिबीजनल कार्यालय, जी-7, लक्ष्मी भवन, दूसरी और तीसरी मंजिल, पो.बा. सं. 396, नई दिल्ली 110001		81. उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., इलाहाबाद डिस्पेंच यूनिट, पोस्ट बाक्स सं. 44, मार्फत आई.ओ.सी. सूबेदार-गंज, इलाहाबाद-211001	
69. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	नई दिल्ली	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., परियोजना कार्यालय, 8-ब, हंसालय, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1		82. उत्तर प्रदेश	मुगलसराय	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिस्पेंच यूनिट, मार्फत आई.ओ.सी. इन्स्टालेशन, मुगलसराय।	
70. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	शकूरबस्ती	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., शकूरबस्ती इन्स्टालेशन, शकूरबस्ती, नई दिल्ली		83. उत्तर प्रदेश	मथुरा	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बी.पी.सी. डिस्पेंच यूनिट, एस. एंड डी भवन, गेट सं. 9 के सामने, मथुरा रिकफाइनरी, मथुरा।	
71. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	शकूरबस्ती	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., शकूरबस्ती, एल.पी.जी. बोर्डिंग, प्लाट, शकूरबस्ती, नई दिल्ली।		84. उत्तर प्रदेश	मेरठ	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिपो, ग्राम का मकबरा, मेरठ।	
72. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	पालम	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल-1, नई दिल्ली।		85. उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिपो, ग्रैंट रोड, सहारनपुर-247001	
73. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	बिजबासन	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बिजबासन इन्स्टालेशन, बिजबासन, नई दिल्ली।		86. उत्तर प्रदेश	मुगदाबाद	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिपो, रामपुर रोड, मुगदाबाद-244001	
74. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	बिजबासन	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., आई.ओ.सी. टर्मिनल बिजबासन, डिस्पेंच यूनिट, बिजबासन, नई दिल्ली		87. उत्तर प्रदेश	बरेली	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बरेली बोर्डिंग प्लांट, बरेली (उ.प्र.)	
75. उत्तर प्रदेश	बरेली	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बरेली डिबीजनल कार्यालय 35/11-ब सिबिल लाइन्स, बरेली-243001 (उत्तर प्रदेश)		88. राजस्थान	जोधपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिपो, राई का बाग, जोधपुर।	
76. उत्तर प्रदेश	लखनऊ	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिपो 94, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001		89. राजस्थान	जयपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिबीजनल कार्यालय पुराना रैजीडेंस रोड, दक्षिणी साऊथ, पी.बी.नं. 106, जयपुर-302001 पी.बी. (दक्षिण) के लिये 302006 (कार्यालय के लिये दिल्लीबरी)	
77. उत्तर प्रदेश	आगरा	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बीकान का बंगला, प्रतापुरा, ईशगढ़, आगरा-282001		90. राजस्थान	अजमेर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., तापे बाग, रेलवे क्रान्ति के नजदीक, अजमेर-205001	
78. उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., डिपो, गुड्स रोड के नजदीक, धर्मशाला रोड, गोरखपुर-273001		91. राजस्थान	जयपुर	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., जयपुर डिपो, जैन गोशाला, दक्षिण साऊथ-302001	

1	2	3	4	1	2	3	4
92.	राजस्थान	उदयपुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., उदयपुर डिपो, उदयपुर मार्गे रोड, उदयपुर-313001	106.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, कोयम्बटूर-641001
93.	राजस्थान	कोटा	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., कोटा डिपो, गुड्डम शेड के नजदीक, कोटा।	107.	तमिलनाडु	मदुरै	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, मदुरै-625001
94.	राजस्थान	जयपुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., जयपुर बोटांग प्लाट जयपुर।	108.	तमिलनाडु	तिरुनालवेली	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, तिरुनालवेली-627001
95.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., जबलपुर डिबीजनल कार्यालय, ब्लॉक सं. 70 और 71, सेक्टर 17, न्यू बैंक आफ इंडिया भवन, पो.बा. 39 जबलपुर-460017	109.	तमिलनाडु	तिरुचुरापत्ती	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, तिरुचुरापत्ती-620001
96.	पंजाब	पटियाला	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो रेलवे गुड्डम शेड के नजदीक, फेक्ट्री एरिया, पटियाला-147001	110.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., इंसटालेशन पो.बा. सं. 1644 पिलामेट्टु कोयम्बटूर-641004
97.	पंजाब	पठानकोट	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., धाकी रोड, रेलवे स्टेशन के नजदीक, पठानकोट	111.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., कोयम्बटूर एल.पी.जी. बोटांग प्लाट, पिलामेट्टु, कोयम्बटूर-641004
98.	पंजाब	जलंधर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, रेलवे गुड्डम शेड के नजदीक, जलंधर मिठा, जलंधर-144004	112.	कर्नाटक	बंगलौर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिबीजनल कार्यालय, "डी लालस" 2-सी रेजिडेंसी रोड, पो.बा. सं. 2575, बंगलौर।
99.	पंजाब	जलंधर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., आई.ओ.सी. पार्क नार्दन और एल.पी.जी. बोटांग प्लाट, सूचीपिंड, जलंधर।	113.	कर्नाटक	बंगलौर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., इंसटालेशन, बानावडी मार्की संक नगर, पो.बा. सं. 3305, बंगलौर-560033
100.	हरियाणा	हिसार	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो रेलवे स्टेशन के के नजदीक, हिसार-125001	114.	कर्नाटक	मंगलूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, मंगलूर-570021
101.	हरियाणा	हिमाचल	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., हिमाचल बोटांग प्लाट हिसार।	115.	कर्नाटक	मंगलूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, मंगलूर-575001
102.	हरियाणा	ग्रामवाल	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिस्पेंच यूनिट, शास्त्री कालोनी के नजदीक, जी.टी. रोड, ग्रामवाल-133001	116.	कर्नाटक	मंगलूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., मंगलूर डिस्पेंच यूनिट मंगलूर, कर्नाटक।
103.	तमिलनाडु	मद्रास	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय, 7 कोटासम्बकम हाई रोड, पो.बा. सं. 1277, मद्रास-600034	117.	कर्नाटक	बंगलौर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., बंगलौर डिपो (एल.पी.जी.) बंगलौर (कर्नाटक)
104.	तमिलनाडु	मद्रास	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिबीजनल कार्यालय सं. 7, कोटासम्बकम हाई रोड, पो.बा. सं. 1277, मद्रास-600087	118.	कर्नाटक	हवेली	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., तटीय लैण्ड, हवेली।
105.	तमिलनाडु	मद्रास	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., मार्फत आई.ओ.सी. लूबे ब्लॉकिंग प्लाट डिस्पेंच	119.	आन्ध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिबीजनल कार्यालय, 43 घ. गंगाजिनी पेनी रोड, पा० बा. सं. 1511, सिकन्दराबाद।
				120.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिस्पेंच यूनिट, मल्कापुरम, 314-प० विशाखापत्तनम-330011

1	2	3	4
121.	आन्ध्र प्रदेश		भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., एविएशन गैस स्टेशन, गन्नाबरम, हुवाई भडडा, वेकन फेडरी, एस.पी.ओ. 521102
122.	आन्ध्र प्रदेश	निजामाबाद	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. डिपो, निजामाबाद-503003
123.	आन्ध्र प्रदेश	मैसूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., "जी.एन.टी. टाई-524101 नेल्सोरजिला।
124.	आन्ध्र प्रदेश	बारांगल	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो गुड्डम शेड रोड, बारांगल-506002
125.	आन्ध्र प्रदेश	निडाडनोल	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो निडाडनोल-301
126.	आन्ध्र प्रदेश	रायचूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, रायचूर-101
127.	आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., मार्फत एच.पी.सी. एल. डिपो, डाडापेली-501, जिला गुन्टूर।
128.	आन्ध्र प्रदेश	सस्तनगर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, मार्फत 64 ए. एच.पी.सी.एल. डिपो, सस्तनगर।
129.	आन्ध्र प्रदेश	गुन्टकल	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, मार्फत एच.पी.सी.एल., अतुर रोड गुन्टकल।
130.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., चार्जपली डिपो (एल. पी.जी.), हैदराबाद।
131.	केरल	एर्नाकुलम	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिवाजनल कार्यालय, पो.बा. सं. 2622, एर्नाकुलम कोचीन-682031
132.	केरल	एर्नाकुलम	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., इंसपेक्शन पो.बा. सं. 2615, एर्नाकुलम, कोचीन-31
133.	केरल	कोचीन	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., कोचीन डिस्ट्रिक्ट यूनिट, मार्फत, आई.ओ.सी. सबल ममल, कोचीन-682302
134.	केरल	कन्नोर	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो, कन्नोर-670001
135.	तमिलनाडु	हराड	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., मार्फत एच.पी.सी. लि., डिपो, त्रिनोगानी रोड, इरोड-2]

1	2	3	4
136.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., तिरुपति एविएशन गैस, रंगुन्टम-7520

स्पष्टीकरण स्थापन

इस मामले में छूट को मूलतः प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था। आवेदन पत्र देरी से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को मूलतः प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[स.एस-38014/13/86-एम.एस.-11]

New Delhi, the 8th September, 1987

S.O. 2557.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S. O. 375 dated the 20th January, 1987, the Central Government hereby exempts the regular employees of the units of M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited specified in the schedule annexed hereto from the operation of the said Act for a period from 1st April, 1986 upto and inclusive of 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of:—
 - (i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period

when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to :—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register accounts book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the State/ Union territory	Name of Area	Name of Factory
1	2	3	4
1.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Chairman's Office, Bharat Bhavan, 4 & 6, Currimbhay Rd., Ballard Estate, Bombay-400038.
2.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Refining Division, Mahul, Bombay-400074.
3.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Bombay Area Office, Bharat Bhavan, 4 & 6, Currimbhay Rd., Ballard Estate, Bombay-400038.
4.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Bombay Divisional Office, 'E' & 'F' Maker Towers, 12th Floor, Cuffee Parade, Bombay-400065.

1	2	3	4
5.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Aircraft Service Station, Santacruz Aerodrome (Domestic) Santacruz, Bombay-400057.
6.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Bharat Petroleum Trading Centre, Trombay House, Juhu, Bombay-400054.
7.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Marine Oil Terminal, Butcher Island Bombay.
8.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Sewree, Bombay-400015.
9.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Malet Road, Wadi Bunder, Bombay-400009.
10.	Maharashtra	Bombay	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Trombay Despatch Unit, Refinery Site, Mahul, Bombay-400074.
11.	Maharashtra	Nagpur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. "Kanoria House", Palm Road, P.O. Box No. 17, Nagpur-440001.
12.	Maharashtra	Poona	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. 11, Dr. Coyaji Road, P. Box No. 61, Poona-411001.
13.	Maharashtra	Akola	Bharat Petroleum Corpn. Ltd Depot, Near Railway Station, Akola. Pin Code-444001.
14.	Maharashtra	Amravati	Bharat Petroleum Corporation Limited Depot Morshi Road, Amaravati, Pin Code-444601.

1	2	3	4	1	2	3	4
15.	Maharashtra	Manmad	Bharat Petroleum Corporation Limited Depot P.O. Box No. 6, Manmad-423103.	24.	Goa	Panaaji	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Goa Divisional Office "SHAN" Dr. Pissurlencar Rd., Panaaji (Goa) Pin Code-400001.
16.	Maharashtra	Nagpur	Bharat Petroleum Corporation Limited Depot, Opp. Phule Market, Nagpur-440016.	25.	Goa	Vasco-Da-Gama	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Despatch Unit. Vasco-Da-Gama, (Goa) Pin Code 403002.
17.	Maharashtra	Poona	Bharat Petroleum Corporation Limited Depot, 40/41, Dr. Ambedkar Road, P.B. No. 208, Opp. R.T.O. Poona-411001.	26.	Gujarat	Gandhi Nagar	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Kandla Installation P.B. No. 33, Post Gandhidham, Gujarat.
18.	Mahrashtra	Sholapur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Depot. P. Box No. 2, Sholapur-413001.	27.	Gujarat	Ahmedabad	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Ahmedabad Divisional Office, Mission Road, Bhadre, P.O. Box No. 52, Ahmedabad-380001
19.	Maharashtra	Sangli	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot. Chandan Wadi, Miraj, Sangli District, Pin Code-406410.	28.	Gujarat	Baroda	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Despatch Unit (Koyali), Jawahar Nagar, Dist. Baroda, Pin Code-391321.
20.	Maharashtra	Amara-vati	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, C/o IOC Depot. Behind Vijaya Mills, Badnera, Dist. Amaravati, Pin Code 444701.	29.	Gujarat	Ahmedabad	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Despatch Unit, Sabarmati Installation. Ahmedabad-380019.
21.	Maharashtra	Poona	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Loni Despatch Unit, C/o HPCL Installation, Loni, Poona District.	30.	Gujarat	Bhavnagar	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Aviation Service Station, Civil Aerodrome, Bhavnagar.
22.	Maharashtra	Kolhapur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Kolhapur Depot, Near Railway Station, Kolhapur.	31.	Gujarat	Bhuj	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Aviation Service Station, P.B. No. 29, Bhuj-370001.
23.	Maharashtra	Nagpur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Khapri Depot (LPG) Khapri, Dist. Nagpur.	32.	Gujarat	Surat	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Outside Sahara Gate, Surat, Pin Code 395003.

1	2	3	4	1	2	3	4
33.	Gujarat	Ahmedabad	Bharat Petroleum Corpn Ltd. Ahmedabad Bottling Plant, Ahmedabad.	42.	Madhya Pradesh	Raipur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Raipur Depot, Telghani Nake, P.O. Raipur, Pin Code-492001
34.	Madhya Pradesh	Bhopal	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Bhopal Divisional Office, C/2, B.D.A. Colony, Opp. Nagar Nigam Rest House, Near Link Road No. 3, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.) . Pin Code-462016.	43.	West Bengal	Calcutta	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Area Office, 31, Benoy Badal Dinesh Bag, P. Box No. 360 Calcutta-700001.
35.	Madhya Pradesh	Gwalior	Bharat Petroleum Corpn Ltd., Aviation Service Station, P.B. No. 9, Gwalior, Pin Code-474002.	44.	West Bengal	Calcutta	Bharat Petroleum Corpn Ltd., Divisional Office 31, Benoy Badal Dinesh Bag, P.O. Box No. 360, Calcutta-700001.
36.	Madhya Pradesh.	Raipur	B.C.C. Ltd., Gwalior-474002.	45.	West Bengal	Howrah	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Muarigram Despatch Unit, C/o IOC Installation P.O. Radhadasi, Howrah.
37.	Madhya Pradesh	Raipur	Bharat Petroleum Corporation Ltd., Raipur Aviation Service Station Raipur.	46.	West Bengal	Midnapore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Haldia Despatch Unit P.O. Haldia Oil Refinery, Dist. Mdinapore.
38.	Madhya Pradesh	Indore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot. 26, Park Road, Indore (M.P.) Pin Code-452003.	47.	West Bengal	Burdwan	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Rjabandh Despatch Unit, C/o IOC Installation P.O. Rjabandh, Dist. Burdwan, Pin Code-613212.
39.	Madhya Pradesh	Khandwa	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot Khandwa (M.P.) Pin Code-450001.	48.	West Bengal	Jalpaiguri	Bhaarat Petroleum Corporation Ltd. Jalpaiguri Despatch Unit, C'o IOC Installation, P.O. Bhaktinagar Dist. Jalpaiguri, Pin Code-734425.
40.	Madhya Pradesh	Jabalpur	Bharat Petroleum Corpn Ltd. Depot South Civil Lines Jabalpur (M.P.) Pin Code-482001.	49.	West Bengal	24 Parganas	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Budge Budge Installation, P.O. Budge Budge, Dist. 24 Parganas Pin Code-743319.
40.	Madhya Pradesh	Ratlam	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Ratlam (M.P.) Pin Code-457001.				
41.	Madhya Pradesh	Satna	Bharat Petroleum Corpn Ltd. Satna Depot, Satna.				

1	2	3	4	1	2	3	4
50.	West Bengal	Jalpaiguri	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Dalgeon Depot, P.O. Birpare Jalpaiguri Pin Code-735204.	58.	Bihar	Patna	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Patna Despatch Unit, P.O. Box No. 27, Patna-80001.
51.	West Bengal	Burdwan	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Rajbandh Depot, P.O. Rajbandh, Dist. Burdwan	59.	Orissa	Bhubaneswar	Bharat Petroleum Corporation Ltd., Bhubaneswar Divisional Office, Plot No. 121-B, Suryanagar, Unit VIII, P.O. Barmunda Colony P.O. Box No. 165, Bhubaneswar-751003.
52.	West Bengal	Calcutta	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Aviation Service Station, Dum Dum Airport Dum Dum Calcutta.	60.	Orissa	Cuttack	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Cuttauk Depot, Sekharpur P.O. Cuttack Pin Code-753003.
53.	Bihar	Patna	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Patna Divisional Office, Exhibition Road, P.O. Box No. 20, Patna-800 001.	61.	Orissa	Sambalpur	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Sambalpur Depot, P.O. Modipura, Dist. Sambalpur, Pin Code-768 002.
54.	Bihar	Begusarai	Bharat Petroleum Corporation Ltd., Baruki Despatch Unit, Post Box No. 1, Barauni Oil Refinery, Dist. Begusarai, Pin Code-851 114.	62.	Orissa	Ganjam	Bharat Petroleum Corpn Ltd., Barhampur Depot, P.O. Barhampur, Dist. Ganjam, Pin Code-768 008.
55.	Bihar	Dhanbad	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Dhanbad Depot, Dhanbad Bazar, Post Box No. 36, P.O. Dhanbad, Pin Code-826001.	63.	Assam	Bongaingaon	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Bongaingan Despatch Unit, C/o IOC Post Daligaon-783385, Gonalpura
56.	Bihar	Ranchi	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Ranchi Depot, Station Road, P.O. Chutia, Ranchi, Pin Code:834001.	64.	Assam	Duliajam	Bharat Petroleum Corpn Ltd., Duliajam Despatch Unit (LPG) C/o IOC, Post Duliagaon-783385, Gonalpura.
57.	Bihar	Singhbham	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Tatanagar Depot, Burma Mines, Goods Shed Road, P.O. Tatanagar, Dist. Singhbhum, Pin Code-831002.	65.	Assam	Gauhati	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Despatch Unit, C/o HPCL Gauhti, Pin Code-781020.
				66.	U.T. of Delhi	New Delhi	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Delhi Area Office E.C.E. House, Post Box No. 7, Connaught Circus, New Delhi-110001.

1	2	3	4	1	2	3	4
67.	U.T. of Delhi	New Delhi	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Delhi Divisional Office, G-7, Laxmi Building, II & III Floor, P. Box. No. 396, New Delhi-110001.	77.	Uttar Pradesh	Gorakhpur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot. Near Goods Shed, Dharamshala Road, Gorakhpur-273001.
68.	U.T. of Delhi	New Delhi	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Project Office, 8-B, Hansalaya, 15, Barakhamba Road, New Delhi-110001.	78.	Uttar Pradesh	Kanpur	Bharat Petroleum Corporation Ltd., Despatch Unit, C/o IOC Installtion, P.O. Panki Power House, Kanpur-208020.
69.	U.T. of Delhi	Shakurbasti	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Shakurbasti Installation Shakurbasti, New Delhi.	79.	Uttar Pradesh	Kanpur	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Kanpur Depot, Fazalganj, Kanpur-208012.
70.	U.T. of Delhi	Shakurbasti	Bharat Petroleum Corpn. Ltd, Shakurbasti LPG Bottling Plant, Shakurbasti, New Delhi.	80.	Uttar Pradesh	Allahabad	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Allahabad Despatch Unit, P.O. Box No. 44, C/o IOC, Subedarganj, Allahabad-211001.
71.	U.T. of Delhi	Palam	Bharat Petroleum Corpn. Ltd, Indira Gandhi Inter-national Airport, Terminal I, New Delhi.	81.	Uttar Pradesh	Mughalsarai	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Despatch Unit, C/o IOC Installation, Mughalsarai.
72.	U.T. of Delhi	Bijwasan	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Bijwasan Installation, Bijwasan, New Delhi.	82.	Uttar Pradesh	Mathura	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., BPC Despatch Unit, S & D Building, Opp. Gate No. 9, Mathura Refinery. Mathura.
73.	U.T. of Delhi	Bijwasan	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. IOC Terminal, Bijwasan Despatch Unit Bijwasan, New Delhi.	83.	Uttar Pradesh	Meerut	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Abuka Makbara, Meerut.
74.	Uttar Pradesh	Bareilly	Bharat Petroleum Corpn. Ltd, Bareilly Divisional Office 35/11-B, Civil Lines Bareilly-243001 (U.P.).	84.	Uttar Pradesh	Saharanpur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Depot, Grand Road, Saharanpur-247001.
75.	Uttar Pradesh	Lucknow	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, 94, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001.	85.	Uttar Pradesh	Moradabad	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Depot, Rampur Road, Moradabad-244001.
76.	Uttar Pradesh	Agra	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Chhaun-Ka-Nagla, Pratappura, Idgah, Agra-282001.	86.	Uttar Pradesh	Bareilly	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Bareilly Bottling Plant, Bareilly (U.P.)

1	2	3	4	1	2	3	4
87.	Rajasthan	Jodhpur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Rai-Ka-Bagh, Jodhpur.	96.	Punjab	Pathankot	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Dhaki Road, Near Railway Station, Pathankot-145001.
88.	Rajasthan	Jaipur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Divisional Office, Old Residency Road, Jaipur South, P.Box No. 106 Jodhpur-302001 (For P. Box Delivery) 302006 (For Office Delivery.)	97.	Punjab	Jalandhar	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Near Railway Goods Shed Jalandhar City, Jalandhar-144004.
89.	Rajasthan	Jaipur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Jaipur Depot, Bais Godam Jaipur Soutn -302001	98.	Punjab	Jalandhar	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., IOC Pipeline & LPG Bottling plant, Suchi Pind, Jalandhar.
90.	Rajasthan	Ajmer	Bhara Petrooleum Corpn. Ltd., Tope Dhara, Near Ralway Crossng, Ajmer-205001.	99.	Haryana	Hissar	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Depot, Near Railway Station, Hissar-125001.
91.	Rajasthan	Udiapur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Udaipur Depot, Udaisagar Road, Udaipur-313001.	100.	Haryana	Hissar	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Hissar Bottling Plant, Hissar.
92.	Rajasthan	Kota	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Kota Depot, Near Goods Shed, Kota	101.	Haryana	Ambala	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Despatch Unit, Near Shastri Colony, G.T. Road, Ambala-133001.
93.	Rajasthan	Jaipur	Bharat Petroleum Corpon. Ltd., Jaipur Bottling Plant, Jaipur.	102.	Tamilnadu	Madras	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Area Office, 7, Kodambakkam High Road, P. Box. No. 1277, Madras-600034.
94.	U.T. of	Chandigarh	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Chandigarh Divisional Office, Block No. 70 & 71, Sector No. 17, New Bank of India Building, P. Box No. 39 Chandigarh-160017.	103.	Tamilnadu	Madras	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Divisional Office, No. 7, Kodambakkam High Road, P.Box No. 1277, Madras-600034.
95.	Punjab	Patiala	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Depot, Near Railway Goods Shed, Factory Area, Patiala-147001.	104.	Tamilnadu	Madras	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Tondiarpet Installation, Tondiarpet, Madras-600081.

1	2	3	4	1	2	3	4
105.	Tamilnadu	Madras	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., C/o I.O.C. Lube Blending Plant, Despatch Unit, Ennore High Road, Madras-600081.	116.	Karnataka	Mangalore	Bharat Petroleum, Corpn. Ltd. Mangalore Depatch Unit Mangalore Karnataka.
106.	Tamilnadu	Coimbatore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Depot, Coimbatore-641001.	117.	Karnataka	Bangalore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Bangalore Depot (LPG) Bangalore Karnataka.
107.	Tamilnadu	Madurai	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Depot, Madurai-625001.	118.	Karnataka	Hubli	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Tabit Land, Hubli.
108.	Tamilnadu	Tirunalvelli	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Tirunalvelli-627001.	119.	Andhra Pradesh	Secundrabad	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Divisional Office 45A, Sarojini Devi Road Post Box No. 1511 Secunderabad.
109.	Tamilnadu	Trichirapalli	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Depot, Trichirapalli-620001.	120.	Andhra Pradesh	Visaknapatnam	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Despatch Unit. Malakapuram, P.O. Visaknapatnam-530011.
110.	Tamilnadu	Coimbatore	Bharat Petroleum Corporation Limited, Installation Post Box No. 1644, Peelamedu, Coimbatore, Pin Code-641004.	121.	Andhra Pradesh		Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Aviation Service Station Gannavaram Aero- drome Becon Factory S.P.O. 521102,
111.	Tamilnadu	Coimbatore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Coimbatore LPG Bottling Plant Peela- medu, Coimbatore-641004.	122.	Andhra Pradesh	Nizamabad	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Nizamabad-503003.
112.	Karnataka	Bangalore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Divisional Office, 'The Laurels' 2-C Residency Road, P.O. No. 2575, Bangalore.	123.	Andhra Pradesh	Nellore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot G.N.T. Road, Tada 524101, Nellore DT,
113.	Karnataka	Bangalore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Installation Banawadi Maruthi Seva Nagar Post Box No. 3305, Bangalore-560033	124.	Andhra Pradesh	Warrangal	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Goods Shed Road, Warangal 506002.
114.	Karnataka	Mysore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Mysore-570021.	125.	Andhra Pradesh	Nidadvole	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot Nidadvole-534301.
115.	Karnataka	Mangalore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot Mangalore-575001.	126.	Andhra Pradesh	Raichur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot, Raichur 534101.
				127.	Andhra Pradesh	Guntur	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot C/o HPCL Depot Tarapelli-522501, Distt. Guntur,

1	2	3	4
128.	Andhra Pradesh	Sanatnagar	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot. C/o 64-A HPCL Depot. Santanagar.
129.	Andhra Pradesh	Guntakal	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot. C/o HPCL Atur Road, Guntakal.
130.	Andhra Pradesh	Hyderabad	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Charlapelli Depot (LPG) Hyderabad.
131.	Kerala	Ernakulam	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Divisional Office, Post Box No. 2622, Ernakulam Cochin-682031.
132.	Kerala	Ernakulam	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Installation Post Box No. 2615 Ernakulam Cochin-682031.
133.	Kerala	Cochin	Bharat Petroleum Corpn. Ltd.. Cochin Despatch Unit C/o IOC Ambal Magal Cochin-682302.
134.	Kerala	Connanore	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Depot Cannanore-670001.
135.	Tamilnadu	Erode	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. C/o HPCL Depot, Chenamali Road, Erode-638002.
136.	Andhra Pradesh.	Tirupati	Bharat Petroleum Corpn. Ltd. Tirupati Aviation Service Reingunta-517520.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/13/86 SSI]

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1987

वा.सं. 2558.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :-

1. मैसर्स रुक्मंगदान इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्टर 95/101, 11, मेन रोड, चामराजापेट बंगलौर-18

2. मैसर्स विमानार एंड कंपनी, नं. 55, 13, क्रॉस 4 मेन रोड मालेश्वरम्, बंगलौर-3

3. मैसर्स प्रिडिशन इंडस्ट्रियल कम्पोनेंट्स, एम एम इंडस्ट्रियल स्टेट, बंगलौर-82

4. मैसर्स डी एम एम प्रिंटिंग इन्क प्राईवेट लि., 105, 5वां क्रॉस एस आई एरिया, राजाजीनगर, बंगलौर-18

5. मैसर्स मारा सिन्हाहल्ली मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ओपरेटिव सोसाइटी लि., मद्दूर तालुक मादया कस्बा

6. मैसर्स मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ओपरेटिव सोसाइटी लि., गुरूर, मद्दूर तालुक, मादया कस्बा

7. मैसर्स हुरुगलवादी मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ओपरेटिव सोसाइटी लि., मद्दूर तालुक मादया कस्बा

8. मैसर्स प्राइमरी को-ओपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड परियापत्ता, मैसूर कस्बा

9. मैसर्स डालफिन डिटेक्टिव एजेंसी ट्रेडिंग प्रासिवेलीड मुरुसावी मट रोड, एनचेतगिरी स्ट्रीट हुबली-28

10. मैसर्स आर्लिड गैस लि., 8/18/20, सतूर इंडस्ट्रियल स्टेट पोस्ट ऑफिस सतूर धरवाड और इसके हुबली और बेलगांव स्थित डिपो

11. मैसर्स सारस स्माल टूल्स इंडस्ट्रीज नं. 16 हास्पिटल रोड, बंगलौर-53 और इसकी बंगलौर-26 स्थित शाखा

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एम-35019(39)/87-एम एम-2]

New Delhi, the 9th September, 1987

S.O. 2558.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely,

1. M/s. Rukmangandan Engineering Contractor, 95/101, Hind Main Road Chamarajapet, Bangalore-18.

2. M/s. Beeyannar and Company, No. 55, 13th Cross, 4th Main Road Malleswaram, Bangalore-3.

3. M/s. Precision Industrial Components, M.M. Industrial Estate, Bangalore-82.

4. M/s. D.M.M. Printing Inks Private Limited, 105, 5th Cross, S.S.I Area, Rajajinagar, Bangalore-10.

5. M/s. Marasinganahalli Milk Producers Co-operative Society Limited, Maddur Taluq, Mandya District.

6. M/s. Milk Producers Co-operative Society Limited, Gulur, Maddur Taluk Mandya District.

7. M/s. Hurugalavadi Milk Producers Co-operative Society Limited, Maddur Taluk, Mandya District.

8. M/s. Primary Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Limited, Periyapathna, Mysore District.

9. M/s. Dolphin Detective Agency, Traffic Island Murusavee Mutt Road, Ancharageri Street, Hubli-28.

10. M/s. Allied Gases Limited, 8/18/20, Sattur Industrial Estate Post Office Sattur, Dharwad, including its Depots at Hubli and Belgaum.

11. M/s Saras Small Tools Industries No. 16 Hospital Road, Bangalore, 53, including branch at Bangalore-26.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(39)/87-SS-II]

का.आ. 2559.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी प्रविष्टि निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित लागू किये जाने चाहिए :-

1. मैसर्स बेट कैम्पिन, सी डी ए, वेस्टर्न कमान्ड, सेक्टर-9, चंडीगढ़
2. मैसर्स चैम्बर आफ इंडस्ट्रियल एंड कमिश्नियल एण्डरटेकिंग, गिल रोड, लुधियाना
3. मैसर्स डिपार्टमेंटल कैम्पिन महालेखाकार का कार्यालय, (हिमाचल-प्रदेश) शिमला

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एम - 35019(35)/87 - एम. एम.-2]

S.O. 2559.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Wet Canteen, C.D.A. Western Command Sector-9, Chandigarh.
2. M/s. Chamber of Industrial and Commercial Undertakings Gill Road, Ludhiana.
3. M/s. Departmental Canteen, Office of the Accountant General (H.P.) Shimla.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(35)/87-SS. II]

का.आ. 2560.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 16(1) के अनुसरण में श्री के. सी. शर्मा, के स्थान पर श्रीमती कुसुम प्रसाद, भारतीय पत्र संचिक सेवा अधिकारी को सितम्बर 1987 के 9वें दिन के अग्ररातन से आगामी आदेश जारी होने तक महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए - 12026/3/87 - एम. एम. - 1]

S.O. 2560.—In pursuance of section 16(1) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints Smt. Kusum Prasad, an officer of the Indian Administrative Services (Rajasthan : 1960) as Director General, Employees' State Insurance Corporation with effect from the afternoon of the 9th September, 1987, until further orders vice Shri K. C. Sharma.

[No. A-12026/3/87-SS. I]

का.आ. 2561.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी प्रविष्टि निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध

अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :-

1. मैसर्स मानक टूल्स, एम-46/9 जी आई डी सी फेज-3, तरोडा, अहमदाबाद-30
2. मैसर्स एग्रोमिन टूल्स प्राइवेट लि., स्टेट हाईवे नं. 68 पलाया देहगम-5 जिला अहमदाबाद
3. मैसर्स जय ट्विस्टिंग वर्क्स, प्लॉट नं. 115 रोड नं. 8बी उद्योग, उद्योग नगर, उद्योग, जिला सुरत
4. मैसर्स डी एम ट्विस्टिंग वर्क्स, प्लॉट नं. 115 रोड नं. 8बी, उद्योग, उद्योग नगर, उद्योग, जिला सुरत
5. मैसर्स धायरस ट्विस्टिंग इंडस्ट्रिय रोड नं. 8बी, प्लॉट नं. 114 उद्योग, उद्योग नगर, उद्योग, जिला सुरत
6. मैसर्स जे. बी. इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं. 115 रोड नं. 8बी, उद्योग-नगर, उद्योग जिला सुरत
7. मैसर्स नवीन सिल्क इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं. 115 रोड नं. 8 बी, उद्योग नगर, उद्योग, जिला सुरत
8. मैसर्स पंकज इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं. 114 रोड नं. 8 बी, उद्योग नगर उद्योग, जिला सुरत
9. मैसर्स निर्माण बिल्डर्स (इंजीनियर्स एंड कन्स्ट्रक्टर्स), 13 ए सेवाश्रम सोसाइटी, रासीग राज्वा ज्योति आश्रम, इलीग पार्क, बड़ीदा-7
10. मैसर्स एस स्टॉज इंडस्ट्रीज, सी/11 शान्ताथ इंडस्ट्रियल स्टेट प्रजीव मिश्र के पीछे, राशिपाल अहमदाबाद
11. मैसर्स गऊतलाय आश्रम मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि., कमला ग्राम रोड, नवियाद
12. मैसर्स गुजरात इन्वैस्टीमेंट्स लि., 805-806 जी आई डी सी अकम्पवर और इसका इसी जगह स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एम - 35019(40)/87 - एम. एम.-2]

S.O. 2561.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Manek Tools, L/46/9, GIDC. Phase-III, Navada, Ahmedabad-30.
2. M/s. Agromin Tools Private Limited, State Highway No. 68, Pal-aya Dehgam-5, District Ahmedabad.
3. M/s. Jay Twisting Works, Plot No. 115, Road No. 8-B, Udhna, Udyognagar, Udhna, District Surat.
4. M/s. P. M. Twisting Works, Plot No. 115, Road No. 8-B, Udhna Udyognagar, Udhna, District Surat.
5. M/s. Dhairesh Twisting Industries, Plot No. 114, Road, No. 8-B, Udhognagar, Udhna District Surat.
6. M/s. J. B. Industries, Plot No. 115, Road No. 8-B, Udyognagar, Udhna District Surat.
7. M/s. Navin Silk Industries, Plot No. 115, Road No. 8-B, Udhognagar, Udhna, District Surat.
8. M/s. Pankaj Industries, Plot No. 114, Road No. 8-B, Udhognagar, Udhna District Surat.

9. M/s. Nirman Builders (Engineers and Contractors 13-A, Sevashram Society, Near Atma Jyoti Ashram, Ellora Park, Baroda-7.
11. M/s. Banas Steel Industries, C/11, Jagannath Industrial Estate, Behind Ajit Mills, Rakhilal, Ahmedabad-23.
11. M/s. Mafatlal Apparel Manufacturing Company Limited, Kamlagram Road, Nadiad.
12. M/s. Gujarat Insecticides Limited, 805-806, GIDC. Ankleshwar, including its Registered Office at the same place.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(40)/87-SS. II]

का. आ. 2562.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए:—

1. मैसर्स हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन (भारत) लि., तृतीय मंजिल, भारतीय कला केन्द्र बिल्डिंग, 1, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-1
2. मैसर्स डेट लाइन फोटोसेटर्स, 44 चांदनी चौक (भारतीय स्टेट बैंक के सामने) दिल्ली-6
3. मैसर्स पब्लिक एन्टरप्राइजिज सर्विसेज एसोसिएशन ई-374, निर्माण बिहार, दिल्ली-92

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एन-35019(38)/87-एस.एस.-2]

S.O. 2562.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. Hospital Services Consultancy Corporation (India) Ltd., 3rd Floor, Bharatia Kala Kendra Building, 1, Copernicus Marg, New Delhi-1.
2. M/s. Dateline Photosetters 44, Chandni Chowk, (Opp. State Bank of India) Delhi-6.
3. M/s. Public Enterprises Services Association, E-374, Nirman Vihar, Delhi-92.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019 (38)/87-SS. II]

का. आ. 2563.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए:—

1. मैसर्स डिपार्टमेंटल कैंटीन, सैन्ट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, त्रिवेन्द्रम
2. मैसर्स थोटाकाट डिस्टिलेरिज, एडायर, अलवाय, एरनाकुलम कम्बा
3. मैसर्स पैको एल्ट्राप्राइजिज, श्रीनिवास चैम्बर, एन जी रोड, अरनाकुलम, कोचीन-35

4. मैसर्स पैको इलेक्ट्रॉनिक्स XXXVIII-एफ, श्रीनिवास चैम्बर, एन जी रोड, अरनाकुलम कोचीन-35
5. मैसर्स इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विपमेंट प्राइवेट लि. XXVIII/820 एनएम पिल्ली नगर, अरनाकुलम, कोचीन-15
6. मैसर्स कोचिन अरबन सैमोरी ट्रीटमेंट एण्ड एजुकेशन स्कीम (कलटैम) परम्पदाप्पू, कोचीन-6 रामेश्वरम् गांव अरनाकुलम
7. मैसर्स एन० एम० एस० होमियो मेडिकल डिग्री कालेज, मचची-यामापुरम पोस्ट आफिस कोटायम, कम्बा कुम्बा
8. मैसर्स श्याम मोटर एण्ड एग्रीकल्चरल इम्प्रोवमेंट गांव, केन्नूर ताल्लुक, केन्नूर कम्बा
9. मैसर्स श्री अय्यप्पा काथियाकुदम कालिमन व्यवसाय को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि० काथियाकुदम पोस्ट आफिस कोरट्टी त्रिचुर
10. मैसर्स फ्लेक्शन आर्टो स्टील प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लि०, के०के० 136-बी, साऊथ बाजार केन्नूर ताल्लुक एंड कम्बा और इसकी 16 नार्थ वेली स्ट्रीट कमलाथोप लेन मद्रुरई-1 स्थित शाखा

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(37)/87-एस०एस-2]

S.O. 2563.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. Departmental Canteen, Central Telegraph Office, Trivandrum.
2. M/s. Thottakat Distilleries, Edayer, Alwaye, Ernakulam District.
3. M/s. Paico Enterprises, Srinivas Chambers, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-35.
4. M/s. Paico Electronics, XXXVIII, F, Srinivas Chambers, M.G. Road, Ernakulam, Cochin-35.
5. M/s. Electrical Control Equipment Private Limited, XXVIII/826-A, Panampillary Nagar, Ernakulam, Cochin-15.
6. Ms. Cochin Urban Leprosy Treatment and Education Scheme (Cultes. Perumpadappu, Cochin-6, Rameswaram Village, Ernakulam District.
7. M/s. NSS Homco Medical Degree College, Sathive-thamapuram, P. O. Kottayam District Kurichy.
8. M/s. Shyam Motors, Payangadi, Eaxhom Village, Cannore Taluk, Cannore District.
9. M/s. Sree Ayyappa Tiles Kaithakundam Kalimon Vyavasaya Co-operative Society Limited, Kaithakundam Post Office Koratty, richur.
10. M/s. Fyexon Auto Steel Products (Private) Limited, K. K. 136, B. South Bazar Cannore Taluk and District, including its branch at 16, North Veli Street, Kamalathope Lane, Madurai-1.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishment.

[S. 35019 (37)/87-SS.-II]

का० आ० 2564.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स नेशनल इन्वियरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली अक्टूबर, 1984 से 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान बंशित किये जाएंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संवत् अभि-
धायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संवत् किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (5) निम्न द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षण या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी —
 - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
 - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
 - (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, तबक और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
 - (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा, —

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और भजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकारी या सेवा की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

सफ्टीकरण आपन

इस मामले में छूट को भूतलवी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पत्र देरी से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलवी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस-38014/82/86-एस०एस-1]

S.O. 2564.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1984 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in the behalf shall, for the purposes of:—
 - (i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowers to:—
 - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not effect the interest of anybody adversely.

[F. No. S-38014/82/86-S-4]

का०आ० 2565:—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 9-क के माध पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक, सुल्बई के स्टेट बैंक कम्प्यूटर केन्द्र के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहले अप्रैल, 1984 से 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह नार्च्यल सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, उसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्जित किए जाएंगे;
- (2) इस छूट के होने हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रमुखियां प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिनियम द्वारा दी गई छूट के प्रयुक्त होने की तारीख से पूर्व संवत् अधिनियमों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अधिकार पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जायेंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (5) निम्न द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन निवृत्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निमित्त का कोई अन्य पदधारी:—
 - (i) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई निम्न विवरणों की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
 - (ii) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अधिष्ठित उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या;

(iii) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुखियों को जो ऐसी प्रमुखियां हैं जिनके फलस्वरूप इस अधिनियम के अधीन छूट दी जा रही है, नगद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशकत होगा:—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिवार में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखावहियां और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक ही, उसके अधिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिवार में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने या युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा पास करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिवार में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखावहियों या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

स्पष्टीकरण प्राप्त

इन मामलों में छूट को भूतलजी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट को आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलजी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिभूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस-38014/77/86-एस०एस०I]

S.O. 2565.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91-A of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the State Bank of India, Computer Centre, Bombay from the operation of the said Act for a period with effect from 1st April, 1984 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns

in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employee's State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :—

- (i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employee's State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowers to :—
 - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
 - (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
 - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
 - (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

[F. No. S-38014/77/86-SS. I]

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1987

का० आ० 2566.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मारमामोबा पत्तन ग्यास, मारमामोबा के अधीन कार्यशाला के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली अक्टूबर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, को अर्थात् के लिए छूट देता है। उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पेशगीर्तन दर्शाए जायेंगे।

(2) इस छूट के तहत हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्रमुखिधार्ता प्राप्त करेंगे, जिनका पान के लिए वे इस अधिनियम द्वारा दी गई छूट के प्रभुता होने की तारीख से पूर्व संरक्षित अभिलेखों के आधार पर हकदार हो जायेंगे ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिलेख पहले ही संरक्षित किया जा चुका है तो वे पान नष्ट किए जायेंगे ;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उक्त अधि की शर्तों जिसके दौरान उक्त कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधि कड़ा गया) ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रमुख में और ऐसी विवरणियाँ सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अधि की बखत देनी थी :

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी, —

- (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अर्थात्, उक्त अधि की शर्तों की गई किसी विवरणों की विवरणियों की सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
- (ii) यह अभिलेखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा गया अभिलेखित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
- (iii) यह अभिलेखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उक्त प्रमुखिधार्ता को, जो ऐसी प्रमुखिधार्ता है जिनके प्रतिकलम्बन इस अधिनियम के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और बन्धु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या
- (iv) यह अभिलेखित करने के प्रयोजनों के लिए कि उक्त अधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किसी उपाय का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सक्षम होगा :—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक में यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे या ;
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिनियम के कारखाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उक्त कारखाने के व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह वर्गियों के विवरण और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी विवरणियाँ और अन्य वस्तुओं, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकारी या मेसक का या ऐसे किसी व्यक्ति का जो ऐसे कारखाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति का जिसके घर में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विवरण करने का दायित्व का कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखावही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं. एम-38014/34/86-एस.एस.-I]

ए.के. अहलुवालिया, अधीक्षक सचिव

स्वच्छीकरण शासन

इस मामले में छूट की भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट की भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 2566.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1984), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Workshop under the Mormugao Port Trust, Mormugao from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in the behalf shall, for the purposes of—
 - (i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be employers to—
 - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/34/86-SSI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1987

का. आ. 2567 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., रांची के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd September, 1987

S.O. 2567.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bihar State Mineral Development Corporation Limited, Ranchi and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(i)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 2 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to Palamau Khan Mazdoor Sangh Daltanganj, Dist. Palamau on the management of Disrampur, Manasoti Graphite Mines and Semra Dolomite and Magnetite Mine of Bihar State Mineral Development Corporation.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N. B. Ghosal, Officer-On-Special Duty, Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. Ranchi.

For the Workmen—Sri Satyapal Verma, President, Palamau Khan Mazdoor Sangh, Daltanganj.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Mineral

Dhanbad, dated the 11th August, 1987

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-29011(5) 81-D.III(B) dated the 6th January, 1982 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :

(1) Whether the action of the management of Bihar State Mineral Development Corporation in terminating the services of 37 workmen employed in their various mines as detailed in Annexure, I with effect from 22-3-1980 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

(2) Whether the action of the management of Manasoti Ladwa Khan Magnesite Mine of Bihar State Mineral Development Corporation in terminating the services of the following seven workmen in August 1978 without payment of retrenchment compensation and without giving requisite notice, was justified. If not, to what relief by way of notice pay, retrenchment compensation for past period of service etc. are the workmen entitled?

1. Luruk Mochi.
2. Bilakh Mochi.
3. Tapeswar Singh.
4. Kailash Ram.
5. Bahadur Singh.
6. Raj Mohan Singh.
7. Nandu Mochi.

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accepted it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-29011/5/81-D.III(B)]

Memorandum of settlement arrived at between the management of the Bihar State Mineral Development Corporation Ltd, Ranchi and their workmen represented by the Palamau Khan Mazdoor Sangh, Daltanganj in course of mutual negotiation held on 6th July, 1987 at Ranchi.

Representing Employees :

1. Sri U. K. Choubey,
General Manager (Adm.)
2. Sri N. B. Ghoshal,
Officer on Special Duty.

Representing Workmen :

1. Sri Satyapal Verma, President,
Palamau Khan Mazdoor Sangh.
2. Sri K. M. Dubey, Treasurer,
Palamau Khan Mazdoor Sangh.

Short recital of the Case

The Government of India in Ministry of Labour vide their notification No. L-29011(5)/81-D III(B) dated the 6th January, 1982 referred the following matters for adjudication before the Central Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as provided for in the clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

1. Whether the action of the management of Bihar State Mineral Development Corporation Ltd., in terminating the service of 37 workmen employed in their various mines as detailed in Annexure I with effect from 22-3-1980 is justified if not, to what relief the workmen are entitled?
2. Whether the action of the management of Manasoti Ladwa Khar Magnesite Mines of Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. in terminating the services of the following seven workmen in August, 1978 without payment of retrenchment compensation and without giving requisite notice, was justified? If

not to what relief by way of notice pay, retrenchment compensation for past period of service etc. are the workmen entitled?

1. Luruk Mochi 2. Bilak Mochi 3. Tapeswar Singh 4. Kailash Ram 5. Bahadur Singh 6. Raj Mohan Singh 7. Nandu Mochi. This reference bears the number as Reference No. 2/1982 in the Central Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad. During the pendency of the matters before the Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, the parties to the dispute entered into mutual negotiations with a view to resolve the dispute with due intimation to the Hon'ble Tribunal. The matter was mutually discussed on several dates and ultimately in the mutual negotiation held on the 6th July, 1987 of Ranchi the following settlement arrived at between the parties :—

I—Regarding Termination of 37 (thirty seven) work-men.—

1. It was agreed between the parties that as since then Sarbasri, Nandu Vishwakarma, Suresh Kumar Singh, Om Prakash Pandey, and Raj Pati Ray, have been taken back in service and since Sri Niyazuddin Mian had died, there remains no dispute in respect of these workmen.
2. The Union representing the workman has conceded the remaining 32 (thirty two) workmen and have come to the conclusion that only the following 18 (eighteen) workmen are interested in the dispute and the remaining are not because they are either more gainfully employed else where and/or not interested in the employment of the Corporation.
1. Sarbasri, Suraj Narain Sukla, 2. Nizabuddin Mian 3. Audhesh Kumar Dubey 4. Kanchan Dubey, 5. Akal Mahto 6. Bihari Dubey 7. Harbansh dubey 8. Deo Muni Singh 9. Rishiraj Fathak 10. Nand Lal Prasad 11. Ram Pravesh Singh 12. Indra Deo Yadav 13. Promod Prasad Singh, 14. Seo Shankar Singh 15. Raghubar Singh, 16. Ram Chandra Singh, 17. Ram Chandra Sao, 18. Ambika Ram.
3. It was agreed between the parties that the above mentioned 18 (eighteen) persons be re-employment in the services of the Corporation on the conditions as follows :—
 - (a) That these eighteen persons will be re-employed in two phases viz first eleven in the first phase and the remaining seven three month thereafter.
 - (b) That the intervening period between the date of their termination re-employment will be treated as leave-without pay and hence will not be entitled to any payment.
 - (c) That before giving employment to each of these persons their identity will be checked/verified by a proper agency of the management in which the Union will be represented.
 - (d) That there will be no reduction in the terms and conditions of their services which they were entitled before the termination.
 - (e) That one month's time will be given to the concerned persons to join duty otherwise he shall forfeit the claim to the job.
4. That there remains no dispute in respect of the remaining 14 (fourteen) persons :—

II—Retrenchment Compensation to Seven workmen.

1. It is agreed between the parties that the payment will be made to the concerned seven workmen as per provision of the law.

This agreement fully and finally settles the matters pending before the Honble Central Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, being ref. No. 2/82.

Representing Employers :

1. (U. K. Choubey)
General Manager (Adm.)
2. (N. B. Ghoshal)
Officer on Special Duty.

Representing Workmen :

1. (Satyapal Verma).
President, Palamau Khan
Mazdoor Sangh
2. (K. M. Dubey)
Treasurer, Palamau Khan
Mazdoor Sangh

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

का. प्र. 2568.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, कुदरेमुख आयरन ऑर कंपनी लि., बंगलौर के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-8-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2568.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kudremukh Iron Ore Company Limited, Bangalore and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT BANGALORE

Dated the 13th Day of August, 1987

PRESENT :

Sri B. N. Lalge, B.A. (Hons) LL.B.,—Presiding Officer
Central Reference No. 5/1987
(Old No. C.R.2/1981)

I PARTY : Vs. II PARTY:

Workman Shri O. P. Bhaskaran
Nair, represented by the
General Secretary,
Mineral Miners' Union,
Chickmagalur, Karnataka.
The Chairman & Managing
Director, M/s. Kudremukh
Iron Ore Co., Ltd.,
M. G. Road, Bangalore-1.

APPEARANCES :

For the I Party, Sri N. G. Phadke, Advocate, Bangalore.
For the II Party, Sri B. C. Prabhakar, Advocate, Bangalore.

AWARD

The present reference was referred to the Industrial Tribunal of the State Government By Order No. L-11025/A/

87-D IV(B) dated, 13-2-1987, the case has been transferred to this Tribunal. The point of reference is as shown below:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kudremukh Iron Ore Company Limited, Bangalore in discharging from their service Sri O. P. Bhaskaran Nair, Junior Operator-cum-Mechanic Grade I with effect from 9-7-79 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The I Party workman has then filed his claim statement. He contends as follows :

He was working as Junior Operator-cum-Mechanic Grade I. He was served with a charge sheet dated 27-1-79. He gave his reply dated 1-2-79. The II Party has then conducted the domestic enquiry and as a consequence he was discharged from service by a letter dated 9-7-79. The charge sheet issued to him was vague. The explanation given by him indicates that Mohiddeen has committed certain acts that the management did not held any enquiry against him. Only officers were made to give evidence in the enquiry held against him. The said enquiry is not in accordance with the principles of natural justice. The management was vindictive. The action of the management was arbitrary, the punishment is too harsh. The order may be set aside and he may be reinstated with consequential benefits.

3. The management has filed its counter statement and contentions are as follows :

The dispute is not an industrial dispute and there is no proper espousal. He was posted to work in the night shift of 25-1-79. At about 6 a.m. on 26-1-79 he started checking as to whether any workman had come for work in the first shift of 26-1-79 and he found one Sri Mohiuddin Operator-cum-Mechanic Grade-II, has come for work. The workman questioned him as to why he had come for work. The workman further got angry with him and shouted at him saying as to why he was not following the other workers. The workman interfered with the smooth working of the Department and when Mohiuddin refused to accede, the workman assaulted him and further threatened him saying that he will see him later in the Town. These acts were very serious and grave. The management therefore issued a charge sheet to him. He gave his explanation dated 1-2-79. It was not satisfactory. A two member enquiry committee was constituted. He was given all the opportunity in the enquiry. The enquiry committee gave its report, the findings were accepted by the management and then he was discharged by an order dated 9-7-79. Sri Mohiuddin had committed no act of misconduct there was no cause to held any enquiry against him. The allegation of vindictiveness is an after thought. The management is not aware of his trade union activities. The order of discharge is fair and proper. In case the domestic enquiry is set aside it may be permitted to prove the charge by adducing evidence. The reference may be rejected.

4. On 13-1-82 this Tribunal has framed the following issues :

1. Whether the dispute referred is not an Industrial Dispute as there was no proper espousal?
2. Whether the domestic enquiry is just and according to the principles of natural justice?
3. Whether the punishment imposed is proper?

5. After recording the evidence and hearing the arguments the first two issues which were taken up as preliminary issues have been disposed of by an order dated 30-10-82. On first issue it has been held that it shall be deemed to be an Industrial Dispute under Section 2-A of the Industrial Disputes Act. On issue No. 2 it was held that the domestic enquiry held against the workman is not valid. However, the management was given an opportunity to establish its charge by adducing evidence. The parties were also called upon to adduce on the rest of the points.

6. The management has examined mine witnesses and has got marked exhibits M-1 to M-28. The workman has examined himself and one witness and has got marked exhibits W-1 to W-22. The parties have been heard.

7. My findings on the points of dispute and the third issue are as follows :

Points of dispute.—The management was justified in discharging the workman.

Issue No. III : The punishment imposed is proper. He is not entitled to any relief.

8. Reasons :

Points of Dispute & Issue No. 3.—MW-1 Sri K. S. V. Murthy was a member of the enquiry committee. This evidence is on the point of additional issue No. 2. Since the issue had been already answered the evidence of MW-1 is of no consequence as regards the point of reference.

9. The record discloses that the workmen intended that the Republic day falling on 26th January should be a non-working day for all the employees. The management on the other hand was very particular to save time and expedite the work, since it was time bound project of national prestige and linked with contractual obligations to certain countries. The management had the practice of giving the national holiday to all except to those who so ever was called upon to work on that day would get an alternate off day at his choice. The workmen, it appears contended that those who are called upon to work on the national holiday should be paid the over time wages. It appears that the management has not inclined to oblige them.

10. The Evidence of MW-5 Ramprasad the foreman in para 9 makes out the rival contentions. In this background the evidence requires to be examined.

11. MW-2 Mohiuddin has sworn that on 26-1-79 he had gone for work to the first shift commencing from 6 A.M. According to him he reported at the conference room because there was no light in the foreman's room. At that time two foremen of the night shift Suri and William were present. His own foreman Ramprasad was also present. MW-2 adds that after reporting to duty, he went to the foreman's room with a torch to check up the Roaster. At that time, one Lokaiah, Kalasi was with him. MW-2 further swears that when he was checking the roaster the I Party workman Nair went to him and questioned him as to why he had attended to duty though it was a general holiday. Nair told him to go back but he refused to go back. Mohiudeen then swears that Nair held him and fisted him and went away from the foreman's room. Thereafter Mohiudeen went to the Conference room, there some other workers of the night shift were present. Nair threatened Mohiudeen that he would take care of him in the Township. Mohiuddin then proceeds to say that the foreman Ramprasad asked him to go to the township and bring the workers. But Mohiudeen told him that because Nair had threatened him that he would see him in the township he was afraid to go. At that point Lokaiah MW-3 was asked to go and call the workers and that Mohiudeen would take him in the Jeep. Though Mohiudeen states that Foreman Suri wrote his complaint Ext. M-4 at his request he has corrected in the next sentence and he has stated that on Mr. Gopala Krishna Operator-cum-Mechanic has written the same. The evidence of MW-2 Mohiudeen has been recorded on 14-3-83 regarding the incident of 26-1-79. If he has stated a wrong name of the scribe of his complaint exhibit M-4 it cannot be concluded that he is unreliable. The workman Nair admits his presence in the foreman's room at about 6 A.M. of 26-1-79. His contention is that he had lent Rs. 100 to Mr. Mohiudeen and since he was in need of money he asked Mohiudeen to pay the same but he did not pay and on the contrary he has involved in a false case. Mohiudeen had denied the suggestion that he owed Rs. 100 to Nair or that he had promised to pay back on 26th.

12. The management intends to prove its case by showing that the evidence of MW-2 Mohiudeen is corroborated by the evidence of several of the witnesses if not by the evidence of MW-3 Lokaiah

13. MW-3 Lokaiah admits that on 26-1-79 at about 6 A.M. he had gone to the Engineer's room (which is the same as foreman's room) and there was no bulb, no light. His evidence runs that MW-2 Mohiudeen was there and so also Nair. Then he heard MW-2 and Nair speaking something about money. At that stage the learned counsel for the management has sought permission from the Court for cross-examination of the witness on the ground that he has turned hostile, and his prayer was allowed. MW-3 Lokaiah admits that he has signed the complaint of Mohiudeen at Ext. M-5 (a). In the cross-examination MW-3 however admits that he heard Mohiudeen and Nair talking in Malayalam and he does not know that language. MW-3 Lokaiah corroborates the evidence of MW-2 to the extent that both of them had first met in the Engineer's room and after MW-2 had taken a torch both of them had gone into the foreman's room. MW-3 Lokaiah further supports the evidence of MW-2 that Nair had gone there and that at that time MW-2 was looking into the roaster. He however swears that he does not know whether Nair asked MW-2 as to why he was attending to his duties on that day. In the re-examination MW-3 explains that he could not understand as to what they talking in Malayalam but he only heard the word "Rupee". In my opinion the evidence of MW-3 in the exam-in-chief that he heard both of them talking about money only on the basis that he heard one word as rupee cannot be believed. No motive has been attributed as to why the other witnesses such as MW-4 Suri, MW-5 Ramprasad, MW-6 Gopalakrishna should depose against the workman. The contention that MW-8 Ansalika compelled MW-3 Lokaiah to sign on Ex. M-5 cannot be believed. No such suggestion was made to MW-8 Ansalika.

14. WW-2 Nair has a case that on the morning of 26th January, 1979 at about 6.20 A.M. he had gone to collect some letters and then he heard about some conversation between Nair and MW-2 Mohiudeen. There is no case put up by the workman Nair himself either in his evidence or in his reply statement Ext. M-10 about the presence of WW-2 Nair at that time. No suggestion have been made to MW-2 or MW-3 that at that time WW-2 Nayak was present. WW-2 states that Nair was talking in Malayalam and he does not understand Malayalam. In the cross-examination he concedes that on that day he did not collect any letter and one vargatta gave him his letter outside the premises. Since no case of the presence of Nair is suggested to MW-2 and MW-3 and since it is not there in Ext. M-10, I find that WW-2 Nayak cannot be trusted the documents at Exts. W-13 to W-22 produced by the I Party to show that he has been in the service of the II Party and that some others like him have been continued in service even after the period of contract can be of no avail.

15. The learned counsel for the II Party contended that even the workman Nair himself has not sworn that he did not assault or threaten, MW-2 Mohiudeen on that morning and thus it may be held that the said facts have been proved. The learned counsel for the I Party argued that his evidence recorded at the time of domestic enquiry which is in the file Ext. M-2 is his exam-in-chief. When the domestic enquiry has been set aside and the II Party has been permitted to adduce fresh evidence, no piece of evidence from the proceedings of the domestic enquiry can be availed off by any party. The learned counsel for the I Party then submitted that the reply statement Ext. M-10 is the earliest statement given by the workman and it may be taken into account. Ext. M-2 is his exam-in-chief. When the domestic enquiry it can be used only as a corroborative piece of evidence. I thus find that the contention of the learned counsel of II Party that the workman has himself not sworn to the fact that he did not assault or threaten MW-2 deserves to be accepted. In the cross-examination WW-1 the workman, it has been specifically suggested he has falsely narrated the incident in Ext. M-10. In para 7 of his evidence WW-1 Nair swears he had Rs. 100 to MW-2 Mohiudeen in December 1976. He has further explained that on 3rd or 4th of December he had drawn that amount from the salary credited in month of November 1979. It appears that there is some mistake in his statement that he had paid some amount in 1978. Accepting that his correct statement is that he had drawn the amount on 3rd or 4th of December, 1979 from his Bank, it does not find consistency with his written reply Ext. M-10. In Ext. M-10 he states that he had paid

Rs. 100 to Mohiudeen on 1-12-78 (and not on 1-12-79) the statements made by the workman in Ext. M-10 have not been suggested to MW-2 or MW-3, the narration found in Ext. M-10 is not to be found in the Exam-in-Chief of WW-1 or WW-2. Ext. M-10 shows that the scene of incident was field office, where as the evidence MW-2 and MW-3 makes it very clear that it was the foreman's room. WW-1 has again changed his version in his evidence and has stated that his wife was also getting money from Tailoring and his uncle and brother who are working in Military were sending him money and he cannot say from which source he got the money and paid it to MW-2. It is admitted by Nair that till today Mohiudeen has not repaid him the amount and still then he has not taken any steps such as filing of the suit or otherwise. Admittedly he has not given any complaint to the management in that regard. In para 11 of his evidence Nair admits that there was no enmity between himself and Mohiudeen. Taking into account all these factors I find that the fact that MW-3 Lokaiah has not supported the evidence of MW-2 can be no ground to discard the evidence of MW-2.

16. Ext. M-4 the complaint given by MW-2 Mohiudeen, his statement recorded by MW-6 Gopalakrishna and in addition the sworn testimony of MW-4 Suri MW-5 Ramprasad and MW-6 Gopalakrishna substantiate the evidence of MW-2.

17. MW-4 Suri swears about the incident and his evidence corroborates that of MW-2 on material points. The evidence of MW-4 Suri MW-5 Ramprasad substantiates that of MW-2 that he was afraid to go to the township since Nair had threatened him that he would take care of him in the township. The report of Ramprasad Ext. M-6 lends force to his evidence.

18. The learned counsel for the I Party contended that Ext. M-4 and M-5 were not produced before the Enquiry Officer and therefore they are got up documents. On going through the evidence of MW-4, MW-5 MW-6 and documents themselves, I find that there is no force in that contention. Ext. M-7 is xerox copy of Ext. M-5 Ext. M-8 is the xerox copy of backside of Ext. M-5. Ext. M-9 is charge sheet issued to the workman, Ext. M-1 is the order of appointment of the enquiry officer. No document out of M-1 to M-10 supports the case of the workman.

19. Ext. W-1 is the charge sheet, same as Ext. M-9 Ext. W-2 is the same as the reply of the workman Ext. M-10 Ext. W-3 to W-6 are letters written by the workman to the management. They do not relate to the incident in question Ext. W-7 is the order of discharge Ext. W-8 to W-12 is again a bunch of letters etc. written by the workmen to the Manager and they are not relevant as regards the incident.

20. On going through the evidence in great detail I find that the evidence of MW-2 is sufficiently corroborate by that of MW-4, MW-5 and MW-6 and the documents at Exhibits M-4, M-5, M-6 & M-10 and that the charges shown against the workman in Ext. M-9 are established. It cannot be forgotten that this is not a criminal court where a proof expected is if beyond all reasonable doubt. None the less there is sufficient material to hold that the workman did indulge in the said acts of misconducts.

The learned counsel for the I Party referred to the case of K. C. P. Employees Association, Madras -vs- Management of K. C. P. (1978 1 LLJ Page. 322) and argued that if there is doubt it must go to week section, Labour. It was further argued that since MW-3 Lokaiah has been declared as hostile and since there is the sole evidence of MW-2 Mohiudin sufficient doubt has crapt in and the benefit of such doubt should be in the favour of workmen. It is difficult to accept the said contention the evidence has been analysed and on due appreciation a finding has been arrived at that. The management has established the charges levelled against the workmen. In the context of the facts of the case they authorise does not help the I Party.

21. The learned counsel for the I Party then referred to the case of Rajendra Kumar Kindra -vs- Delhi administration

(1984 11 LLJ Page 517). The authority is on the point that if the finding in the domestic enquiry are based on surmises and conjunctures the findings cannot be accepted, no question of the validity of the domestic enquiry is at hand. The point at issue is whether the evidence produced by the management is such that a man of ordinary prudence can accept and hold a person guilty. The evidence of MW-5 Ramprasad is sufficiently substantiated by report M-6. Ext. M-6 shows that MW-2 Mohiudeen had refused to go to the colony and bring the workers on the ground that he had been threatened by the I Party workman. In his evidence dated 16-4-84. MW-5 has sworn that Mr. K. G. Karanth has acknowledged his report and has put his initials at Ext. M-6 (a). It cannot be believed that MW-4 Ramprasad MW-5 Srii MW-6 Gopalakrishna and MW-8 Ansari have all succumbel to the pressure of the management. Though it has been suggested for some of these officers that Ext. M-5 and M-6 have been got up documents there is nothing in their cross-examination to substantiate the said Allegation. One of the most important factors is that there is not even a suggestion against them of any personal animosity or any special reason for them to act at the behalf of the management. It is not a case where this Tribunal is proceeding on surmises and conjunctures.

22. The evidence of MW-7 Verghese is on the point that after Nair was discharged as per Ext. M-11, he had given his application for refundable P.F. Ext. M-12 and MW-7 has sent him the cheque Ext. M-14 with a covering letter Ext. M-13 along with the calculation Ext. M-15. He further states that the refused cover was registered as per Ext. M-16 and then he sends the cheque to the Accounts Department with a memo Ext. 17. He has further stated about the Nair giving an application for no objection certificate for the passport Ext. M-18 he has then referred to further documents such ments such as Ext. M-1 to M-26 which deal with the question whether Nair was gainfully employed or whether he had left India after his discharge. These matters are of no importance in view of the finding that the management has proved the charges against him. Similar is the case of MW-9 J. Azad and rest of the documents which are not specifically referred. Ext. W-10 is a letter by the I Party to the management to reconsider the order on sympathetic grounds. Ext. W-11 is a letter by the management to the workman showing that his appeal had been dismissed. Ext. W-12 is the letter by the workman for the supply of copies of enquiry proceedings. Ext. M-13 to M-22 are documents showing that even after the period of contract some of the workmen had been appointed on superannuation terms. These documents are not relevant on the point whether the II Party has proved the charges. They had been relief upon by the I Party to show that inspite of limited contract of service The I Party was entitled to remain in service until he reached the age of superannuation.

23. The learned counsel for the I Party referred to the case of Western India Automobile Association Vs. the Industrial Tribunal, Bombay (1949 1 LLJ p. 245) (2) 1930 LLJ p. 921 the Bharat Bank Ltd., Delhi, vs. the Employees of the Bharath Bank Ltd. Delhi and Bharat Bank Employees Union, Delhi. (3) 1981 1 LLJ page 327 Grindlays Bank Ltd. vs. Central Government Industrial Tribunal and others. (4) 1981 LLJ page 134 Champaklal Takkur and other vs. State of Gujarat. (5) 1982 1 LLJ page 33 workmen of M/s. Williamson Magor and Co. Ltd. vs. M/s. William Magor and Co. Ltd. and others. (6) Bombay Labour Union and others vs. Franchises (P) Ltd. S. C. Labour Judgements 1953—83 3 Volume page 10. (7) 1986 1 LLJ page 490 S. G. Chemicals and dyes Trading Employees Union vs. S. G. Chemicals and dyes Trading Ltd. (8) 1986 11 LLJ page 171 Central Inland Water Transport Corporation Ltd. and others vs. Tarun Kanti Sen Gupta and others.

24. The learned counsel for the II Party referred 1987 (1) LLJ Page 804 Amarsing vs. Aglawat Indian Petrol Chemicals Ltd. and to the case of Labour Law notes. These authorities cited for both the parties are not pertinent on the point of appreciation of evidence. The I Party has referred to them on the footing that the charges against the workman have not been proved.

25. Dealing with additional Issue No. III it is important to note that the project was a time bound project and the

management was particular to stick up to the schedule and in a democratic set up each individual has right to act according to his own conscience and if the I Party workman was not willing to work on a republic day there was no compulsion against him but at the same time he had no right to compel other workers not to attend to work. It is not a case of mere compulsion but stopping to violence and I find that Section 11-A is not attracted and the publication of discharge cannot be held to be unreasonable or harsh.

26. The management is thus held to be justified in discharging him and that he is not entitled to get any relief.

27. In the result the reference is hereby rejected.

B. N. LALGE, Presiding Officer

[No. L-29012/9/74-LR IV/D.III(B)]

का. अ. 2569.—प्रयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, के. जी. एफ. कर्नाटक के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित प्रयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रयोगिक अधिकरण, बैंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-8-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2569.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bharat Gold Mines Limited, Kolar Gold Fields, Karnataka, and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT BANGALORE

Dated this the 13th day of Aug., 1987

PRESENT :

Shri B. N. Lalge, B.A. (Hons.) LL.B.,—Presiding Officer
Central Reference No 1/1987

(Old No. C.R. 4/1975)

I Party

Workmen represented by the General Secretary, Nundydroog Mine Labour-Association, Station Road
Oorgaum, Kolar Gold Fields, Karnataka State.

Vs.

II Party

The Chairman-cum-Managing Director Bharat Gold Mines Ltd., Oorgaum Post, Kolar Gold Fields,
Karnataka State.

APPEARANCES :

For the I Party : Shri K. P. Sochindranath, Trade Union Leader, Banagalore.

For the II Party : Shri K. J. Shetty, Advocate, Bangalore.

AWARD

The present reference was referred to the Industrial Tribunal of the State Government. By order No. L-11025/A/87-D IV(R) dated : 13-2-1987, the case has been transferred to this Tribunal. The point of reference is as shown below :

SCHEDULE

"Whether the management of Bharat Gold Mines Ltd., Oorgaum is justified in transferring Sarvashri Manickam, Kannan and Anthonyswamy from Cap-Lamp Room Section of Nundydroog Mine to Materials Department ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

2. The First Party union has then filed its claim statement and inter-alia states as follows :—

All the Mines of Second Party had employed about twenty eight thousand workers. They were not classified. There have been awards in favour of First Party. Though the pay-scale revised, there was no classification of workers. Some of the employees gave a petition to Second Party on 22-3-1972 that though there was no change in the nature of duties, they have been paid Rs. 1.40 per day, whereas others are paid Rs. 1.90. These workers are called as Cap-Lamp Room Incharging. Chargeman working in the Electricity Department do the same kind of work, but they are given higher pay scale. They requested the Second Party to give them higher scale or some scale as D-3. Group D-3 is of Rs. 90-10-130 on 11-7-72. They requested the II Party to correct their service records. The II Party stated that there was disparity in the wages. They were not satisfied. Then conciliation proceedings were initiated. The II Party gave a reply to the Conciliation Officer dt. 4/5-7-1973 and admitted of having fixed them in Group-D. When the dispute was pending they were transferred to Champion Roof Mines on 1-3-1974 from Nandydroog Mines. They are the Executive Committee Members and protected workers. They approached the Government to intervene in the matter. There was no settlement. They have been victimised, when they were working as Cap-Lamp-in-charge they were doing clerical and supervisor work. Now when they are transferred as Storeman they are made to do manual work. The II Party has indulged in unfair labour practice. They are not given transport expenses under Section 33 of the Industrial Disputes Act has been infringed. No notice was given to them for the change in the service condition. They cannot be transferred. They are deprived of their seniority and chance of getting promotion. Therefore they pray for the relief of the cancellation of transfers.

3. The II Party has filed its counter statement and inter-alia and it contain as follows :

It is not correct that there is no classification of workers. The agreement of 1972 has given them considerably benefit and about 8000 workers are converted from daily to monthly rated employees. From 1-1-1973 there was another revision, though there was loss of about Rs. 4 crores. From 1-4-1958 there was a nationalization. New wage schedule was brought into force on 1-4-1958. It is not aware of any petition given by them, prior to introduction of Cap-Lamp Miners were issued only carbide lamps. It is not true that these workmen of I Party has given test and they were designated as Cap-Lamp Incharge from 1-4-1971. Anthonyswamy and Manickam were designated as Cap-Lamp room maistris from 1-2-1972. Kannan was promoted as Cap-Lamp room Incharge. This designation has been wrongly equated to that of Cap-lamp room chargeman. Because of the wrong designation these 3 workmen started claiming that they should be treated as Cap-Lamp room inchargemen. Departmental promotion committee processes the matter. Whenever the promotions are made there was no meeting of the Departmental Promotion Committee. There is no post as Cap-Lamp-room-in-charge. Prior to the establishment of Cap-Lamp room, the workmen of the Electricity Department were doing the said kind of work. The set up therein was Foreman supervisor, Cap-Lamp room chargemen and Cap-Lamp-room attendant I & II. The 1st two were monthly rated and the rest were daily rated. There has been no discrimination. It is not aware of any letter dt. 11-7-1982 or their reply dt. 24-1-1973. The claim of these workmen to place them in D-III Grade (Monthly rated) is not valid. It is of higher scale. They are of Group-V (daily rated) it has been converted into monthly rated w.e.f. 1-10-1972. Alteration in designation does not mean that there is change in duties and responsibilities. It is not correct that when a dispute was pending, their service conditions were changed. In the interest of the understanding and in the normal course these transfers have been affected and in accordance with the standing orders. It is denied that they have been victimised. They cannot claim wage on par with the electricity personnel. It is denied that they have worked as supervisor or as clerks. It is denied that on their transfer to the Champion Roof Stores they are asked to do manual work. There

is no unfair labour practice. There is no provision for payment of conveyance allowance, if there is a transfer. There is no breach of Section 33 of the Industrial Disputes Act. Transfer is a prerogative of the management combined with exigencies of the work. On transfer the workmen carry their seniority in their own grade. The claim is not tenable and the reference may be rejected.

4. The II Party has then examined one witness and has got marked Ext. M-1 to M-13.

5. The I Party has then examined two witnesses and has got marked Ext. W-1 to W-13.

6. Parties have been heard. My findings on the point of dispute is as follows :—

The management was justified in transferring Sri Manickam, Kannan and Anthonyswamy from Cap-lamp-Room-Section to material Department.

REASONS

MW-1, Ramakrishna, the Chief Engineer of II Party has sworn that he was working as an Electrical Engineer in the Nandidoorg Mines prior to 1976. He further states that in 1972, he was in charge of issuing and maintenance of Cap-Lamps for Minors from the Cap-Lamp Room. According to him, workmen of Foremen 'C' Grade used to supervise the work of the subordinates. He further states that below the Foreman 'C' Grade there were two kinds of subordinates Cap-Lamp attendants 1 and 2 were the subordinates to the chagemen. He then adds that these workmen, Manickam Kannan and Anthonyswamy were the attendants working in Cap-Lamp Room. He further swears that prior to the introduction of Cap-Lamp in 1972, they were issuing carbides and were working as semi-skilled workers of SH2. His evidence then discloses that the work of an attendant in the Cap-Lamp Room is a skilled job and the worker can become an attendant in Cap-Lamp Room by promotion from SH2 job. His evidence then reads that the post of Cap-Lamp room attendant is classified as S1 category in order to support his evidence. The management has produced Exts. M-1, M-2, M-3. The extracts from their service registers. Exts. M-1 is of Manickam. It shows that when he was appointed in 1957, he started working as surface Carbide charger. Ext. M-1 further shows that on 1-4-1971, he was promoted as Cap-Lamp-room maistry and put in to A-S1 Grade. When refixation was done, according to the memo dt. 22-11-1972, he was put in Grade-G.V. w.e.f. 1-10-1972. He continued to be Cap-Lamp room Maistry till he was transferred on 1-3-1974 as stores Issuer to the Material Department. Ext. M-2 of Anthonyswamy shows that prior to 1-4-1971 he was working as a Carbide Issuer on promotion he started working as Cap-Lamp-Room-Maistry from 1-4-1971. At that time he was Grade-S1. On 1-10-1972 he was put in Grade-S-V by virtue of memorandum dt. 22-11-1972. On 1-3-1974, he was transferred to Material Department. Ext. M-3 of Kannan discloses that prior to 1-2-1972, he was a Carbide Issuer and on promotion he became Cap-Lamp room-in-charge w.e.f. 1-2-1972 in the Grade of A.S.1. Similarly on 1-10-1972, he was put in Grade G.V by virtue of memorandum dt. 22-11-1972. On 1-3-1974, he was transferred to Material Department as Stores Issuer. Regarding the evidence of MW-1 the writing in the service register as Cap-Lamp Maistry or Cap Lamp room-in-charge is on account of some mistake and that there are no such posts at all in the wage structure. What is materially is not the nomenclature by which the post is called but it is the Grade of the post that counts, M-1, M-2, M-3 clearly indicates that when refixation was made on 1-10-1972, all these 3 workmen were put in Grade G-V. The evidence of MW-1 then shows that when they were transferred in March, 1974, as store Issuer to the materials Department, they continued to be in the same Grade as G-V. He has categorically stated that the nature of duties which they were doing in Cap-Lamp-Room and the nature of duties which they are presently doing in the stores of material Department are the same. In para-3 of his evidence he has stated that in the II Party, it is customary to transfer a workman from one Department to another and that the distance from their quarters to either Nandidoorg Mines or Stores Department is the same;

3 kilometers. In the Cross-examination, he has been asked about the nature of duties they were doing in the Cap-Lamp room. He has stated that they use to issue Cap-Lamps and keep record of the same and when returned, put them for charging. He has been confronted with the entries made at Ext. M-3 (a), it relates to Kannan and shows that he has been designated as Cap-Lamp room-in-charge. Similarly M1(a) of Manickam and M2(a) of Anthonyswamy have been pointed out to the witness. In the case of Manickam it is shown as Cap-Lamp Room Maistry and for Anthonyswamy as Cap-Lamp Room in-charge there is no suggestion made to MW-1. That in the Cap Lamp room these three workmen were doing any other kind of job such as charging the Cap-Lamp with electric power. The witness has been specified in stating that these three persons were not attending to the work of maintenance of Cap Lamp or doing any supervisory work in relation to the Cap Lamps. MW-1 has categorically stated that the Assistant Foreman and chagemen were doing the work of supervision and maintenance of Cap-Lamps. It is important to note that there is no case pleaded in the claim statement that these three workmen were attending to the work of supervision and maintenance of Cap-Lamps or such other of the work of Cap-Lamps room. The turning of the evidence of WW-1 Kannan and WW-2 Manickam. I find that they do not swear that they were doing any work of maintenance of the Cap-Lamps or the work of Cap-Lamp room. The crucial point is whether these persons were working in such a post which carried the wages of Rs. 1.90 per day in which case it would be easy to inter that they were working in a grade higher to ASI. WW-1 Kannan has sworn that his post as Cap Lamp Room-in-charge has been described as Cap-Lamp Room chageman in page 3, column 5 of the schedule to Ext. Column 3 of the said Schedule of page-3 shows that the new scale of pay was Rs. 70-5-100-10-150-10-180-10-220. The entry in column No. 5 is very clear in showing that it relates to Cap Lamp Room chagemen. In the remarks column clause (f) makes it evident that fitters and mechanists of Grade-I, Maistry & Electrical chageman Electrical fitter Wiremen Grade-I etc., were all clubbed in one group and it is stated that they shall get Rs. 95 at the beginning itself. By no stretch of imagination it can be gathered from the evidence on records that these three persons over worked as technical persons such as electrical chageman. Though there is a case that they underwent some test, there is no documentary evidence to support the same. The post of Cap-Lamp room chageman shown in column No. 5 of page 3 of the Schedule to Ext. W-7, therefore relates to chagemen (Electrical) working in the Cap-Lamp room and not to Cap-Lamp Room Maistry or Cap-Lamp room in-charge. Though they also work in the Cap Lamp Room WW-1 evades to answer a direct question put to him that the post of chagemen is a highly skilled post of Grade-D. It is admitted by him in para-9 that at the time of his transfer he was drawing Rs. 66 per month. He further concedes that foreman in-charge of Cap-Lamp Room was higher post and officer in-charge of the Cap Lamp Room was a still higher post. The evidence of WW-1 thus does not help the I Party to show that at the relevant time they were getting such a scale of pay which the management could not have categorised as Group-V.

7. WW-2 Manickam states that after training interview and selection he was posted as Cap Lamp in-charge. No document was pointed out to me about his training interview and selection. He points out to his salary slip Ext. W-10 his wages for 26 days is shown as Rs. 66. The slip of November 1973. It is not explained as to how the workmen can claim to be a chagemen and still getting daily rated wages of Rs. 66. Ext. M-1, M-2 M-3, M2(a), M3(a) point out to constant raise in wages and do not indicate that there was any training and extraordinary promotion. The entries made in the three service books produced before me have not been challenged. In para-4 of his evidence WW-2 admits that when he came to the Cap-Lamp section he was posted as issuer. According to him in 1971 he was getting Rs. 2/- per day. He admits that Skilled-I (SI) post is of Group-V and was subsequently converted as a monthly rated post. This admission supports the evidence of MW-1 Ramakrishna as discussed above. He further admits that on 1-4-1971, he started with Rs. 2/- per day. The entries in Ext. M-1 are consistent with his statement. He admits that

in the settlement in W-7 semi-skilled-II to Skilled-I and highly skilled-I are all put in Group-V (G-V). From the Schedule to Ext. W-7 and from the settlement Ext. W-7 itself it can be made out that there was no post as Cap-Lamp room Maistry or Cap-Lamp Room incharge. Page-3 of Ext. W-7 shows that semi-skilled Grade-II and I which were of the scale or 1-70|10|2-10 and 1-60|10|2-00 respectively were put into the new category of Group-V in para-4 of his evidence, WW-2 admits that the chageman used to supervise the work of Cap Lamp Issuers and the foremen used to look after the work in general. These admission make it very clear that the post of Cap-Lamp Room chageman was two steps higher than the post of Cap-Lamp Room incharge.

8. The I Party had relied upon several documents to substantiate its case. That the three workmen could not have been transferred to the materials department. Ext. W-1 is the pay slip of Kannan of August 1974. The basic pay is as shown as Rs. 66/- per month. It is not shown as to how it support their case. Ext. W-2 a representation against putting them in Group-V an admission cannot be proved in favour of the party, and it does not help them. Ext. W-4 is a representation made by the Union to the Assistant Labour Commissioner, Bangalore. Ext. W-3 is a reply of the management given to the Assistant Labour Commissioner in that connection. Ext. W-5 is a minutes of the proceedings held between the workmen and the management on 5-11-1973 in the presence of the Assistant Labour Commissioner. These documents show their rival contentions Ext. W-8 is the recommendation of Basu, one man committee in the Schedule to the said report. There is no mention of any posts such as Cap Lamp Room Maistry or incharge. Ext. W-9 is the recommendations in regard to the categorisation of workmen. It does not show the post such as Cap-Lamp Room Maistry or incharge. In my view it does not help the I Party. Ext. W-10 shows the names of Lamp Issuers as per roster. The management does not dispute that these three persons were doing the work of issuing of Cap Lamps. Ext. W-13 is a representation made by Manickam. It only put forth his case.

9. The I Party can endeavour to succeed if there is change in service condition because of transfer. The transfer is challenged on the footing that because they agitated for their legitimate pay scale and grade in the Cap-Lamp Room, they have been transferred to the material department. On facts a finding has been recorded that there was only a mistake in the nomenclature as Cap-Lamp Maistry or incharge and that the scale of pay and grade which are incidentally discussed herein have been correctly maintained by the II Party.

10. Now it requires to be examined whether the three workmen had been put to any disadvantage by the transfer. MW-1, Ramakrishna has specifically sworn that promotions are governed on the basis of common seniority confined to a certain group and that it is not departmentalwise. The workmen have not produced any material to show to the contrary, it is thus obvious that the promotional chances are not at a discount. The workmen have a case that in the Cap-Lamp Room they had Supervisory and clerical nature of work, whereas they are now made to work as manual labourers by lifting the stores and handing them over to the concerned persons. It has been suggested to WW-2 that these three workmen do not actually lift materials and hand them over but they take the concerned worker to the spot and the worker himself carries away the material. There is a specific suggestion to that effect to WW-1, in para-9. He has denied it that there is no independent material placed before me to show that the work in the materials department is onerous. If these persons were lifting the Cap Lamps and handing them over to the workers I do not find as to why they should have any grievance if they are asked to hand over stores material to the concerned worker. On going through the evidence in great detail, I do not find that there is any change in the condition of service or any extra burden on the workmen because of the transfer.

11. The evidence of MW-1 shows that the present place of work of Materials Department is equal distance from the residence and it is an admitted fact that they were not paid any conveyance allowance when they were working in Cap

Lamp Room. The learned counsel for the workmen has placed before me the authorities of M/s. Mackiman, Mackenzie-Vs-Audivi de-costa (Special leave petition No. 1265 of 1987 S.C.) 1987 (1) SVLR(L) page-131).

Mislinakhan Vs. Union of India [1987(1) SVLR(L) Page-145].

12. The I authority is on the point of equal remuneration for the same work. The point at issue is not regarding remuneration.

13. The II authority is on the point of discrimination between two classes of workers in the context of the facts before me. I donot find that there is discrimination. The authorities are not pertinent.

14. The learned counsel for the II Party cited the case of the Jaipur Udyog Ltd., Vs. the Cement Work Karamchari Sangh (1971 LJ P. 437) and argued that the Court cannot expande the point of reference. It has been already observed that the questions whether these three workmen were wrongly put Grade-G.V, or whether they were entitled to higher grade or far higher scale of pay have all been discussed has incidental points to the main point of validity of transfer and no attempt has been made to expande the point of reference.

15. The learned counsel for the II Party then referred to the case of Hindustan Liver Ltd., Vs. The workmen (1974 1 LJ Page-94). The authority is on the point that transfer is a prerogative of the management and that the transfer cannot be set aside unless it has been on account of victimisation or unfair labour practice. MW-1 Ramakrishna was sworn that it is usual for the management to transfer the workmen from one department to another. I do not find any force in the contention of the I Party that they have been victimised because they claimed the Grade and the scale of pay, to which they thought to be entitled. The evidence on records discloses that if they were made to work for 8 hours in Cap Lamp Room, they have now to work only for 7 hours in the materials department. Even otherwise, I do not find any convincing evidence about victimisation or unfair labour practice on the part of II Party. I find no merit in the case put forth by the I Party. I do not find that the transfer were not justified.

In the result, the reference stands rejected. (Dictated to the Secretary, taken down by him and typed and corrected by me.)

Dt. 13-8-87.

B. N. LALGE, Presiding Officer.

[No. L-29012/9/74-LR.IV[D.III(B)]

का. प्र. 2570 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, त्रावेनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लि., कोचुवेली, त्रिवेन्द्रम-21 के प्रबंधन से सम्बद्ध नियजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रतिकरण, क्यूलौन के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-8-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2570.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Quilon, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Travancore Titanium Products Ltd. Kochuveli, Trivandrum-21 and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th August, 1987.

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
QUILON

(Dated, this the 14th day of August, 1987)

PRESENT :

C. N. Sasidharan, Industrial Tribunal

in

Industrial Dispute No. 15/87

BETWEEN

The employers in relation to the management of Travancore Titanium Products Ltd., Kochuvelli, Trivandrum-21 (By Sri B. S. Krishnan, Advocate, Ernakulam).

AND

The workmen represented by :

The General Secretary, Titanium Workers Union, Kochuvelli, Trivandrum-21.

AWARD

This industrial dispute between the above parties has been referred for adjudication to this Tribunal by the Govt. of India as per order No. L-29012/47/86-D. III(B) dated 14th July, 1987.

2. The issue referred for consideration is :

"Is the management of Travancore Titanium Products Ltd., Trivandrum justified in fixing the scale of pay of Sri N. P. Varghese at Rs. 790 and denying the same to Sri Rajan Valath who claims to be senior to him but is paid only Rs. 750? If not, what relief Sri Rajan Valath is entitled to?"

3. Notice were duly served to both parties. On 4th August, 1987 when the case stood posted for appearance of the parties and statement of union the management alone appeared. The union remained absent and was declared ex-parte. The management took adjournment for engaging counsel and for filing affidavit to prove its case. The case was accordingly posted to today. The management has engaged a counsel and filed a valuation on 10th August, 1987. But, today, when the case was called, the management and counsel remained absent without any reason whatsoever. There was no representation also on behalf of the management. Management was also set ex-parte.

4. In this state of affairs it has to be presumed that there is no dispute now subsisting to be adjudicated upon. I therefore find that there is no subsisting dispute between the parties for adjudication.

An award is passed accordingly.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

[No. L-29012/47/86-D. III(B)]

का. द. 2671:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, विश्वकर्मा कॉपर कंपनी लि., बेंगलूर के प्रबन्धकों से सम्बन्धित निर्यातकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बेंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-8-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2571.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Chitradurga Copper Co. Ltd., Bangalore and their workmen which was received by the Central Government on the 25th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL, BANGALORE

Dated, the 28th day of July, 1987

PRESENT :

Sri B. N. Lajge, B.A. (Hon.) LL.D., Presiding Officer.

Central Reference No. 88/87

1st Party :

Sri R. D. Albert, Ex-Timberman S/o R. G. Shanasingh, M/s Chitra Durga Copper Co. Ltd., Copper Nagar, (Thamaranagar), Chitradurga.

Vs.

The Chairman-cum-Managing Director, M/s. Chitradurga Copper Company Limited, No. 16/1, Ali Asker Road, Bangalore-560052.

APPEARANCES :

For the 1st Party—Sri Wilson Vinod Kumar.

For the IInd Party—Sri R. J. Babu, Advocate.

AWARD

The Government of India by its order No. L-43012/16/85/D. III(B) dated 23rd April, 1987 made the present reference in the following points of dispute.

POINTS OF DISPUTE

"Whether the discharge of Sri R. D. Albert, Ex-Timberman, by the management of M/s Chitradurga Copper Co. (now managed by M/s Hutti Gold Mines, Hutti Raichur District) on the letter of resignation alleged to have been obtained under threat and Coercion is legal, proper and justified? If not, to what relief is the workman entitled?" and

"Whether the action on the part of the management of M/s. Chitradurga Copper Co. (now managed by M/s Hutti Gold Mines, Hutti) in denying re-employment to Sri R. D. Albert, is justified when management provided re-employment to other workmen viz. S/Shri Siddali-Yellappa, Prabhudhev, Chitharanjan Dass, Devappa, Basavaraj, Nagi Sivanna, Govamarappa, K. P. Godtrappa, and R. Chandra Naik? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. During the course of the trial, the parties have arrived at a Compromise and have filed a joint settlement memo.

3. Thereafter this Tribunal has passed an order as shown below :—

ORDER

Welfare Officer of the II Party and the 1st Party workmen and their Advocates admit the contents and execution of the memo.

The Compromise is in the interests of Justice and also in the interests of the workmen. The I Party workmen has given his application to the II Party for such appointment. The II Party shall therefore appoint him w.e.f. 1st August, 1987. An award is duly passed accordingly.

The joint memo. shall form part of the award.

Dt. 28-7-1987.

B. N. LAJGE, Presiding Officer

[No. L-43012/16/85-D. III(B)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

IN THE COURT OF THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL, BANGALORE

Central Reference No. 88/87

I Party—R. D. Albert.

Vs.

II Party—The Chairman and Managing Director, Chitradurga Copper Co. Ltd., H. O. Bangalore.

Settlement Memo.

1. The First party has agreed to seek re-appointment with the II Party and has agreed not to claim any back wages.

2. The Second party has hereby agreed to provide the first party fresh appointment as a watchman (temporary) on daily wages of Rs. 12.25 at their Haladath Mines Arosiken Taluk and to provide him free quarters if available with free lighting to an extent of 30 units per month. That his total emolument's will work out at Rs. 375 per month.

3. That the 1st party has to submit an application to the Head Office through the 2nd party at Chitradurga.

Sd/-

(Illegible).

Advocate First party

Sd/-

(Illegible).

Advocate 2nd party.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

का. आ. 2572.—केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 अक्टूबर, 1986 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3555 तारीख 11-10-1986 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 5 के सामने की प्रविष्टि "श्री बी. डी. नरुला, अपर कार्यपालक निदेशक, स्थापन (विशेष), परिवहन मंत्रालय, रेल विभाग (रेल बोर्ड), नई दिल्ली" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"श्री बी. डी. नरुला रेल का प्रतिनिधित्व करने वाले"
कार्यपालक निदेशक,
स्थापन (आइ. आर.),
रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड)
नई दिल्ली।

[सं. एन. 16014/30/87-एल डब्ल्यू]

शशि भूषण, अवर सचिव

टिप्पण:—केन्द्रीय परामर्शी ठेका श्रम बोर्ड पुनर्गठन से संबंधित पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. एन. 16025/9/85-एल. डब्ल्यू. तारीख 26-12-1985 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ. सं. 126, तारीख 11-1-1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2572.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), read with rule 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification No. S.O. 3555 dated 11-10-1986, of the Government of India, in the Ministry of Labour, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 11th October, 1986, namely:—

In the said notification, against serial No. 5, for the entry "Shri B. D. Nirula, Additional Executive Director, Establishment (Special), Ministry of Transport, Department of Railways (Railway Board), New Delhi"; the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri B. D. Nirula, ...Representing the Railways"
Executive Director,
Establishment (IR),
Ministry of Railways, (Railway Board),
New Delhi.

[No. S-16014/30/87-LW]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

NOTE :—Earlier Notification No. S-16025/9/84-LW dated 26-12-1985 relating to the re-constitution of the Central Advisory Contract Labour Board was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide S.O. No. 126 dated 11-1-1986.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

का. आ. 2573.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार धारारी कोलियरी, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-8-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2573.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bararee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th August, 1987.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 335 of 1986

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bararee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 10th August, 1987

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012/13/86-D.IV(B), dated, the 29th September, 1986:

SCHEDULE

"Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union, Dhanbad for protection of wages of the workmen in Annexure-A in Group VA with effect from October, 1978 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

ANNEXURE 'A'

S. No. Name of the workmen

1. Shri Shanji Paswan
2. Shri Chowanthi Balik Yadav
3. Shri Hanshu
4. Shri Ganeshi
5. Shri Shamcharan Yadav
6. Shri Parsho Ram

In this reference only the workmen filed their W.S. Thereafter several adjournments were granted to the employers for filing their W.S. Ultimately on 4-8-87 both the parties appeared before me and filed a joint compromise petition. I have heard the parties on the said Joint compromise petition and I do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the joint compromise petition which forms part of the Award as Appendix.

Dated : 10-8-87

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012/13/86-D.IV(B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

APPENDIX

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In the matter of reference No. 335/86

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bararee Colliery of Bhowra Area of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Bhowra, Distt. Dhanbad.

AND

Their workmen represented by Bihar Colliery Kamgar Union.

Joint compromise petition of the employer and the workmen/sponsoring Union.

The above mentioned employers and workmen most respectfully beg to submit jointly as follows :—

- (1) That the employers and workmen have jointly negotiated the matter covered by the aforesaid reference with a view to arriving at an amicable and overall settlement of the dispute.
- (2) That as a result of such negotiations the employers and workmen/sponsoring union have come to a mutually acceptable and amicable settlement of the dispute on an overall basis on the following terms and conditions:—
 - (a) It is agreed that the seven (7) workmen covered by the aforesaid reference namely S/Shri Shamjee Paswan, Chouthi, Balik Yadav, Hanshu, Ganeshi, Shyam Charan Fadav, Parshu Ram, [7th name included as per corrigendum letter No. L-24012/13/86-D.IV(B) dated 3-6-87 from the Ministry of Labour] who were Miner/Loaders in P.R. Group VA wages and were observed as Stowing Pipe Mazdoors in daily rated Cat. I wages of NCWA-I from the 1st October, 1978 to 31st January, 1980 will be given protection of group wages of group VA of Miner/Loader for the above period (1st October, 1978 to 31st January, 1980).
 - (b) It is agreed that the arrears payable to the above named workers, if any as a result of implementation of clause 'a' will be paid to them within a period of 2 months from the date of publication of the Award.
 - (c) It is agreed that this is an overall settlement in full and final of all the claims of the workmen concerned arising out of the aforesaid reference.
- (3) That the employers and the workmen/sponsoring union consider the above settlement/terms as fair and reasonable to both the parties.

In view of the above, the employers and the workmen/sponsoring union jointly pray that Hon'ble Tribunal may be pleased to give an award in terms of the above settlement and dispose of the reference accordingly.

Sd/-
(Illegible),

Secretary,
Bihar Colliery Kamgar Union,
For and on behalf of the workmen.

Sd/-
(M. Sen),
Area Secretary, BCKU,
For and on behalf of the workmen.

Sd/-
(Illegible),

Agent,

Bararee Colliery, ECCL,

For and on behalf of the Employers
(J. R. Varman),

Sd/-

(Illegible)

Personnel Manager, BCCL,

Bhowra Area,

For and on behalf of the Employers

नई दिल्ली 3 सितम्बर, 1987

का. भा. 2574.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-87 का प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2574.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th August, 1987.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 29 of 1986

Reference No. L-12012/92/85-D-II(A) Dt. 24-1-1986
In the matter of dispute :—

BETWEEN

Shri Surendra Bahadur Singh,
C/o Shri Shishu Pal Singh,
119/205 Om Nagar, Kanpur.

AND

The Chief Regional Manager,
State Bank of India,
Mall Road, P. B. No. 453
Kanpur.

APPEARANCES :

Shri S. N. Sharma, Counsel—for the Management.

Shri Shishu Pal Singh, representative—for the workman.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/92/85-D-II(A), dated 24th January, 1986, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of State Bank of India, Kanpur, in terminating the services of Shri Surendra Bahadur Singh from 3rd May, 1984 is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?"

2. The case of the workman Shri Surinder Bahadur Singh is that on 7th August, 1980 he was recruited as temporary guard by Pandu Nagar Branch of State Bank of India. After some time he got his postings in some other branches of the State Bank of India at Kanpur, such as Chandra Shekhar Azad Branch, Vishwa Vidyalaya Branch, Govind Nagar Branch and Sabjimandi Kidwai Nagar Branch. His last posting was in the Sabjimandi Branch Kidwai Nagar, Kanpur. On 3rd May, 1984 the manager of Sabjimandi branch terminated his services illegally without giving him any prior notice. He alleges that having served for more than 240 days in the different branches of State Bank of India at Kanpur, in view of Staff Circular Nos. 147 of 1980 and 168 of 1976 he ought to have been made permanent by the management bank. He also alleges that the management committed breach of the statutory directions contained in para 495 and para 522 of Shastri Award. He has, therefore, prayed that the management be directed to make him permanent and pay him back wages.

3. In reply the management has admitted that the workman was employed as guard on 7th August, 1980, by Pandu Nagar Branch of the State Bank of India, Kanpur, but according to it his status was that of temporary badli guard. The management has further admitted that the workman remained posted in some branches of State Bank of India, Kanpur and that between 7th August, 1980 and 3rd May, 1984 he worked for 615 days as has been shown by him in the annexure to his claim statement. The management pleads that the workman had not completed 240 days of actual service during the period of 12 months preceding the date on which his services were terminated and as such his case is not covered by sec. 25B of the I.D. Act, 1947. The management further pleads that every branch of the State Bank of India at Kanpur is an independent unit and as such the temporary services rendered by the workman in different branches of State Bank of India at Kanpur, cannot be legally clubbed. His employment in each branch was distinct, fresh and independent. Another plea raised by the management is that no valid industrial dispute exists between the parties in as much as the workman settled his accounts with the management without any demur or protest at the time of termination of his services. Moreover, the management in terms of provisions of para 23.15(c) of Desai Award is entitled to engage a temporary employee for a limited period in connection with a temporary increase in work of a permanent nature. Lastly, the management says that there was a proposal to absorb the workman permanently in the bank services but at the time of his interview it was found that he did not comply with the qualifications required for permanent absorption in the bank service.

4. In his rejoinder the workman has reiterated the facts alleged by him in his claim statement. He has further alleged that once a dispute is referred for adjudication the presumption would be that it is an industrial dispute.

5. In support of his case whereas the workman has tendered in evidence his own affidavit, the management has tendered in evidence the affidavit of Shri Gyanendra Nath Pandey, an officer of the State Bank of India, posted in Region I and a few documents some of which have been admitted by the representative for the workman and marked as Ext. M-1 to Ext. M-V. Both the workman and management witnesses have been cross examined by the opposite parties.

6. It is the admitted case of the parties that the workman was employed as guard by Pandu Nagar Branch of the management bank at Kanpur on 7th August, 1980, and that after serving in the said post for 615 days during the period from 7th August, 1980 to 2nd May, 1984 in different branches of State Bank of India, Kanpur his services were terminated by Manager, Sabjimandi Branch, Kidwai Nagar, Kanpur. Whereas, according to the workman, he was appointed as temporary guard, according to the management he was employed as temporary badli guard. Further whereas the contention of the workman is that during the period of 12 months preceding the date of termination of his services he had worked for more than 240 days, the contention of the management is that it is not so; he only worked for 218 days inclusive of all paid Sundays and Holidays in the Sabjimandi branch of State Bank of India.

7. So we have to see first whether the employment of the workman was as temporary badli guard or merely temporary

guard and then we have to see whether or not he had worked for 240 days or more during period of 12 months prior to the termination of his services.

8. Shri S. N. Sharma, advocate, counsel for the management during the course of arguments, has placed reliance on some of the statements made by workman in his cross examination and has further relied upon the ruling in the case of *Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd., Versus Mills Mazdoor Sangh, 1986 Lab. IC 1361 (SC)*.

9. In the said ruling it was held that badli workman got work only in the absence, temporary or otherwise of regular employee and they do not have any guaranteed right of employment. Their names are not borne on the muster rolls of the establishment concerned. Badli workmen are really casual employees without any right to be employed and they are not entitled to any compensation for the closure.

10. The learned counsel for the management submits that in his cross examination the workman has said that initially he was appointed as badli guard but later on he worked as temporary guard. On examination of his statement in cross examination as a whole it would appear that he had worked as badli guard in Pandu Nagar, Usmanpur, Naubasta, Moti Jheel and Kenal Road branches of the State Bank of India at Kanpur. In view of all this the latter part of his statement that subsequently he worked as temporary guard becomes unbelievable. If he could be employed as Badli Guard in these branches, there is no reason why he would not have been employed in the same capacity in other branches of State Bank of India at Kanpur. On the other hand management witness has clearly stated that workman has all along worked as Badli guard in different branches of State Bank of India, at Kanpur.

11. Despite all this I am unable to uphold the point of view placed before me by the learned counsel for the management. In this connection I would like to refer to documents paper No. II filed with the list of documents by the management. It has been marked as Ext. M-1. It is the statement regarding duty given by the workman during the year 1983. Its heading is quite important and it reads as under :

Statement of working of temporary guard Shri Surendra Bahadur Singh for the year 1983.

The use of word temporary, as stated above is quite important. Had the workman been a badli guard, he would have been described as badli guard in the statement. Much reliance cannot be placed on the testimony of the management witness because he has admitted in his cross examination that the workman never worked with him in any of the branches of the management in which the workman remained posted. He even does not know whether or not any appointment letter was given to the workman. He also does not know whether or not letter of termination was given to the workman at the time of termination of his services.

12. Here it will be useful to refer to para 23.15 of Desai Award. In the said para in connection with the classification of workman only 4 categories of employees have been described. They are—Permanent employee, Probationer, Temporary employee and Part Time employee. A temporary employee has been described as meaning an employee who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature, or who is employed temporarily as an additional employee in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes an employee other than a permanent employee who is appointed in a temporary vacancy of a permanent workman. In para 3 of the written statement the management has pleaded that the workman was engaged as purely temporary badli guard against leave vacancy/absentism of permanent guard at various branches of the bank at Kanpur.

13. From the above it can be concluded that so far as banking industry is concerned there is no category of employee such as badli workman. The ruling on which the learned counsel for the management has relied is distinguishable on facts. In that case the dispute was between a Cotton Mills and a Mazdoor Union. It was not a dispute between a banking industry and workman. As such no adverse inference can be drawn from the statements made by the workman in his cross-examination that in some of the branches his employment was as badli guard. All this has no meaning. The term badli

guard seems to have been used by both the parties in a broader sense, i.e. to say substitute for a permanent workman who absents himself from duty due to leave or otherwise. Hence, I hold that the workman worked as temporary employee in the different branches of the State Bank of India at Kanpur, and not as badli workman in the sense in which it is sought to be understood by the learned counsel for the management.

14. On the second point the contention of the learned counsel for the management is that the temporary services rendered by workman in different branches of the bank at Kanpur cannot be legally clubbed in as much as the employment of the workman in each of these branches was distinct, fresh and independent. For the purpose of ascertaining whether or not the workman has rendered one year continuous service within the meaning of section 25B of the I.D. Act, the period of his employment in the last branch is to be taken into account. In support of his point the learned counsel has placed reliance on the ruling in case of Indian Cable Company Vs. Its workmen, 1962 ILJ 409(S.C.).

15. Even in this argument of the learned counsel for the management I find no force. In the ruling referred to by him it was held that the question whether a branch in any particular case would be regarded as distinct industrial establishment for the purposes of sec. 25-G of the Act, is a pure question of fact. So every case has to be examined on its own facts.

16. It is not disputed before me that the State Bank of India is a class A bank. In the case of A class bank according to para 507 of the Sastri Award for the purposes of retrenchment a town is to be taken as a unit. This being so we will have to see whether or not during the 12 months proceeding the date of termination the workman had worked for 240 days. There is on record the joint inspection report bearing 3 dates i.e. 30-9-86, 5-10-86 and 24-10-86. From this joint inspection report it appears that in the Subjimandi Kidwai Nagar Branch the workman worked for 226 days in Naubasta Branch he worked for 14 days in Kanal Road Branch he again worked for 14 days and in the Usmanpur Branch he worked for 5 days. The total number of working days comes to 259 days. This is for the period from 9-5-83 to 2-5-84. This I say, so, despite the fact that specific period after 11-7-83 is not mentioned in the joint inspection report. But it can be inferred from the fact that he worked in the Subjimandi Kidwai Nagar Branch, the branch in which he was last posted for 226 days. Hence, his case is fully covered by Sec. 25-B(2)(a) of the Industrial Disputes Act. To be more explicit the workman would be deemed to be in continuous employment of the management for a period of one year preceding the date of termination of his service.

17. I may state here that the workman's representative has been unable to make out a case for the workman for his being made permanent in the bank. In the circumstances, in the instant case termination of services of the workman would amount to retrenchment, within the meaning of sec. 25F of the I.D. Act.

18. Sec. 25F of the I.D. Act lays down that no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under as employer shall be retrenched by that employer until;

- (a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of such notice.
- (b) the workman has been paid, at the time of retrenchment compensation which shall be equivalent to fifteen days average pay (for every completed year of continuous service) or any part thereof in excess of six months; and
- (c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate government (or such authority as may

be specified by appropriate government by notification in the Official Gazette).

In the instant case there is nothing on record to show that the workman was given one month's notice in writing or one month's pay in lieu of notice or compensation referred to in the section quoted above. Naturally therefore, non compliance of the provisions of this section would amount to illegal termination of the services of the workman. The provisions of this section having not been complied with, the workman would be deemed as still continuing in service and entitled to back wages except for the period during which he had remained employed else where during this period.

19. I, therefore, hold that the action of the management is not justified. The management will therefore, reinstate the workman and pay him all back wages except for the period during which he remained employed elsewhere after the termination of his service. However, it is made clear that after the reinstatement of the workman the management will be at liberty to retrench/terminate his services in accordance with law.

Award is made accordingly.

Let six copies of this award be sent to Government of India, for its publication.

ARJAN DEV, Presiding Officer

[No. I-12012/92/85-D.H(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

कार. आ. 2575 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इंटग्रेल कोच फैक्ट्री मद्रास के प्रबंधकों से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25 अगस्त, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2575.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Integral Coach Factory, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th August, 1987.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Tuesday, the 11th day of August, 1987

PRESENT:

Thiru Fyazee Mahmood, B.Sc. B.L., Industrial Tribunal.
Industrial Dispute No. 81 of 1986

[In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the Management of Integral Coach Factory, Madras-600038].

BETWEEN

Thiru L. Rama Murthy,
C/o T. P. Thiruppal,
No. 5/23, Vasantha Garden Street,
1st Lane, Madras-600023.

AND

The General Manager,
Integral Coach Factory,
Madras-600038.

REFERENCE:

Order No. L-41012(48)/85-D.II(B), dated 29-5-1986 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Monday, the 10th day of August, 1987 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru T. P. Thiruppal, Authorised Representative for the workman and of Thiru A.J.D. Rozario, Authorised Representative for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following

AWARD

This dispute between the workman and the Management of Integral Coach Factory, Madras arises out of a reference under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L. 41012 (48)/85-D. II(B), dated 29-5-1986 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue:

"Whether the action of the General Manager, Integral Coach Factory, Madras, in removing Shri L. Ramamurthy, Khalasi, from service with effect from 30-10-82 is justified. If not, to what relief is the workman entitled."

(2) In the claim statement, it is submitted by the Petitioner Workman that he was appointed as a Khalasi in the Integral Coach Factory, Madras on 14-6-1973. He was issued with a charge memo on 18-3-1982 on an allegation of having misbehaved with the Assistant Shop Superintendent and having abused him in filthy language and refused to carry out the instructions given. He submitted an explanation to the charge memo and thereafter an enquiry was held. He attended the enquiry on 6-8-1982 and it was adjourned to 8-9-1982. On the same day, the enquiry was held ex parte though his mother had sent a letter dated 7-9-1982 to the Enquiry Officer seeking an adjournment of the enquiry. The ex parte enquiry conducted without giving a reasonable opportunity of defending himself is illegal. The action taken by the Punishing Authority and Appellate Authority on the enquiry findings cannot be sustained. It is prayed that the Petitioner-Workman may be reinstated in service from the date of removal with all back wages and other attendant benefits.

(3) In the counter statement filed, the allegations made by the Petitioner-Workman are denied. The Petitioner was workman as a Khalasi on 26-2-1982 misbehaved with his superior, Assistant Shop Superintendent and abused him in filthy language when he was instructed to carry out the work allotted to him. A charge memo was issued to him on 18-3-1982 for violation of the Railway Service (Conduct) Rules, 1966. He tendered an explanation dated 28-5-1982. As the explanation was not found satisfactory an enquiry was conducted as laid down under the Railway Servants (Disciplinary and Appeal) Rules, 1968. The Enquiry Officer afforded ample opportunity to the Petitioner to defend himself in the enquiry. As the Petitioner absented himself in the enquiry the Enquiry Officer proceeded ex parte. The Punishing Authority accepted the findings of the Enquiry Officer holding him guilty of the charges framed imposed the penalty of removal from service with effect from 30-10-1982. The Petitioner preferred an appeal which was dismissed. The Petitioner had deliberately abstained from attending the enquiry. The enquiry proceedings were conducted as per the Railway Servants (Disciplinary and Appeal) Rules and in accordance with the principle of natural justice. The termination of service of the Petitioner was valid and legal and therefore the claim petition has to be dismissed.

(4) A preliminary issue was framed to the following effect: "Whether the domestic enquiry held was valid and proper."

(5) No oral evidence was adduced on either side, Exs. W-1, W-2 and M-1 to M-18 were marked by consent.

(6) The only ground on which the enquiry has been assailed is that the Petitioner had not been given opportunity of participating in the enquiry and the Enquiry Officer had arbitrarily proceeded to hold an ex parte enquiry and found him guilty of the charges levelled. In dealing with the question, it is essential to set out certain facts which form the

background of the case. The Petitioner was employed as a Khalasi on 14-6-1973 in the Integral Coach Factory, Madras. On 18-3-1982, he was issued with a charge memo for having misbehaved with a superior, namely, Assistant Shop Superintendent on 26-2-1982 and abused him in a filthy language disobeying to carry out the work allotted to him. Ex. M-3 was the charge sheet which was served on the Petitioner. Annexure-1 to charge sheet reads as follows:

"That the said Shri L. Ramamurthy, T. No. 33/3085, while functioning as Khalasi in Shop 33 had misbehaved with Shri A. P. Jose, Assistant Shop Superintendent/PC/Fur. at about 13-45 Hrs. on 26-2-1982 and abused him in filthy language in Tamil when he was questioned for his refusal to carry out the instructions of ASS/PC/Fur. It is reported that his misbehaviour on 26-6-82 towards the ASS/PC/Fur. is not the first time. Shri L. Ramamurthy had also been orally warned earlier on two occasions i.e. on 4-12-81 and 19-1-82 for similar offences. In spite of that he had not improved his behaviour towards his supervisory officials. Thereby he failed to maintain devotion to duty and conducted himself in a manner unbecoming of a Railway Servant violating Rule 3(1)(ii) and 3(1)(iii) of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966."

List of documents, list of witnesses and material particulars were all furnished to the Petitioner as disclosed by the charge sheet Ex. M-3. Ex. M-4 dated 28-5-1982 was the explanation tendered by the Petitioner to the charge memo issued to him, in which he had while not unconditionally accepting the charges however pleaded to be excused and gave an assurance that such insubordination would not recur in future. As the explanation was not accepted, an enquiry on the charges framed as contemplated under the Railway Servants (Conduct and Appeal) Rules, 1968 was initiated. On 6-8-1982, the Petitioner appeared before the Enquiry Officer and denied the charges. He requested time till 12-8-82 to engage a defence counsel. The Enquiry Officer allowed him time upto 12-8-1982 and later extended this date at the request of the employee for nominating the defence counsel. The Petitioner did not nominate the defence counsel but sent a communication marked as Ex. M-9 to the Enquiry Officer stating that as he was unwell he was unable to attend the enquiry on 12-8-1982 and requesting four days extension of time for engaging his defence. The Petitioner was informed by Ex. M-10 that the departmental enquiry stood adjourned to 8-9-1982. On the said day, the delinquent-employee did not turn up for the enquiry, but a letter was received by the Enquiry Officer marked as Ex. M-11 (A), (the original of Ex. M-11) purported to have been sent by the mother of the Petitioner requesting that the enquiry be adjourned by two months on the ground that her son had lost his mental balance. This communication was received by the Enquiry Officer on 8-9-1982. The Enquiry Officer had proceeded with the enquiry on 8-9-1982 in the absence of the Petitioner. Ex. M-12 are the proceedings of the Enquiry Officer and Ex. M-13 (copy of which has been marked as Ex. W-2) are the findings of the Enquiry Officer.

(7) A perusal of the proceedings and the findings, disclose that the Enquiry Officer had acted on the evidence recorded in the enquiry in coming to the conclusion that the employee was guilty of the charges framed against him. The Enquiry Officer had also further pointed out that in the explanation to the charge memo the workman had also indirectly accepted the charge by expressing that such insubordination will not recur in future. The Enquiry Officer had assigned proper reasons for not accepting the letter sent by the mother of the Petitioner-workman seeking adjournment of the enquiry by two months as no proof had been adduced before the Enquiry Officer that the delinquent-employee was suffering from any mental imbalance and therefore not in a position to attend the enquiry. The Enquiry Officer had rightly pointed out that this petition was only a ruse adopted by the delinquent-employee to abstain from and prolong the enquiry. Accepting the findings of the Enquiry Officer by an order dated 23-10-1982 marked as Ex. M-14, the Petitioner was informed by the Punishing Authority that he was removed from service with effect from 30-10-1982. No show cause notice against the proposed punishment was issued as it was

not contemplated by the relevant rules as revealed by Ex. M-18. In the order of removal it was pointed out that he had been warned on two prior occasions for similar acts of insubordination. Ex. M-15 dated 11-12-1982 was the Appeal Petition sent by the Petitioner against the order of removal imposed on him. It is pertinent to note that in this communication, the Petitioner had stated as follows:—

“Although I attended the first inquiry on 6-8-1982 I requested for an adjournment for want of a Defence Council. The Inquiry was next fixed on 8-9-82. I could not attend the inquiry as I was indisposed on that day. However the Inquiry Officer treated my case as ‘Ex-parte’ and finalised the Inquiry Proceedings holding me guilty. Hence I was denied an opportunity of representing the actual facts at the inquiry.”

There was not a whisper made even at this stage about his inability to attend the enquiry on 8-9-1982 on account of any mental imbalance as stated in the letter sent by his mother marked as Ex. M-11(A). On the other hand, Ex. M-15 merely states that he could not attend the enquiry on 8-9-1982 as he was indisposed on that day. It clearly exposes the falsity of the contents of Ex. M-11(A) and is a clear indication that the delinquent had deliberately abstained from participating the enquiry on 8-9-1982 without assigning sufficient reasons. No oral or documentary evidence was produced before this Court to establish his mental illness during the relevant time. It only fortifies the falsity of his plea put forward. The Enquiry Officer was therefore perfectly justified in proceeding with the enquiry ex-parte and the Petitioner cannot complain of not having been given ample and reasonable opportunity of conducting his defence. In the circumstances, the validity of the enquiry conduct cannot be assailed and it has to be upheld as fair and proper. Considering the gravity of the misconduct committed by the employee and his past record of service, the punishment of removal from service calls for no interference under Section 11-A of the Industrial Disputes Act. Accordingly, the order of removal is upheld and the Petitioner held disentitled to reinstatement in service or any other relief.

(8) In the result, an award is passed dismissing the claim of the Petitioner-workman. There will be no order as to costs.

*Dated, this 11th day of August, 1987.

Sd./-Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For both sides: None.

DOCUMENTS MARKED

For workman:

Ex. W-1/22-7-85—True copy of letter from the Petitioner to the Ministry of Labour, New Delhi regarding non-employment.

Ex. W-2/8-9-82—True copy of the domestic enquiry findings.

For Management:

Ex. M-1/26-2-82—True copy of complaint given by ASS/PC to the Shop Superintendent.

Ex. M-2/26-2-82—True copy of complaint given by ASS/PC to the Works Manager.

Ex. M-3/18-3-82—Charge sheet with enclosure to the Petitioner.

Ex. M-4/28-5-82—Copy of letter from Petitioner to the Works Manager. (Explanation).

Ex. M-5/17-6-82—Xerox copy of letter from the Petitioner to the Works Manager to the charge memo.

Ex. M-6/19-7-82—Order of General Manager, Integral Coach Factory regarding appointment of Enquiry Officer. (xerox copy).

Ex. M-7/6-8-82—Proceedings of the Enquiry Officer. (xerox copy).

Ex. 8/6-8-82—List of charges framed against the petitioner during the enquiry.

Ex. M-9/12-8-82—True copy of letter from the Petitioner to the Works Manager seeking adjournment for the enquiry on 12-8-82.

Ex. M-10/19-8-82—True copy of letter from the General Manager, I.C.F. to the Petitioner.

Ex. M-11/7-9-82—Xerox copy of letter from Smt. Pushpavalli to the General Manager, Personal Branch Madras-38 seeking time for two months to participate in the enquiry by his son Thiru Ramamoorthy, the Petitioner.

Ex. M-11(A)/7-9-82—Original of Ex. M-11.

Ex. M-12/8-9-82—Enquiry Proceedings. (true copy).

Ex. M-13/8-9-82—Findings of the Enquiry Officer. (true copy).

Ex. M-14/23-10-82—Removal Order issued by the Management to the Petitioner Thiru L. Ramamurthy. (true copy).

Ex. M-15/11-12-82—Appeal against the removal order preferred by the Petitioner to the Additional Chief Mechanical Engineer, I.C.F., Madras. (true copy).

Ex. M-16/10-3-83—Letter from the Petitioner to the Additional Chief Mechanical Engineer, I.C.F., Madras requesting for reinstatement in service.

Ex. M-17/23-3-83—Reply to Ex. M-15 and M-16 issued by the Additional Chief Mechanical Engineer/Fur/ICF confirming the punishment.

Ex. M-18/13-12-78—A. C. Circular No. 173 of General Manager, I.C.F. Madras-38 regarding amendment of Service Rules.

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal

[No. L-41012/48/85-D.H(B)]

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1987

का. अ. 2576-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसर्ग में, केन्द्रीय सरकार, आकाशवाणी के प्रवर्तन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20 अगस्त, 1987 को प्राप्त हुआ था

New Delhi, the 7th September, 1987

S.O. 2576.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of All India Radio and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th August, 1987.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
NEW DELHI

I.D. No. 37/86

In the matter of dispute between :

Shri Bikram Singh S/o Smt. Chandan Singh H. No. RZ-258 B/42, Raj Nagar, Palam Colony, New Delhi-45.

Versus

The Chief Engineer, North Zone, All India Radio, Jam Nagar, New Delhi.

APPEARANCES:

Shri Multan Singh—for the workman.

Shri Narinder Chaudhary with Shri M. C. Sharma—for Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-42012(6)/84-D.II(B) dated 14-2-86 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of All India Radio in relation to its Chief Engineer and Director General of All India Radio in terminating the services of Shri Bikram Singh with effect from 25-7-83 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. It is stated by the workman that he served the Management from 31-11-81 to 25-7-83 whereafter his services were terminated without any notice, charge sheet or enquiry and without payment of any notice pay or retrenchment compensation. The action of the Management was clearly illegal and unjustified as the mandatory provisions of the I.D. Act had not been complied with. Hence the workman sought his reinstatement with continuity of service and with full back wages.

3. The Management in its written statement submitted that the workman was kept for casual work which after being achieved he was removed as no work was existing at the time of removal from service. It was denied that the workman continued to work without any break. It was further stated that the removal was because of non-availability of the work and the workman cannot be given benefit.

4. The parties did not produce any oral evidence and placed reliance on the documents placed on record. The Management itself has placed on record statement Ex. M-1 showing the attendance of the workman as casual labour for the period from 13-11-81 to 2-7-83. As some periods were missing from this statement the Management submitted a further statement Ex. M2 showing the attendance of the workman for the period from 21-8-82 to 5-9-82 and 3-7-83 to 17-7-83. A combined reading of Ex. M-1 and M-2 goes to show that the workman had put in total about 258 days during the period 1-8-82 to 25-7-83 which means that he had completed one year's continuous service as defined in section 25-B of the I.D. Act and consequently he had become entitled to the benefits conferred by Section 25-F of the I.D. Act. The Management had admittedly not given any notice nor paid any wages in lieu of notice period nor paid any retrenchment compensation and, therefore, the termination of the service of the workman was clearly in violation of the mandatory provision of section 25-F of the I.D. Act.

5. The contention of the Management that the workman was employed only as casual worker and he is not entitled to any retrenchment compensation and that the protection of section 25-F (and 25-G) of the Act is not applicable to him is devoid of any force. This controversy has been set at rest by the Authority Workmen of MCD and another Vs. Management of MCD and another 1987 (1) LLJ 85 Delhi High Court wherein it was held as under:—

"Industrial Disputes Act, 1947 Section 2(S) and 25-F Daily rated workman—Retrenchment of daily rated worker—Procedure to be followed—Condition precedent laid down in Sec. 25(F) would apply even to daily rated worker if he had put in the requisite service during the relevant period. Lumpsum compensation awarded towards back wages since the worker was daily rated worker and on account of difficulty in ascertaining the number of days such worker might have worked.

Industrial Dispute relating to the non-employment of a workman was referred for adjudication to the Additional Industrial Tribunal, Delhi. The said workman was employed on a daily rated basis as a pipe fitter, Slum Department of the Municipal Corporation of Delhi. Based on the contention that the scheme in which the workman was employed was transferred to Delhi Development Authority and, therefore, the workman cannot claim any relief against Delhi Municipal Corporation, the Labour Court dismissed the claim of the workman. Hence the writ petition by the workman.

Held.—When the petitioner was not assigned any further work it amounts to termination and on that date the department was admittedly with the Municipal Corporation, Delhi. It is well settled that Section 25(F) of the I.D. Act is plainly intended to give relief to retrenched workman. The qualification for relief under Section 25(F) is that the person should be a workman employed in an industry and has been in continuous service for not less than one year under his employer. What is continuous service has been defined and explained in Section 25(B) of the I.D. Act. The workman who is not in continuous service for a period of one year shall be deemed to be in continuous service if the workman during the period of 12 months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than 240 days. Daily rated workman is as good a worker provided he has put in the requisite number of days of service during the relevant period. Once a daily rated worker has rendered continuous uninterrupted service for a period of one year or more within the meaning of Section 25(F) of the I.D. Act the condition enumerated in that section has to be complied with. Non-compliance with this provision would render the termination invalid."

6. In view of the discussion made above the action of the Management in terminating the services of Shri Bikram Singh with effect from 25-7-83 is illegal and unjustified and the workman is entitled to reinstatement with continuity of service and with full back wages. This reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

Dated 11th August, 1987.

G. S. KALRA, Presiding Officer

[No. L-42012/6/84-D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

का. आ. 2577 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गण में, केन्द्रीय सरकार, कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्तर्गण में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2577.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the National Bank for Agricultural and Rural Development and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st August, 1987.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
NEW DELHI

I.D. No. 20/87

In the matter of dispute between :

Secretary, National Bank of Agriculture
and Rural Development.

Vs.

National Bank of Agriculture
and Rural Development, New Delhi..

APPEARANCES :

Shri Subhash for the Union.

Shri S. S. Sharma for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-12011/44/85-D.II(A) dated 17th March, 1987 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of National Bank for Agriculture and Rural Development in making appointment of S/Shri Bhupal Singh and Naresh Kumar Chawla in the clerical cadre without following the normal recruitment rules and without giving opportunity to the subordinate staff for consideration for appointment to the post is justified ? If not, to what relief the eligible subordinate staff is entitled to ?"

The union of the workman filed statement of claim stating that the management attempted to appoint two persons namely Bhupal Singh and Naresh Kumar Chawla as clerks on 7-1-1985 at its Delhi Regional Office without holding any test, interview etc. and the Union staged protest with the local Management. It was further stated that the appointments were the result of favouritism and against specific instructions issued by the Government of India to fill the vacancies through Employment Exchange and other permissible sources could be tapped only if the Employment Exchange issued non-availability certificate but the Management violated the instructions and attempted to recruit the above persons arbitrarily. Out of the two persons in question one was the son of a Cook of one of the Directors of the National Bank, Dr. Sen and the other was his friend's nephew. These two persons were only matriculate whereas the subordinate staff working in the NABARD at New Delhi had qualifications of graduation beside service of considerable years in the NABARD and in the Reserve Bank of India. According to the NABARD (staff) Rules, 1982 vacancies in the clerical cadre are to be filled in by direct recruitment of under-Graduates on the basis of written test and interview conducted by the selection board of the NABARD and further that the subordinate staff in group 'C' shall also be considered for appointment alongwith the outside candidates provided they fulfil the eligibility conditions. The Management acted in violation of these rules. Further, the NABARD had advertised vacancies available under group 'B' in the year 1983 and had conducted written test and interview on all India Basis and a large number of persons were recruited and also waiting list panel was considered regarding people from the said waiting list panel. The action of the Management clearly violated the provisions of article 16 of the Constitution which guarantees equality of opportunity to all in matters of public employment. In the light of these submissions the Union of the workman sought the following reliefs :

- to decry the act of the National Bank as illegal ab initio.
- to restrain the National Bank from committing such acts in future, and
- to take such action against the erring Officers as the Hon'ble Court may deem fit.

3. The Management filed written statement in which the allegations of the workmen were controverted and it was

submitted that the proposed appointment of Sarvshri Bhupal Singh and Naresh Kumar Chawla was purely on ad-hoc and temporary basis for an initial period of one year only to attend to certain urgent works and such appointment could be made in terms of rule 8 of NABARD (Staff) Rules 1982. It was denied that these appointments were sought to be made for favouritism. It was further stated that appointments had not since been made and subsequently the position was reviewed and the Management have decided to revoke the orders of appointment issued to the aforesaid two persons and they were not being appointed to the service even on ad-hoc basis. It was, therefore, prayed that the matter may be treated as closed, as the dispute no longer survives.

6. The Management had placed on record an attested copy of the letter No. NBNDSSE.36(1D)4463/86-87 dated 5-3-87 addressed to the Ministry of Labour, Government of India to the effect that on re-consideration it has been decided not to appoint S/Shri Bhupal Singh and Naresh Kumar in the service of NABARD and to treat the matter as closed. The Management has also produced copies of letter Nos. NB(ND)/SF. 36/2/87/87-88 and No. NB(ND)/SF. 36-288-87-88 dated 30-7-87 addressed to S/Shri Bhupal Singh and Naresh Kumar whereby the officer of appointment made earlier has been withdrawn, Shri S. S. Sharma who appeared on behalf of the Management also made statement that the persons mentioned in the terms of reference have not been allowed to join the service of NABARD and their order of appointment has been withdrawn and the NABARD has no intention to appoint these persons. Shri Subhash appearing on behalf of the Union of the workman admitted the statement made by Shri S. S. Sharma and further stated that the initial appointment of these workmen was illegal and against the rules and this point may be decided.

7. It is apparent from the documents placed on record and the statements made by the representative of the parties that Shri S/Shri Bhupal Singh and Naresh Kumar Chawla have not been allowed to join in the clerical cadre of the NABARD and in fact the offer of appointment to them has also been withdrawn. Under these circumstances the dispute no longer survives and it will not serve any useful purpose to enter into a consideration of the question whether the initial appointment of these persons was illegal and against the rules. Hence this matter is treated as closed and the reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

Dated 10th August, 1987.

G. S. KALRA, Presiding Officer

[No. L-12011/44/85 D II(A)D.V(A)]

का. आ. 2578 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार, दृष्टिकोण पक्षन व्यास के प्रबंधन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्तर्गत में निश्चित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण तमिलनाडु के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-8-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd September, 1987

S.O. 2578.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Tamilnadu as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Tuticorin Port Trust and their workman which was received by the Central Government on the 26th August, 1987.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL TAMIL NADU
MADRAS

Friday, the 7th day of August, 1987

PRESENT :

Thiru Fyze Mahmood, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal
Industrial Dispute No: 30 of 1986

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the Management of Tuticorin Port Trust, Tuticorin.)

BETWEEN

The workman represented by
The Assistant Secretary,
Tuticorin Port Drivers Union,
45/P, Poobalarayapuram, 2nd Street,
Tuticorin-682 001.

AND

The Chairman,
Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

REFERENCE :

Order No. L-44012/1/85-D.IV (A), dated 30-4-1986 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 29th day of July, 1987 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru G. Balaraman, authorised representative for the workman and of Thiru M. Venkatachalapathy, Advocate appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

This dispute between the workman and the Management of Tuticorin Port Trust, Tuticorin arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-44012/1/85-D.IV (A), dated 30-4-1986 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

"Whether the Chairman, Port Trust, Tuticorin is justified in inflicting the punishment of stoppage of two increments for two years to Shri P. Manuelraj, Motor Driver. If not to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. In the claim statement filed, it is stated that Thiru Manuelraj was working as a Motor Driver and was issued with a charge sheet dated 15-5-1984, to which he had rendered an explanation. By an order dated 19-6-1984, the punishment of stoppage of annual increment for two years was imposed. According to the Petitioner Union the punishment is unjustified. The Petitioner-Union had raised an industrial dispute and pointed out the irregularities committed by the Tuticorin Port Trust Authorities and in their not following the guidelines for allotting vehicles to motor drivers. Thiru Manuelraj was the Secretary of the Port Drivers Union. He had made a representation to the Chairman, Tuticorin Port Trust. The reply given by the Chairman stated that there has been no discrimination in the matter of allocation of vehicles. Thiru Manuelraj had sent a further representation to Chairman stating that the rejection of his earlier representation was baseless and he did not accept the blanket statement of the Chairman. On the basis of this letter, a charge memo was issued to him. It is contended that he had not used any disrespectful and unparliamentary language which warrants any punishment. It is further stated that the Respondent is an Industrial Establishment, for which the provisions of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 applies. As there are no certified Standing Orders applicable to the Tuticorin Port Trust, the Model Standing Orders would apply. According to the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946, before imposing any penalty an enquiry should have been conducted. As no enquiry has been conducted in the instant case the punishment imposed has to be set aside. It is also urged that the order imposing punishment was not passed by the competent authority under the Tuticorin Port Employees (Classification Control and Appeal) Regulations, 1979.

(3) In the counter statement filed on behalf of the Respondent, the allegations made in the claim statement are

denied. It is stated that the action was taken against the workman Thiru Manuelraj on the ground of disrespectful and unparliamentary language used by him in his letter dated 18-4-1984 addressed to the Chairman. The plea that the penalty of withholding one annual increment for two years without cumulative effect could not be imposed without any enquiry is not tenable. Under Regulation 12 of the Tuticorin Port Employees Classification, Control and Appeal Regulations, 1979, for imposing minor penalties as done in the instant case holding of an enquiry is not obligatory and can be dispensed with by the disciplinary authority. The appeal filed by the workman had also been dismissed by the Chairman. Tuticorin Port Trust is not an Industrial Establishment within the meaning of the Industrial Establishment (Standing Orders) Act, 1946. The provision of the Act are also not applicable to the Port Trust in view of Section 13-B of the Act. Hence the plea of the Petitioner that the enquiry should have been conducted as required by the Model Standing Orders is untenable. The Secretary being the Head of the Department is the competent authority as defined in the Regulation to impose the punishment of stoppage or increment. The punishment imposed on the workman was not only justified but also lenient. Hence the workman is not entitled to any relief.

(4) The point for consideration is as contained in the reference.

(5) No oral evidence was adduced on either side. Ex. W-1 to W-23 were relied upon by the Petitioner and Exs. M-1 to M-5 marked on behalf of the management.

(6) The workman Thiru Manuelraj was employed as a Motor Driver in the Tuticorin Port Trust. Ex. W-3 dated 1-12-1982 were the orders issued by the Chairman of the Tuticorin Port Trust for streamlining the procedure for rotation of Drivers. Ex. W-4 dated 17-2-1983 is a copy of the Labour Ministry's Order, wherein certain guidelines were given to streamline the procedure for rotation of Drivers of the Tuticorin Port Trust. This was made on a dispute raised by the Tuticorin Port Drivers Union over the demand for the rotation system. The Management of Tuticorin Port Trust as indicated in Ex. W-4 had decided to adopt the guidelines issued by the Labour Ministry. The Petitioner is the General Secretary of the Tuticorin Port Drivers Union. In his capacity as the General Secretary he had made representation to the Chairman marked as Ex. W-5 dated 9-1-1984 alleging that there has been discrimination made against him in the rotation system of Drivers employed in the Tuticorin Port Trust in reply to this representation, the Chairman had issued an order marked as Ex. W-7 wherein it was stated that the representation had been carefully examined and all the allegations were found to be baseless and no discrimination was shown in the matter of allocation of vehicles. In reply to this communication, the workman had written Ex. W-8 to the Chairman, the contents of which are hereby extracted :

MATTER-I TAMIL

It is these words addressed to the Chairman which invited the charge memo Ex. W-9 issued to the concerned workman Thiru Manuelraj. In the charge memo it was stated that he had used unparliamentary and disrespectful against the Chairman and thereby acted in a manner unbecoming of an employee of the Board and contravened Regulations 3 and 6 of the Tuticorin Port Employees (Conduct) Regulations, 1979. Ex. W-10 was the explanation tendered by the workman to the charge memo issued to him. In it, he had denied that he used unparliamentary and disrespectful words against the Chairman. He had further stated that the letter from the Chairman to the earlier representation made by him characterised his grievances as baseless and it had instigated him to write the letter Ex. W-8 to the Chairman, that such a reply would be expected only from a dictator and

not from a competent authority like a Chairman. Thereafter, after considering the representation, an order dated 19-6-1984 marked as Ex. W-11 was passed by the Secretary, Tuticorin Port Trust imposing the penalty of withholding of one increment for a period of two years without cumulative effect. Appeal filed by the workman to the Chairman was also dismissed by an order dated 20-8-1984 marked as Ex. W-13.

(7) The Authority Representative for the workman has first contended that the words used by the workman in Ex. W-8 cannot amount to any misconduct under the Regulations as to hold the workman guilty of using disrespectful language against the official. The relevant Regulations are 3 and 6 of the Tuticorin Port Employees (Cehduct) Regulations, 1979, an extract of which had been marked as Ex. W-19. There are no merits in this contention and on the language used by the workman, whatever the provocation may be, he had been rightly held guilty of the charge of misconduct levelled against him.

8. The second plea urged is that the Secretary of the Port Trust is not the competent authority to impose the punishment as he is not the Head of the Department. In rejecting this contention, it is sufficient to advert to Ex. M-5, a letter issued from the Government of India, Ministry of Shipping and Transport which clearly stipulates that under Sub-Section (2) of Section 24 of the Major Port Trusts Act, 1963, the incumbents of the following posts in the Tuticorin Port Trust shall be regarded as Head of the Department for the purpose of the said Act.

- (1) Financial Advisor & Chief Accounts Officer.
- (2) Secretary.
- (3) Chief Engineer.
- (4) Deputy Conservator.
- (5) Traffic Manager.

This negates the contention raised that the Secretary is not the Head of the Department and as such not competent to impose the minor penalty of stoppage of increment. In this context, it may also be pointed out that as disclosed by Ex. W-23, the workman Thiru Manuelraj was initially appointed as a Driver by the Deputy Conservator, Tuticorin Port Trust who is admittedly an authority subordinate to the Secretary of the Tuticorin Port Trust. Hence the above plea is rejected as untenable.

(9) The next argument advanced on behalf of the workman is that the Respondent is an Industrial Establishment according to the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946. As there has been no separate certified Standing Orders pertaining to the Respondent Establishment, as per Section 12-A of the said Act, the Model Standing Orders would be applicable which would entail an enquiry being conducted before imposition of the penalty of stoppage of increment. In the circumstances, the imposition of the penalty in the instant case invoking the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979 cannot be sustained. In appreciating this argument, it is relevant to refer to clause 2(c) of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 which defines an "Industrial Establishment" to include (1) an industrial establishment as defined in clause (ii) of Section 2 of the Payment of Wages Act, 1936." For the purpose of this case, it would be sufficient to refer to this clause alone in the definition of "Industrial Establishment" as it would include "Port" by virtue of the provisions contained in clause 2(b) of the Payment of Wages Act. Under Section 12-A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, where there are no separate Standing Orders applicable to the establishment, the Model Standing Orders would be applicable and shall be deemed to be adopted by the establishment concern.

(10) The learned counsel for the Management has not seriously disputed the fact that the Tuticorin Port Trust would constitute an 'Industrial establishment' as defined in the Industrial Employment (Standing Orders) Act. However he would take shelter under Section 13-B of the Act which reads as follows :

"Nothing in this Act shall apply to an industrial establishment in so far as the workmen employed therein are persons to whom the fundamental and Supplementary Rules, Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, Civil Services (Temporary Service) Rules, Revised Leave Rules, Civil Service Regulations, Civilian in Defence Service (Classification, Control and Appeal) Rules or the Indian Railway Establishment Code or any other rules or regulations that may be notified in this behalf by the appropriate Government in the Official Gazette, apply."

According to the learned counsel for the Management, the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979 had been brought into effect in exercise of the powers conferred under Section 126 read with Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 and notified by the Central Government in the Gazette. It is these Regulations which would apply to the workmen of the Tuticorin Port Trust, Industrial Employment (Standing Orders) Act cannot be invoked as it would be inapplicable by virtue of Section 13-B of the Industrial Employment (Standing Orders) Act. This argument proceeds on a fallacy and misconception of provisions contained in Section 13-B of the Industrial Employment (Standing Orders) Act. The clause contained in Section 13-B "any other rules or regulations that may be notified in this behalf by the appropriate Government in the Official Gazette" properly construed in the context in which these words appear in Section 13-B of the Industrial Employment (Standing Orders) Act could only mean Rules and Regulations that may be notified by the appropriate Government for the purpose of Industrial Employment (Standing Orders) Act. In the instant case, the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979 relied upon by the Respondent were admittedly not regulations that were notified under Section 13-B of the Industrial Employment (Standing Orders) Act to enable to the Respondent to take the plea that the provisions of the Industrial Employment (Standing Orders) Act are not applicable to the Tuticorin Port Trust. In this context reference may be made to the observations of the Supreme Court which are very germane to the point in issue rendered in 1978-II-L.L.J. Page 399 (U.P. State Electricity Board and others vs. Hari Shankar Jain and others)

"The Industrial Establishments (Standing Orders) Act is a special law in regard to matters enumerated in the Schedule and the Regulations made by the Electricity Board with respect to any of those matters are of no effect unless such regulations are either notified by the Government under Section 13-B or certified by the certifying Officer under Section 5 of the Standing Orders Act."

The above judgment of the Supreme Court has been followed by the Madras High Court in the decision reported in 1984-II-L.L.J. Page 132 (Pallavan Transport Corporation (Metro) Madras-2 vs. Presiding Officer, 1 Additional Labour Court, Madras), wherein, it was held as follows :

"From the date on which the Act became applicable to P.T.C. establishment till the date of the certified Standing Orders finally coming into force, by virtue of Section 12-A of the Act the Model Standing Orders governed the relationship between P.T.C. and its employees and such Model Standing Orders had the same legal efficacy to govern the terms and conditions of service in industrial establishments to which the Act applies during the relevant period, as the certified Standing Orders have. It was further held that the Service Rules framed by the employer could be of avail to the employer only if such Service Rules could be brought within Section 13-B of the Act, and that the Service Rules framed by the employer could not be invoked and the Model Standing Orders would alone apply to the workmen."

In the light of the above decision, in the instant case, the Respondent cannot invoke the provisions of the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979 for imposing punishment and should have adopted only the Model Standing Orders as contained in Schedule I

of the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules 1946. A perusal of clause 14 of the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules would disclose that in imposing an order of dismissal or stoppage of annual increment or reduction in rank, the employer would have to conduct an enquiry into the misconduct levelled and only after the workman had been found guilty of the charges framed, and given a reasonable opportunity of making representation on the penalty proposed, the employer could take appropriate action. In the instant case, no enquiry had been conducted on the misconduct levelled as envisaged by the above rules. But on the other hand, the Respondent had proceeded to impose the punishment invoking the provisions of the Tuticorin Port Employees (Classification Control and Appeal) Regulations, 1979, under which such enquiry could be dispensed with for the punishment of withholding of increment which is classified as a minor penalty.

11. The further argument advanced by the learned counsel for the Respondent that as the workman had admitted the charges there is no need for enquiry is baseless and not factually correct. The workman had only conceded having written a letter Ex. W-8 but had not admitted his guilt at any point of time. In as much as no disciplinary proceedings were initiated against the workman under the Model Standing Orders applicable to him for the misconduct committed the imposition of penalty of stoppage of one increment for a period of two years without cumulative effect as disclosed by Ex. W-11 invoking the provisions of Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979 cannot be sustained and have to be necessarily set aside.

12. In the result, the punishment of stoppage of one annual increment for a period of two years without cumulative effect is set aside and the workman exonerated of the charge levelled. Award passed accordingly. There will be no order as to costs.

Dated, this 7th day of August, 1987.

Sd/-

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal
WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For the workman :

- Ex. W-1/10-6-82—Minutes of Conciliation Proceedings before Assistant Labour Commissioner. (copy)
- Ex. W-2/13-8-82—Conciliation failure report. (copy)
- Ex. W-3/1-12-83—Procedure for rotation of Drivers in Tuticorin Port. (copy)
- Ex. W-4/17-2-83—Labour Ministry's Order. (copy)
- Ex. W-5/9-1-84—Application by Thiru Manuelraj to the Management. (copy)
- Ex. W-6/9-2-84—Union's representation. (copy)
- Ex. W-7/29-2-84—Chairman's reply to Thiru Manuelraj. (copy)
- Ex. W-8/18-4-84—Reply by Thiru Manuelraj to Chairman. (copy)
- Ex. W-9/15-5-84—Charge Memo. (copy)
- Ex. W-10/22-5-84—Reply given by Thiru Manuelraj. (copy)
- Ex. W-11/19-6-84—Copy of punishment order with findings of Disciplinary Authority.
- Ex. W-12/4-7-84—Appeal to the Chairman. (copy)
- Ex. W-13/20-8-84—Order dismissing the Appeal. (copy)
- Ex. W-14/29-10-84—Union's letter to Assistant Labour Commissioner. (copy)
- Ex. W-15/23-1-85—Minutes of Assistant Labour Commissioner. (copy)
- Ex. W-16/12-4-85—Failure report of minutes. (copy)
- Ex. W-17/22-4-85—Conciliation Failure Report. (copy)

Ex. W-18/6-4-83—Copy of Chief Engineer's letter to the Secretary, Port Drivers Union.

Ex. W-19 —Extract of Tuticorin Port Employees (Conduct) Regulations, 1979.

Ex. W-20/5-9-86—Letter from the Tuticorin Port Mariners' and General Staff Union, Tuticorin addressed to the Assistant Labour Commissioner (C), Trivandrum regarding violation of Labour Ministry's Order. (Photostat copy).

Ex. W-21/ —Minutes of the discussions held on 25-10-1980.

Ex. W-22/19-6-73—Appointment Order of Thiru Manuelraj as Conductor. (Photostat copy).

Ex. W-23/17-12-75—Appointment Order of Thiru Manuelraj as Driver. (Photostat copy).

For Management :

Ex. M-1/1-8-81—Xerox copy of letter from the Tuticorin Port Drivers' Union to the Management.

Ex. M-2/31-12-82—Xerox copy of letter from the Tuticorin Port Drivers' Union to the Management.

Ex. M-3/17-11-83—Xerox copy of letter from the Tuticorin Port Drivers' Union to the Management.

Ex. M-4/14-11-83—Xerox copy of letter from the Drivers' Union to the Management.

Ex. M-5/27-5-80—Xerox copy of Government of India notification addressed to the Management along with schedule.

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal

[No. L-44012/1/85-D.IV (A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1987

का.ग्रा. 2579.—न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 13-12-86 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 3 दिसम्बर, 1986 को भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.ग्रा. 4172 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली के कार्यालय में उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) श्री ज. कानाकैया को न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का सचिव नियुक्त करती है, जिसका गठन भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 28 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या का.ग्रा. 393(अ) के तहत किया गया था।

[संख्या एस-32023/11/83 - डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

ए. के. लुथरा, उप सचिव

New Delhi, the 8th September, 1987

S.O. 2579.—In exercise of the powers conferred by Rule 6 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950 and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4172 dated the 3rd December, 1986 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 13th December, 1986, the Central Government hereby appoints Shri J. Kanakiah Deputy Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, in the Office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi to be the Secretary of the Minimum Wages Advisory Board constituted under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 393(E) dated the 28th May, 1981.

[No. S-32023/11/83-WC(MW)]

A. K. LUTHRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1987

का.प्र. 2580—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार गोविन्दपुर कोलिरी, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन के सम्बन्धित श्रमिकों और उनके कामकाज के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, संस्था-1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार का 25 अगस्त, 1987 का प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 9th September, 1987

S.O. 2580.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Govindpur Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 73 of 1986

In the matter of industrial dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri B. Lal, Advocate and Shri D. K. Verma, Advocate.

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 18th August, 1987

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad. Subsequently vide their Order No. S-11025(5)/85-D. IV B) dated 14-1-1986 the said reference was transferred to this Tribunal from Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, for adjudication.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Govindpur Area No. III of Messrs. Bharat Coking Coal Limited is justified in demoting Shri Rampati Saran, Laboratory Technician from Grade-B to Grade-C from 13-10-1982 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Rampati Saran was employed on 7-11-1978 as Laboratory Technician in Grade-C in Govindpur Area No. III of M/s. B.C.C.L. He was posted in Govindpur dispensary of Area No. III and is still working there. Vide letter dated 3/8-4-1982 the concerned workman was promoted from Grade-C to Grade-B by the G. M. of Area No. III. He was promoted after being interviewed by the members of the D.P.C. constituted by M/s. BCCL authorities. During the course of interview the D.P.C. examined the certificates and testimonials produced by the concerned workman and on being satisfied, the D.P.C. recommended for his promotion from Grade-C to Grade-B. Thereafter the G.M. had issued

the letter promoting him from Grade-C to Grade-B. The concerned workman continued to work in Grade-B and received the salary of Grade-B from April, 1982 to October, 1982. All of a sudden the concerned workman was demoted from Grade-B to Grade-C by the order of the G.M. Govindpur area vide letter dated 12/13-10-1982. The Manager of Govindpur Colliery did not disclose any reason for the demotion of the concerned workman and the said order is arbitrary, illegal and unjustified.

The concerned workman is a member of Koyla Ispat Mazdoor Panchayat which is a trade union organisation functioning in Govindpur Area No. III of M/s. BCCL. The said union protested against the arbitrary and illegal order of demotion of the concerned workman before the G. M. Govindpur Area vide letter dated 18-10-1982 and had requested to revise the order of the demotion of the concerned workman. The General Manager, Govindpur Area did not pay any heed to the Panchayat's request for revision of his arbitrary order. Thereafter the said Panchayat requested the ALC(C), Dhanbad vide letter dated 13-12-1982 to intervene in the matter. The management appeared in the conciliation before the ALC(C) but the conciliation ended in failure. Thereafter the present reference was made. It is further contended on behalf of the workmen that besides the recommendation of the D.P.C. in the matter of promotion the General Manager also on being satisfied promotes a workman from lower category/grade to higher category/grade. The G.M. had promoted Shri D.K. Pandey, Laboratory Technician of Loyabad Hospital, Shri R. K. Choudhury and Shri B. Prasad, Lab. Technician of Loyabad Hospital of BCCL. The General Manager has jurisdiction to promote workman of his area. The condition of five years experience in a particular grade is not strictly adhered to for giving promotion to a higher grade. Shri D. K. Pandey was employed in Grade-C in the year 1977 and was promoted to Grade-B on 1-1-1979. The cancellation of the order of promotion of the concerned workman by the G.M. of Area No. III was wholly unjustified and illegal and as such it has been prayed that the management be directed to restore Grade-B to the concerned workman with payment of difference of wages of Grade-C and Grade-B from November, 1982 till the date of Grade-B is restored to the concerned workman.

The case of the management is that the concerned workman who is a Lab. Technician belongs to the cadre of para medical staff (Technical) posted at the dispensary of Govindpur Colliery. The concerned workman had joined his duties as Lab. Technician as a new recruit on 7-11-1978 and was placed in Grade-C. JBCCI constituted under NCWA-II formulated a cadre scheme in the year 1980 in respect of para medical staff (Technical) for fixation in proper grade and for effecting promotion from lower grade to higher grade. The said cadre scheme is legal and binding both on the workmen and the management. As per the above cadre scheme of JBCCI-I a Technician/Path. Technician/Radiographer is fixed in Grade-C. He is entitled to be considered for promotion to the post of Sr. Technical Grade-B after completion of five years of experience as Grade-C Technician. He also must possess diploma in respective technology from recognised institute. His minimum basic qualification is matriculation. Their seniority has to be considered companywise and not are wise. In view of the above cadre scheme, grade-C Technician of all the hospitals, dispensaries and office of M/s. BCCL. are to be grouped together for determining their interse seniority. The D.P.C. constituted by the headquarters can recommend for promotion from Grade-C technician to Grade-B Sr. Technician. The promotion order issued to the concerned workman by the Area G. M. vide Letter dated 3-4-1982 was in violation of the cadre scheme. The concerned workman had not completed 5 years of service in Grade-C and as such he was not eligible for promotion from Grade-C to Grade-D. The case of the concerned workman for promotion from Grade-C to Grade-D had not been cleared by the D.P.C. constituted by the headquarters. As such the promotion order dated 3-4-1982 was illegal and void. The G. M. Subsequently found that he had issued the order of promotion of the concerned workman from Grade-C to Grade-B in violation of the cadre scheme and without obtaining clearance from the headquarters of the management and as such he cancelled the order of promotion dated

9/4/1982. It has been submitted on behalf of the management that as the original order of promotion of the concerned workman was illegal void and without jurisdiction the conciliation of the order does not amount to demotion of the concerned workman as alleged. In view of the above it is submitted that the workman is not entitled to any relief.

The only point for consideration is whether the management was justified in demoting the concerned workman from Grade-B to Grade-C with effect from 13-10-1982.

The management examined one witness and the workman examined three witnesses to prove their respective case. The documents on behalf of the management are marked as Ext-M-1 and M-2 and the documents of the workman have been exhibited as Ext. W-1 to W-5.

The facts of the case are admitted by the parties. It is admitted that the concerned workman Shri Rampati Saran was appointed as Lab. Technician in Grade-C and was posted on 7-11-1978 at Govindpur dispensary of Area No.—11 of M/s. BCCL. It is also admitted that the concerned workman was promoted from Grade-C to Grade-B by the G.M. vide letter dated 3/8-4-1982. The said office order of promotion of the concerned workman from Grade-C to Grade-B is Ext. W-4 in the case. The said office order Ext. W-4 shows that the G.M. of Govindpur Area had promoted the concerned workman from Grade-C to Grade-B with immediate effect and that the wages of the concerned workman was to be fixed as per company's norms. Ext. W-5 is another office order dated 30-4-1982/5-5-1982 issued by the Agent/Manager of Govindpur colliery showing that in pursuance of the office order dated 3/8-4-1982 (Ext. W-4) issued by the G.M. Govindpur Area, the concerned workman was promoted from Grade-C to Grade-B in the scale of pay of Rs. 640—1160 with effect from 8-4-1982. This Ext. W-5 was issued by the Agent/Manager of Govindpur Colliery in pursuance of the office order passed by the G.M. of Govindpur Area. It is also admitted by the parties that the office order dated 3/8-4-1982 issued to the concerned workman of Govindpur dispensary was withdrawn with immediate effect by the G.M. Govindpur Area vide his office order dt. 29/30-9-1982. The said order is Ext. M-2. Admittedly no reason has been given as to why the promotion order of the concerned workman dated 3/8-4-1982 was withdrawn by the G.M. Govindpur Area. Ext. M-2 only shows that the concerned workman was informed that his case for promotion shall be considered by the headquarters in due course of time as per laid down norms of cadre scheme. This was added at the foot of office order at Ext. M-2 and even this note does not disclose the reason why the promotion order of the concerned workman was withdrawn by the G. M. of Govindpur Area.

The case of the management is that the promotion of Technician is done according to the cadre scheme. Ext. M-1 is the cadre scheme of para-medical staff (Technical). Admittedly the concerned workman who was working as a Lab. Technician at the dispensary of Govindpur Colliery was a para-medical staff. Thus Ext. M-1 is the cadre scheme according to which the promotions of the concerned workman can be made. This cadre scheme came into effect from 8-5-80. The cadre scheme had been drawn in consultation with the union and the management and the representatives of both had signed on the said cadre scheme as will be evident from Ext. M-1. On perusal of Ext. M-1 it will appear that for promotion of a para-medical staff Technician from Grade-C to Grade-B, five years experience as Grade-C Technician is the criteria for eligibility for promotion. The qualification required are that he should possess a diploma in respective Technology from recognised institute and he must be at least a matriculate. It is also provided the mode of promotion according to which the seniority was to be considered companywise. The concerned workman was promoted from Technical Grade-C to Technical Grade-B vide Ext. W-4 dt. 3/8.4.82. It is clear therefore that the concerned workman was promoted from Technical Grade-C to Technical Grade-B when the cadre scheme for the para-medical staff had come into effect and as such his promotion should have been in accordance with the cadre scheme. Ext. M-1. Admittedly the concerned

workman had joined as a Lab. Technician on 7-11-78 in Grade-C and he was promoted from Grade-C to Grade-B with effect from 8-4-82. Thus the concerned workman had not completed five years of experience in Technical Grade-C so that he could be eligible for being considered for promotion in Technical Grade-B. Moreover, according to the cadre scheme Ext. M-1 the seniority of the para-medical staff was to be considered companywise. The G.M. of an area was therefore not in a position to say about the seniority of the concerned workman on the companywise basis.

MW-1 Shri M. K. Singh is the Dy. Personnel Manager of Area No. III. He has stated that the concerned workman belongs to the para-medical staff and is presently in Grade-C. He has stated that the promotion in respect of para-medical staff under the cadre scheme from Grade-C to Grade-B is considered at the company's level and not at the area level. He has further stated that for considering the promotion of para-medical staff the head quarters constitute a D.P.C. and thereafter promotions are made by the headquarters and not by the G.M. of the Area. He further states that the concerned workman had been promoted from Grade-C to Grade-B by the Area General Manager after considering the workman of the said Area alone. He has stated that the matter came to the knowledge of the headquarters and thereafter the promotion of the concerned workman was cancelled. WW-2 Rampati Saran is the concerned man. He has stated that in October, 1978 he was appointed as Lab. Technician in Grade-C in new Govindpur hospital and in April, 1982 he was promoted from Grade-C to Grade-B and was paid the salary of Grade-B after his promotion. He has stated that his promotion was withdrawn vide Ext. M-2 and thereafter he was degraded from Technical Grade-B to Technical Grade-C. He has also stated that the management had not given any notice or show cause to him before withdrawing the order of his promotion from Grade-C to Grade-B. WW-1 D. K. Pandey was a Lab. Technician in Grade-D who had joined in 1974. On representation made by him he was given Grade-C two or three months after he had joined in Loyabad Central Hospital. He has stated that he was promoted in Technical Grade-B in January, 1979. Vide Ext. W-3 and that his promotion was made Areawise. He has stated that he had worked for four or five years in Grade-C and then was promoted to Grade-B without any personnel interview or written test. In February, 1987 he was promoted from Grade-B to Grade-A. In his cross-examination he has stated that the D.P.C. was held during his promotion from Grade-B to Grade-A at the headquarters. The evidence of WW-3 Shri S. K. Sharma who is a Vice President of Koyala Ispat Mazdoor Panchayat does not appear to be correct that no circular was issued by JBCCI that the promotion of para-medical staff from Grade-C to Grade-B would be made companywise as his evidence is against the cadre scheme of the para-medical staff Ext. M-1. It appears that WW-1 was promoted in February, 1987 from Grade-B to Grade-A by the D.P.C. as the promotion under the cadre scheme was to be made by the D.P.C. Ext. W-1 is an office order dt. 6-1-79 and Ext. W-2 is an office order dt. 29-7-83. The promotion of Shri D. K. Pandey from Grade-C to Grade-B was made with effect from 1-1-79 which was a promotion prior to the coming into force of the cadre scheme of the para-medical staff and as such the said office order cannot be a guide in aid of the case of the concerned workman. Ext. W-2 shows that the two persons named in it were regularised as Senior Technician in Technical Grade-B and it was not a case of promotion from Grade-C to Grade-B. The very fact that they were regularised in Grade-B shows that they were already working in Grade-B for some time and as such they were regularised. Hence this Ext. W-2 also cannot be taken help in establishing the case of the concerned workman.

On consideration of the above fact it appears that the promotion of the concerned workman from Technical Grade-C to Technical Grade-B was not in accordance with the cadre scheme Ext. M-1 which was in vogue at the time when the concerned workman was promoted. The promotion of the concerned workman from Grade-C to Grade-B by the

Area Manager was illegal in view of the fact that the promotion had to be considered companywise and para medical staff should have experience of five years in Grade-C at the time of his promotion from Grade-C to Grade-B. All these facts show that the promotion of the concerned workman from Grade-C to Grade-B was not in accordance with the provisions of the cadre scheme and as such it cannot be said to be legal.

The main objection which has now been raised on behalf of the workmen is that although the promotion of the concerned workman may not be legal and in accordance with the provisions of the cadre scheme, the concerned workman cannot be demoted from Grade-B to Grade-C without giving him a notice under Section 9A of the I.D. Act. It is stated on behalf of the workmen that the concerned workman had actually been promoted and had worked in Grade-B after promotion from 8-4-82 till 12-10-82 and had received the pay scale of Technical Grade-B. The concerned workman was therefore deprived of his higher wages by the management by demoting him to Grade-C without giving any reason and without giving him any notice as is required under Section 9A of the I.D. Act. Section 9A of the I.D. Act provides that no employer, who proposes to effect any change in the condition of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the 4th schedule shall effect such change (a) without giving to the workmen likely to be effected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected or (b) within 21 days of the giving such notice. A proviso is attached to Section 9A of the I.D. Act which does not apply in the facts of the present case. Schedule 4 of the I.D. Act of which there is reference in Section 9A relates to the condition of service for the change of which notice is to be given. The first clause of the 4th schedule relates to the wages, including the period and mode of payment. The order passed vide Ext. M-2 shows that the promotion of the concerned workman was withdrawn with immediate effect and thereby he was again placed in Grade-C and his salary was reduced to the scale of Grade-C.

Thus it is clear that there was change in the wages of the concerned workman and a notice under Section 9A of the I.D. Act was a must before his promotion was withdrawn and his wages were reduced to the lower scale Grade-C. It will also appear from Ext. M-2 that the order of withdrawal was from immediate effect of the order dt. 30-9-82 and no chance was given to the concerned workman to explain anything in the matter. In view of the above although it appears to me that the promotion of the concerned workman was not in accordance with the cadre scheme, his withdrawal of promotion from Grade-B to Grade-C was also unjustified as no notice under Section 9A of the I.D. Act was given to the concerned workman before passing of the order of withdrawal of the order of promotion and thereby reducing his wages from Grade-B to Grade-C. As the provision of Section 9A of the I.D. Act have not been complied with, the order of the management withdrawing the order of the promotion of the concerned workman vide Ext. M-2 was illegal, more so, when the concerned workman had enjoyed the fruits of the order of his promotion from Grade-C to Grade-B by way of higher wages of Grade-B. The option of giving the notice under Section 9A of the I.D. Act is still available to the management.

In the result, I hold that the action of the management of Govindpur Area No. III of Messrs. Bharat Coking Coal Limited is not justified in demoting Shri Rampati Saran, Laboratory Technician from Grade-B to Grade-C from 13-10-1982. Consequently, the concerned workman is entitled to the difference of wages of Grade-C and Grade-B with effect from the date of his demotion to Grade-C from Grade-B.

This is my Award.

18-8-1987.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. I-20012/19/83-D.III(A)]

P. V. SREEDHARAN, Desk Officer